

**पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय**

16-जनवरी-2015 19:08 IST

**इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट में माननीय प्रधानमंत्री के उद्घाटन संबोधन के मूल पाठ का हिंदी अनुवाद**

आज यहां ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। यह अर्थशास्त्रियों एवं उद्योग जगत की हस्तियों को साथ लाने का अच्छा मंच है। मैं इसके आयोजन के लिए द इकोनॉमिक टाइम्स को धन्यवाद देता हूं।

अगले दो दिनों के दौरान, आप विकास एवं महंगाई, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे, गंवाए जा चुके अवसरों और असीमित संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। आप भारत को अपार संभावनाओं से भरे एक देश के रूप में देखेंगे, जो पूरी दुनिया में अद्वितीय है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके सुझावों पर मेरी सरकार पूरा ध्यान देगी।

मित्रों,

संक्रांति 14 जनवरी, को मनायी गयी। यह एक पावन त्यौहार है। यह उत्तरायण का प्रारंभ है जिसे एक पुण्यकाल माना जाता है। इसके साथ ही लोहड़ी पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य, उत्तर की यात्रा प्रारंभ करता है। यह शीतकाल से बसंत ऋतु की ओर कदम बढ़ाने का भी सूचक है।

नए ज़माने के भारत ने भी अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है (The New Age India has also begun its transition); यह 3 से 4 वर्ष की सुस्त उपलब्धियों के शीतकाल से नये वसंत की ओर की यात्रा है। लगातार दो वर्षों तक 5 फीसदी से भी कम की आर्थिक विकास दर और शासन का कोई भी सटीक तौर-तरीका न होने से देश गहरी निराशा में डूब चुका था। दूरसंचार से लेकर कोयले घोटाले की खुलती परतों ने अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया था। हम, भारत को अवसरों की भूमि बनाने के लक्ष्य से भटक गए थे। अवसरों की कमी के कारण अब हम अधिक समय तक पूंजी और श्रम बल के पलायन का जोखिम नहीं उठा सकते।

जो बर्बादी हो चुकी है अब हमें उसमें सुधार लाना होगा। विकास की रफ्तार बहाल करना एक कठिन चुनौती है। इसके लिए कड़ी मेहनत, सतत प्रतिबद्धता और ठोस प्रशासनिक कदम उठाने की आवश्यकता होगी। हालांकि, हम निराशा पर विजय पा सकते हैं और हमें अवश्य ऐसा करना चाहिए। हमने जो भी कदम उठाए हैं उन्हें निश्चित रूप से इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

मित्रों,

नियति ने मुझे इस महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक हम "हर आंख से आंसू को नहीं पोछ देते" हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए। गरीबी हटाना मेरा बुनियादी लक्ष्य है। समावेशी विकास की मेरी सोच इसी पर टिकी है। इस विजन को नए जमाने के भारत की वास्तविकता में तब्दील करने के लिए हमें अपने आर्थिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट रहना होगा।

सरकार को एक ऐसा इको-सिस्टम अवश्य तैयार करना चाहिए:

- जहां अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास के लिए हो; और आर्थिक विकास, चहुंमुखी प्रगति को बढ़ावा दे;
- जहां विकास, रोजगार का सृजन करता हो; और रोजगार, हुनर पर केन्द्रित हो;
- जहां हुनर का सामंजस्य उत्पादन से हो; और उत्पादन, गुणवत्ता के मानदंड के अनुरूप हो;
- जहां गुणवत्ता, वैश्विक मानदंड पर खरी उतरे; और वैश्विक मानदंडों को पूरा करने से समृद्धि आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समृद्धि सभी के कल्याण के लिए हो।

आर्थिक सुशासन और चहुंमुखी विकास के लिए यही मेरी अवधारणा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत के लोगों की

उन्नति के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करें और नए जमाने के इस भारत का सृजन करें।

मित्रों,

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस नये वसंत में प्रवेश करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। मेरी सरकार, विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तेजी से नीतियों एवं कानूनों की रूप-रेखा तैयार कर रही है। मैं इसी मामले में सभी का सहयोग चाहता हूँ।

पहला, हम बजट में घोषित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने के प्रति कटिबद्ध हैं। हमने इस दिशा में व्यवस्थित ढंग से कार्य किया है।

आपमें से कई अपनी कम्पनियों में कार्बोनेट का अभ्यास करते हैं। बर्बादी कम करने का अर्थ है फालतू खर्च में कटौती और दुरुपयोग को रोकना। इसके लिए आत्म-अनुशासन की जरूरत होती है।

यही वजह है कि फालतू खर्च में कटौती के उपाय सुझाने के लिए हमारे पास व्यय प्रबंधन आयोग है। इस तरह से, हम रुपये को ज्यादा उत्पादक बनाएंगे, और इसका अधिकतम लाभ उठाएंगे।

दूसरा, पेट्रोलियम क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं।

डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। इसने खुदरा पेट्रोलियम के क्षेत्र में निजी कम्पनियों के प्रवेश का रास्ता खोल दिया है।

गैस की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ दिया गया है। इससे निवेश का नया प्रवाह आएगा। इससे आपूर्ति बढ़ेगी। यह कदम महत्वपूर्ण बिजली क्षेत्र को समस्याओं से मुक्त करेगा।

आज भारत में रसोई गैस की सब्सिडी सीधे बैंक खातों में भेजना, दुनिया में सबसे बड़ा नकद हस्तांतरण कार्यक्रम है। आठ करोड़ से भी अधिक परिवार यह सब्सिडी सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर रहे हैं। देश के एक तिहाई परिवार इससे जुड़ गए हैं। इससे हेराफेरी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

इसे ध्यान में रखते हुए अन्य कल्याण योजनाओं में भी सीधे नकद हस्तांतरण शुरू करने की हमारी योजना है।

तीसरा, महंगाई को सख्त कदमों से काबू में किया गया है।

तेल के गिरते हुए मूल्यों ने महंगाई को भी बेहद कम करने में मदद की है। खाद्य पदार्थों की महंगाई एक साल पहले 15 प्रतिशत से भी अधिक थी जो पिछले महीने गिरकर 3.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गई।

इससे भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दरें कम करने और सतत विकास सुनिश्चित करने का अवसर मिला।

चौथा, जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में संशोधन के लिए राज्यों की सहमति प्राप्त करना भी एक बड़ी उपलब्धि है। और हमारे अरुण जी तो कहते हैं कि शायद आजादी के बाद इतना बड़ा Reform का कदम इससे पहले कभी नहीं उठाया गया।

जीएसटी का मसला पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से विचाराधीन है। जीएसटी अकेले ही भारत को निवेश के लिहाज से प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बना सकता है।

पांचवां, गरीबों को वित्तीय प्रणाली में शामिल किया गया है।

महज चार महीनों की छोटी सी अवधि में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 10 करोड़ से भी अधिक नये बैंक खाते खोलने में कामयाबी मिली है। हमारे जैसे विशाल देश के लिए यह बड़ी चुनौती थी लेकिन इच्छाशक्ति, दृढ़संकल्प और प्रत्येक बैंकर के पूर्ण सहयोग की बदौलत आज हम सभी को बैंक खाते की सुविधा देने वाला देश बनने के काफी करीब पहुंच गए हैं। जल्द ही सभी खातों को "आधार" से जोड़ दिया जायेगा। अब पूरे देश में बैंक का उपयोग करने की आदत

आम हो जायेगी। अब इससे भविष्य में व्यापक अवसर पैदा होंगे। लोगों की बचत बढ़ेगी। वे नई वित्तीय योजनाओं में निवेश करेंगे। एक सौ बीस करोड़ लोग पेंशन और बीमे की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे-जैसे देश तरक्की करेगा, इन बैंक खातों के जरिए मांग बढ़ेगी और विकास होगा।

हमने सदा सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता आदि के बारे में ही बहस की है। हमने कभी भी वित्तीय एकता पर विचार-विमर्श नहीं किया। हर व्यक्ति को वित्तीय प्रणाली में शामिल करने के बारे में कभी भी विचार-विमर्श नहीं हुआ। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही सहमत हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में दोनों ले बीच कोई विवाद है। दोस्तों, इससे बड़ा सुधार क्या हो सकता है?

छठा, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार किया गया है।

कोयला ब्लॉक अब नीलामी द्वारा पारदर्शी तरीके से आवंटित किए जा रहे हैं।

खनन को सुविधाजनक बनाने के लिए खनन नियमों में बदलाव किया गया है।

इसी प्रकार के सुधार बिजली क्षेत्र में किए जा रहे हैं। हमने, नेपाल और भूटान में लंबित पड़ी परियोजनाओं को वहां की सरकारों के सहयोग से दुबारा शुरू किया है। नवीकरणीय ऊर्जा सहित सभी संभावित स्रोतों का उपयोग करके सभी को सातों दिन चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गये हैं।

सातवां, भारत को निवेश की दृष्टि से आकर्षक बनाया जा रहा है।

बीमा और रियल एस्टेट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाई गई है।

रक्षा एवं रेलवे में एफडीआई और निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों को तुरंत निपटाने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन किया गया है। इससे बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को मुआवजा भी सुनिश्चित किया जायेगा।

आठवां, बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

रेलवे और सड़कों के निर्माण में व्यापक निवेश की योजना बनाई गई है। इनकी संभावनाओं का अधिक लाभ उठाने के लिए नये दृष्टिकोणों और माध्यमों को अपनाया जा रहा है।

नौवां, विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए शासन में पारदर्शिता एवं दक्षता और संस्थागत सुधार आवश्यक हैं।

व्यापार को सुगम बनाने के लिए नियामक ढांचे को सकारात्मक बनाने और स्थिर कर प्रणाली को तेजी से अपनाया जा रहा है।

उदाहरण के लिए मैंने अभी हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आश्वासन दिया है कि वे ऋण और अपने परिचालन के बारे में सरकार की ओर से बिना किसी हस्तक्षेप के अपने व्यावसायिक निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। और मैंने जब Banks की Meeting में ये कहा कि मैं आपको कहता हूं कि ये Surprise था, मैंने उनसे कहा कि आपको इस काम में कभी PMO से Phone नहीं आएगा और मैं मानता हूं कि इससे बड़ा कोई Confidence level नहीं होगा, और यही है जो Transparency लाते हैं।

हमें सुशासन के लिए तकनीक का उपयोग करने की जरूरत है। चाहे वो बायोमीट्रिक आधारित उपस्थिति दर्ज करने जैसा साधारण मसला ही क्यों न हो, जिसने कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्य संस्कृति में सुधार ला दिया है, या मानचित्र तैयार करने और योजनाएं बनाने में अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी जैसा प्रतिस्पर्धी विषय ही क्यों न हो।

मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से लेकर राशन की दुकानों और उपभोक्ताओं तक की पूरी पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला को कंप्यूटरीकृत किया जायेगा। टेक्नोलॉजी की मदद से कल्याणकारी और प्रभावी खाद्य आपूर्ति उपलब्ध होगी।

भारत में बदलाव के लिए केवल योजना बनाना ही नहीं, बल्कि प्रमुख संस्थागत सुधार भी जरूरी है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया-नीति आयोग की स्थापना इस दिशा में एक कदम है। यह आयोग, देश को सहकारी संघीयवाद की राह पर आगे बढ़ायेगा; और जब मैं कहता हूँ सहकारी संघीयवाद, एक प्रतिस्पर्धात्मक भावना के साथ; देश को प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी संघीयवाद कि आवश्यकता है; राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, राज्यों और केंद्र के बीच प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। नीति आयोग, केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास और भागीदारी बढ़ाने का हमारा मंत्र है।

इस सूची का कोई अंत नहीं है। मैं कई दिनों तक इस पर चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि हमारे पास इतना समय नहीं है।

हालांकि हम जो कार्य कर रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको व्यापक जानकारी दी है। हमने अभी तक अनेक कार्य किए हैं। भविष्य में और अधिक कार्य करेंगे।

मित्रों,

सुधारों का कोई अंत नहीं है। सुधारों के पीछे ठोस उद्देश्य होना चाहिए। यह उद्देश्य लोगों के जीवन में बेहतरी लाने वाला होना चाहिए। इस बारे में भले ही अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही होना चाहिए।

हो सकता है कि पहली बार में सुधार किसी को नजर न आये लेकिन छोटे-छोटे कार्य भी सुधार ला सकते हैं। जो कार्य छोटे लगते हैं, वास्तव में वे बेहद महत्वपूर्ण और मूलभूत हो सकते हैं।

बड़े और छोटे कार्यों को करने के बारे में कोई विरोधाभास नहीं है।

पहला दृष्टिकोण नई नीतियां, कार्यक्रम, बड़ी परियोजनाएं बनाने और उल्लेखनीय परिवर्तन लाने के बारे में है। दूसरा दृष्टिकोण उन छोटी बातों पर ध्यान देना है जो जन आंदोलन शुरू करें और इसे व्यापक गति प्रदान करें जिससे विकास को नई गति मिले। हमें दोनों ही रास्तों पर आगे बढ़ने की जरूरत है।

मैं इसे एक छोटे से उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा। 20,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। यह बेशक महत्वपूर्ण है। अगर मैं कल घोषणा करता हूँ कि हम 20,000 MW बिजली... तो Times of India की Headline पर आ जाता है! शायद !

हालांकि, बिजली बचाने के जन आंदोलन चलाकर भी 20,000 मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है।

इनके अंतिम परिणाम एक जैसे ही हैं। दूसरी उपलब्धि हासिल करना कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन पहली उपलब्धि की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार एक नई यूनिवर्सिटी खोलने के समान ही एक हजार प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाना भी महत्वपूर्ण है।

हम जो नए एम्स स्थापित कर रहे हैं उनसे हमारे वायदों के अनुरूप ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा। मेरे लिए स्वास्थ्य सेवा का आश्वासन कोई स्कीम नहीं है। यह सुनिश्चित करती है कि स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा एक-एक रुपया सही जगह खर्च हो और हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवा सुगम एवं सुलभ हो।

इसी तरह जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, तो इसका व्यापक असर पड़ेगा। यह महज नारा नहीं है। यह लोगों का नजरिया बदलने के लिए है। यह हमारी जीवन शैली बदलता है। स्वच्छता आदत बन जाती है। कूड़े-कचरे के प्रबंधन से आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। यह लाखों स्वच्छता उद्यमी बना सकती है। राष्ट्र को स्वच्छता से पहचान मिलती है। यकीनन, स्वास्थ्य पर इसका व्यापक असर पड़ता है। आखिरकार स्वच्छता से ही डायरिया और अन्य बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है।

सत्याग्रह आजादी का मंत्र था। पूरी आजादी में केंद्र बिंदु रहा था सत्याग्रह और आजादी के योद्धा सत्याग्रही थे। नए जमाने के भारत का मंत्र स्वच्छताग्रह होना चाहिए। सत्याग्रह की तरह स्वच्छताग्रह; और इसके योद्धा स्वच्छताग्रही होंगे; सत्याग्रही की तरह स्वच्छताग्रही।

पर्यटन को ही लीजिए। यह ऐसी आर्थिक गतिविधि है जिसका पूरा उपयोग अब तक नहीं किया गया है। इसके लिए स्वच्छ

भारत की जरूरत है। बुनियादी ढांचे और दूरसंचार संपर्क में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा और कौशल विकास की जरूरत है। इसलिए यह एक साधारण सा लक्ष्य ही कई क्षेत्रों में सुधार ला सकता है।

लोगों को क्लीन गंगा कार्यक्रम को समझना चाहिए। यह भी एक आर्थिक गतिविधि ही है। गंगा के मैदानी इलाकों में हमारी 40 प्रतिशत आबादी रहती है। इस क्षेत्र में एक सौ से अधिक कस्बे और हजारों गांव हैं। गंगा की सफाई से नए बुनियादी ढांचे का विकास होगा, इससे पर्यटन बढ़ेगा, इससे आधुनिक अर्थव्यवस्था बनेगी और लाखों लोगों की मदद होगी। इसके अलावा इससे पर्यावरण का भी संरक्षण होगा।

रेलवे भी ऐसा ही उदाहरण है। देश में हजारों रेलवे स्टेशन हैं जहां हर रोज एक या दो रेलगाड़ियां रुकती हैं। इन सुविधाओं को विकसित करने में पैसा खर्च हुआ है लेकिन बाकी समय इनका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। आसपास के गांव के लिए ये स्टेशन आर्थिक विकास के केंद्र बन सकते हैं। कौशल विकास के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे देश के जो छोटे रेलवे स्टेशन हैं, छोटे छोटे गांवों के, वहां Optical fiber network भी है और Electricity भी है। उससे दो किलोमीटर गांव में बिजली नहीं है, क्या हम इस रेलवे स्टेशन को, क्योंकि इन स्टेशनों पर एक या दो ट्रेन आती हैं, वहीं पर skill development center खड़े करें, उस बिजली का उपयोग करें, Optical fiber network का उपयोग करें और उसी Infrastructure की multiple Utility हो सकती है या नहीं हो सकती?

यह छोटी ही सही, मगर खूबसूरत शुरुआत होगी। और मैं जब छोटा था तब मैं ये किताब पढ़ता था; छोटा पर खूबसूरत।

कृषि में भी हमारा मुख्य लक्ष्य उत्पादकता बढ़ाना है। इसके लिए प्रौद्योगिकी, भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने, और हर बूंद पानी पर ज्यादा फसल.... हर बूंद पानी पर ज्यादा फसल और जब तक हम पानी के महात्म्य को नहीं समझेंगे, मैं समझता हूं पूरे हमारे agriculture sector में सफलता से आगे नहीं बढ़ सकते और नवीनतम तकनीक को प्रयोगशाला से भूमि तक लाना। आज कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किया, वो सब प्रयोगशाला में पड़ा है, जब तक हम Lab to land process पूरा नहीं करते हैं, किसानों को लाभ नहीं होगा। जैसे ही दक्षता बढ़ेगी खेती की लागत घट जाएगी। इससे खेती व्यावहारिक बनेगी।

उत्पादन के मामले में कृषि से जुड़ी समूची मूल्य श्रृंखला को बेहतर भंडारण, परिवहन और खाद्य प्रसंस्करण के जरिए सुधारा जाएगा। हम किसानों को वैश्विक मंडियों से जोड़ेंगे। हम भारत का जायका दुनिया तक पहुंचाएंगे।

मित्रों

मैंने कई बार कहा है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। यह कोई नारा नहीं है। यह भारत के बदलाव का महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

सरकारी तंत्र की दो मूलभूत समस्याएं हैं - वे जटिल भी हैं और शिथिल भी।

जीवन में लोग मोक्ष के लिए चार धाम की यात्रा करते हैं। सरकार में एक फाइल 36 धाम जाती है और उसे फिर भी मोक्ष नहीं मिलता।

हमें इसे बदलने की जरूरत है। हमारे व्यवस्था को पैना, कारगर, तेज तथा लचीला होना चाहिए। इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उनमें नागरिकों का भरोसा बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए नीति निर्देशित राष्ट्र की जरूरत है।

मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट क्या है? इसका मतलब है कि सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है। अर्थव्यवस्था के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां निजी क्षेत्र बेहतर काम करेगा और बेहतर परिणाम देगा। उदारवाद के 20 वर्षों में हमने कमांड और नियंत्रण का नजरिया नहीं बदला है। हम सोचते हैं कि कंपनियों के कामकाज में सरकार का दखल ठीक है। इसे बदलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब अराजकता लाना नहीं है।

पहले, सरकार को उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी राष्ट्र को जरूरत है। दूसरे, सरकार में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता है ताकि राष्ट्र ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे हासिल किया जा सके।

हमें राष्ट्र की जरूरत क्यों पड़ती है ? इसके पांच मुख्य घटक हैं -

- पहला, सार्वजनिक सेवाएं जैसे रक्षा, पुलिस और न्यायपालिका
- दूसरा, बाहरी घटक- जो दूसरों को प्रभावित करते हैं जैसे प्रदूषण। इसके लिए हमें नियामक व्यवस्था की जरूरत है।
- तीसरा, बाजार की शक्ति- जहां एकाधिकार के लिए नियंत्रण की जरूरत होती है।
- चौथा, सूचना में अंतर जहां किसी को यह सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि औषधियां असली हैं इत्यादि।
- पांचवां, हमें यह सुनिश्चित करना है कि कल्याण और सब्सिडी व्यवस्था से समाज का निचला तबका भी वंचित न रहे। इसमें खासतौर से शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल शामिल है।

ये ऐसे पाँच क्षेत्र हैं जहां हमें सरकार की जरूरत होती है।

इन पांच क्षेत्रों में हमें सक्षम, प्रभावी और ईमानदार सरकार की जरूरत होती है। सरकार में हमें निरंतर ये सवाल पूछने चाहिए- मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ और बदले में उससे क्या प्राप्त कर रहा हूँ ? इसके लिए सरकारी एजेंसियों को दक्ष बनाने के लिए सुधार लाना होगा। इसलिए हमें कुछ कानूनों को फिर से बनाने की जरूरत होगी। कानून सरकार का डीएनए है। उन्हें समय-समय पर नया रूप देते रहना चाहिए।

भारत आज दो ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। क्या हम भारत को बीस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना नहीं देख सकते ?

क्या हमें यह सपना साकार करने के लिए माहौल नहीं बनाना चाहिए ? हम इसके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। यह कठिन कार्य है। मैं ये अच्छी तरह से जनता हूँ। अर्थव्यवस्था को तेज विकास के रास्ते पर लाने के लिए तुरंत और आसान सुधार काफी नहीं होंगे। यह हमारी चुनौती है और यही हासिल करना हमारा उद्देश्य है।

डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया इसी दिशा में किए जा रहे प्रयास हैं।

डिजिटल इंडिया सरकारी पद्धतियों में सुधार लाएगा, बर्बादी को दूर करेगा, नागरिकों तक पहुंच बढ़ाएगा और उन्हें सशक्त बनाएगा। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी जो ज्ञान आधारित होगी। हर गांव में ब्रॉडबैंड के साथ व्यापक ऑनलाइन सेवाओं से भारत को इस हद तक बदला जा सकेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

स्किल इंडिया भारत की युवा आबादी की क्षमताओं से लाभ उठाएगा जिसकी आजकल हर कोई चर्चा कर रहा है।

मित्रों

शासन में सुधार लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। जहां अधिनियम, नियम और प्रक्रियाएं जरूरतों के अनुकूल नहीं हैं हम उनमें बदलाव कर रहे हैं। हम कई तरह की मंजूरीयों को कम कर रहे हैं क्योंकि वे निवेश की राह रोकती हैं। हमारी जटिल कर व्यवस्था सुधार की बाट जोह रही है जिसमें सुधार की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। मैं स्पीड में विश्वास करता हूँ। मैं तेजी से बदलाव को बढ़ावा दूंगा। आने वाले समय में आप इसकी सराहना करेंगे।

इसके साथ ही हमें गरीबों, वंचितों और पीछे छूट गए समाज के तबकों पर ध्यान देने की जरूरत है।

मुझे विश्वास है कि उनके लिए सब्सिडी की आवश्यकता है। मैं दोहराता हूँ सब्सिडी की आवश्यकता है। हमें जरूरत है सब्सिडी देने के लक्ष्य पर आधारित व्यवस्था की। हमें सब्सिडी में हेरा-फेरी को रोकने की जरूरत है सब्सिडी को नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सब्सिडी में बर्बादी दूर की जानी चाहिए। लक्षित समूह स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए और सब्सिडी उन तक अच्छी तरह पहुंचनी चाहिए। सब्सिडी का अंतिम लक्ष्य गरीबों को सशक्त बनाना और गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना एवं गरीबी से जंग में उन्हें भागीदार बनाना है। मैं उस रास्ते पर जाना चाहता हूँ जहां गरीब स्वयं भी गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सजग हो, उसके हम वो शस्त्र दें, वो अवसर दें ताकि वो भी गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला हमारा एक मजबूत soldier बन जाए और तभी हम गरीबी से मुक्ति पाएंगे।

इस बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि विकास का परिणाम, रोजगार होना चाहिए। सुधार, आर्थिक वृद्धि, प्रगति - यह सब खोखली बातें हैं यदि इनसे रोजगार पैदा न हों।

हमें न सिर्फ अधिक उत्पादन की, बल्कि जनता के लिए और जनता द्वारा उत्पादन की जरूरत है।

मित्रों

आर्थिक विकास खुद-ब-खुद देश को आगे नहीं ले जा सकता।

विकास के बहुत से आयाम हैं एक तरफ हमें अधिक आय की जरूरत है। तो दूसरी तरफ हमें समावेशी समाज की भी आवश्यकता है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था के दबाव और तनाव को संतुलित रखता है।

इतिहास राष्ट्रों के उत्थान और पतन का गवाह है। आज भी, कई देश आर्थिक मामले में समृद्ध हो चुके हैं लेकिन सामाजिक रूप से गरीब हैं। उनकी पारिवारिक प्रणाली, जीवन मूल्य, सामाजिक तानाबाना और उनके समाज में मौजूद अन्य विशेषताएं छिन्न-भिन्न हो चुकी हैं।

हमें उस पथ पर नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसे समाज और अर्थव्यवस्था की जरूरत है जो एक-दूसरे के पूरक हों। राष्ट्र को आगे ले जाने का सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है।

ऐसा लगता है कि विकास सिर्फ सरकार का एजेंडा बन चुका है। लोगों को लगता है विकास तो सरकारी काम है, सरकार का एजेंडा है, इस मनोस्थिति को हमें बदलना होगा। इसे स्कीम के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।

विकास हर किसी का एजेंडा होना चाहिए। यह जन आंदोलन होना चाहिए।

मित्रों, बाकी दुनिया की तरह, हम भी दो खतरों- आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंतित हैं। हम सब मिलकर इनसे निपटने का रास्ता ढूंढ लेंगे।

आज प्रेरणा और आर्थिक वृद्धि के लिए हर कोई एशिया की तरफ देख रहा है और एशिया में भारत महत्वपूर्ण है। न सिर्फ अपने आकार बल्कि लोकतंत्र और जीवन मूल्यों के लिए। भारत का मुख्य जीवन दर्शन सर्वे मंगल मांगल्यम् और सर्वे भवंतु सुखिनः है। इसमें विश्व कल्याण, विश्व सहयोग और संतुलित जीवन की बात कही गई है।

भारत बाकी दुनिया के लिए आर्थिक वृद्धि और समावेश का आदर्श बन सकता है।

इसके लिए हमें ऐसी श्रम शक्ति और अर्थव्यवस्था की जरूरत है जो वैश्विक जरूरतें और आकांक्षाएं पूरी करती हों।

हमें सामाजिक सूचकों में तेजी से सुधार लाने की जरूरत है। भारत को अब अल्पविकसित देशों की श्रेणी में नहीं रहना चाहिए। और हम ऐसा कर सकते हैं।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था "उठो, जागो और जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता रुको मत"। नए जमाने के भारत का सपना साकार करने के लिए हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए।

हम सब मिलकर ऐसा कर सकते हैं।

बहुत बहुत धन्यवाद।

\*\*\*\*\*

DS/VK/AK-हिंदी इकाई

पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय

11-जनवरी-2015 16:16 IST

वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का गांधीनगर में प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

Let me begin by expressing our solidarity with the people of France as they mourn their loss and come to terms with the brutal terrorist attack. As we see it spread around the world, let us pledge to work together to make sure that it will not succeed against the life that we have all gathered here to build, and the values that we stand for.

Ladies and gentlemen,

On behalf of the people of India and on my personal behalf, I welcome you all to this Summit. In January, 2013, while concluding the sixth Summit, I had extended an invitation for today's event. Your response has been outstanding. I am glad to be here to welcome you.

On this occasion, I express my gratitude to the old partners of this event - both countries and organisations. These include Japan and Canada. Without their support, this event could not have come this far.

I also welcome warmly and thank new partners like USA, UK, Netherlands, Australia, Singapore and South Africa for joining this event. I particularly thank the Secretary General of the United Nations and the President of the World Bank for their presence. It shows their commitment towards progress and prosperity in emerging economies.

Your partnership has enhanced the enterprising spirit of 60 million Gujaratis. It has boosted the morale of 1.2 billion Indians. This event is perhaps the biggest gathering on earth where, a budding entrepreneur has the opportunity to see the President of the World Bank. And where a young farmer, dreaming to set up a food processing unit, can listen to the views of the UN Secretary General on issues like food security. That is why, during one of the previous events, I had called it 'Davos in Action.'

Friends! India has always believed that the whole world is one family - Vasudhaiva Kutumbakam. Few have seen this in practice. I am informed that more than hundred countries are participating in this event.

सौ से अधिक देश एक छत के नीचे आज इकट्ठे हुए हैं।

We are here as a family not only in terms of space, but also because we recognise that

- Someone's dream is dependent on someone's direction;
- Someone's success is related to someone's support;
- Someone's curiosity is linked to someone's care.

This is what a family does. The ultimate objective is welfare of all. हमारे यहां कहा गया है: लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ।



I am sure all of us, from the Secretary General of UN to the President of the World Bank, from leaders of the strongest economies to delegations of small countries, from CEOs of Fortune 500 companies to start-up entrepreneurs, all want the planet earth to become a better place to live.

Thus, our meeting here is not just -

- A meeting of hands but also of hearts;
- It is not only a meeting of ideas, but also of aspirations.

As a host to this family gathering,  
As a curator of thousands of dreams floating here,

I welcome you all once again.

I hope your stay here is, of course, comfortable. वैसे गुजराती लोग मेहमान नवाज़ी में जरा अच्छे रहते हैं। I trust you will enjoy our hospitality. This is the time of Kite Festival in Gujarat. This festival gives us the message of high spirits. Do participate in it.

Friends! After becoming Prime Minister, I have travelled to the remotest parts of India and also to various parts of the world. I have been to the UN, BRICS, ASEAN Summit, G-20 and SAARC summits. Some common worries have been expressed everywhere. The biggest concern is about the global economy. We all have to find ways for its stability and recovery. We also have to work for sustainable and inclusive growth.

We, in India, believe that problems present us with opportunities to become stronger, disciplined and innovative.

My Government is trying to generate confidence. We have prepared a team to secure a robust future. We believe that changes start with a change in mindset.

Friends! It is a matter of great pride that today, there is tremendous interest in India. और मैंने देखा है दुनिया में जहां गया, जिसे मिला, चारों तरफ भारत के प्रति रुचि, भारत के प्रति आकर्षण, भारत के प्रति गौरव का भाव - यह मैं अनुभव कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि यह अपने आप में यह एक हमारी बहुत बड़ी ताकत है। Countries are coming forward to work with us. This has, of course, generated expectations from India.

India's present as well as its rich past is being recognized. I thank the UN Secretary General for giving a formal international stature to Yoga. A record number of 177 countries supported the Indian proposal. Yoga is both a science and an art for improving human life. In today's world, it teaches us to remain stable even in adverse situations. Friends, the 2009 edition of this event created vibrancy when the state of the global economy was depressing. The summits of 2011 and 2013 succeeded in strengthening investor confidence.

It is only because of persistence with positivity that this event of Gujarat Government has become an event for the entire country. This platform has been enlarged so that other states too can take advantage. Today, many other states have adopted this approach. और मैंने पिछले दिनों देखा मध्यदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, सभी राज्य अपने-अपने तरीके से एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए प्रयास कर रहे हैं। The Government of India is committed to support such initiatives by any state government.

Friends! We will have to change the way we have been approaching problems. Recession is often seen just in the context of business and Industry.

Have we ever thought of recession as being the result of low per capita income in countries where a majority of the global population lives?

Have we ever thought of its solution in terms of enhancing the common man's employability, income and purchasing power? This is the biggest task at hand in India. Mahatma Gandhi rightly talked about the last man. वो दरिद्र नारायण की बात करते थे। And Gandhiji's message can show us the way. It is therefore appropriate that this summit is taking place in Mahatma Mandir.

An excellent multimedia exhibition on the life of the Mahatma has been set up in Dandi Kutir. It is hardly a 3 minute walk (from Mahatma Mandir). It portrays the life journey of Gandhiji in brief. In addition, just a few steps away from this venue, there is a world class mega exhibition which showcases products and services by leading companies from India and abroad. और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि कितनी ही व्यवस्तता क्यों न हो, लेकिन इसी कैम्पस में दांडी कुटीर में multimedia technology का उपयोग करते हुए महात्मा गांधी की जो प्रदर्शनी बनाई है आप उसे जरूर देखिए और पास में ही इतना बड़ा exhibition शायद हमारे देश में कभी होता नहीं है। एक प्रकार का unique trade fair है। मैं चाहूंगा कि आप जरूर उसकी मुलाकात ले। I am sure you will not miss the chance to see these magnificent exhibitions.

To me, the best outcome of this event should be inclusiveness and involvement of communities needing care and development.

Thus, this event stands for-

- Inclusiveness of small with big;
- Inclusiveness of poor with rich;
- Inclusiveness of gut feelings with mature thoughts.

I assure this global platform that India wants to work with the global leadership. Be they issues of poverty or ecology, we want to contribute to welfare of the global community. We are aware that with one sixth of the world's population, our activities will have a global impact. We are ready to learn and make this impact positive.

However, India has to be seen from a different angle. It is not just a country of today. It is also an old civilisation. It is not just a country of a few cities. It is a country of thousands of towns and several hundred thousand villages. It is a country of diverse communities. Therefore, India has its own solutions for many pressing problems.

- Our philosophy is a philosophy of conservation;
- Our culture teaches us nurturing of nature;
- Our way of life is that of harnessing.

Such thoughts and practices have existed in India for centuries. Thus, whatever we will do, it will be aligned with our culture, ethos and beliefs. Because, we know, this is what will work in India.

Friends! Our last national elections marked a turning point in Indian democracy. They indicated the high aspirations of our people. This was amply reflected in the record voter participation and a clear verdict in favour of one political party after a gap of 30 years.

My government is committed to changing and improving the economic and social condition of India including the quality of life.

In a short span of seven months, we have been able to change the atmosphere of despair and

uncertainty. Since the first day, my government is actively working to revive the economy. My government is committed to create a policy environment that is predictable, transparent and fair.

Friends! We are on the path of transformation. To start this process, we are making efforts to change the work culture. We have to strengthen our institutions and systems of delivery. To drive this change forcefully, we have recently re-constituted our Planning Commission. Now, it is known as NITI Aayog.

We want to promote co-operative federalism in the country. At the same time, we want a competitive element among the states to create and attract whatever is needed there. I call this new form of federalism: Co-operative and Competitive Federalism.

You may be aware that our economic growth had slowed down during the last few years. Now, my Government is putting an effort to ensure faster and yet inclusive growth. The initial results are encouraging.

On the economic front, during the first two quarters, we registered a growth rate which was one percent higher than the previous year. The IMF has observed that India will be the 2nd fastest growing economy in the coming years.

According to the latest forecast of the OECD, India would be the only country among world's top economies which would increase its pace of growth this year. HSBC's latest report has identified India as the world's largest growing exporter, which is set to move from being the fourteenth to the fifth largest exporter in the world by 2030.

On the political front also, people of various states have supported us in the recent Assembly elections.

This gives us the confidence that we are moving in the right direction. Let me tell you a little about what we are doing and where we want to reach.

Friends! We are not merely making commitments and announcements. We are also backing them up with concrete action at the level of policy and practice. For example, I announced a Financial Inclusion programme. In four months, we have opened more than 100 million bank accounts.

एक प्रकार से सौ दिन में 10 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खोलना सिर्फ घोषणा नहीं है। उसको साकार करने में सफलता पाना और निर्धारित समय में पाना।

We are planning to build smart cities equipped with world-class amenities. For this purpose, we have further liberalized the FDI policy in construction sector.

I announced that a modern rail system including high speed rails will be set up. Immediately, we opened up railways for 100% Foreign Direct Investment. I announced that defence production in the country would be encouraged. The next step was to open the defence sector for Foreign Direct Investment up to 49%. We have taken similar steps in many other areas. These include bringing 49% FDI in insurance. It also includes liberalization of FDI norms for manufacturing of medical devices.

Simultaneously, on the administrative front, we are actively working to provide policy driven governance. और मैं इस बात का बहुत आग्रही रहा हूँ कि राज्य हो, सरकार हो, वो policy-driven होनी चाहिए। Individual के whims पर नहीं चलनी चाहिए। और हमने केंद्र सरकार को भी उस दिशा में बहुत आग्रहपूर्वक बढ़ाने की दिशा में सफलता से कदम उठाए हैं। We have taken far reaching decisions to ensure supply of key natural resources. This includes coal, iron ore and other minerals. We have also amended legal provisions to

facilitate availability of land. This has been done to enable development in remote areas while ensuring better returns to the farming community.

We are trying to complete the circle of economic reforms speedily. We are also keen to see that our policies are predictable. We are clear that our tax regime should be stable. In the last few months, we have taken several decisions in this direction.

We have put focus on building Infrastructure through public and private Investments. This will include national roads, national grids for gas, electricity and water grid. It also includes rural infrastructure, 24x7 electric supply, farm irrigation and cleaning and connecting of rivers.

In order to execute the infrastructure plan, a fast track PPP mechanism is being put in place.

We are undertaking the Sagarmala Project to ensure port-led development. Existing ports are being modernized. New world class ports will be developed along India's coastal circle. Ports will be better connected to the hinterland through road and rail. Inland and coastal waterways will be developed as major transport routes. Low cost airports are being planned to improve regional connectivity, especially to tier-two towns and places of economic and tourist importance.

We are also keen to move towards the next generation infrastructure. Just as we need highways, we need I-ways too. When I say I-ways, (I mean) Information Ways. Under the Digital India Initiative, IT will be used to drive Government processes to improve service delivery and programme implementation, and also to provide broadband connectivity to villages.

To upgrade manufacturing Infrastructure, we are setting up world-class investment and industrial regions along the dedicated freight corridors and industrial corridors. Government of India is working towards single window clearance at the Federal and State levels.

Four months back, we launched "Make In India" initiative to encourage the growth of manufacturing in the country. We are working hard to make India a global manufacturing hub. We are promoting, in particular, labour intensive manufacturing.

क्योंकि मेरे देश में बहुत बड़ी मात्रा में युवा है और रोजगार हमारी प्राथमिकता है और इसलिए हम labour intensive projects को अधिक से अधिक बल देना चाहते हैं।

I have launched these initiatives in a campaign mode so that they force us in the Government to make faster corrections. कभी कभी लोगों को लगता है कि मोदी हर चीज को hype पर क्यों ले जाते हैं, लेकिन यह hype सरकार को भी दौड़ने पर मजबूर करती है। अपने आप को ठीक करने के लिए मजबूर करती है। यह movement अपने आप में खुद को भी परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है।

They challenge us to do away with the red tape and become pro-active. With this purpose, our applications and processes are being aggressively put online.

Ease of doing business in India is a prime concern for you and us. और मुझे याद है कि world bank के chairman पिछली बार जब भारत आए थे उन्होंने एक press statement दिया था। उन्होंने कहा था कि Ease of doing business में अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो आज उसका नंबर 150 के भी पीछे है, वो देखते ही देखते पहले 50 में आ जाएगा। World Bank Chairman ने जो predict किया था मैं विश्वास से कहता हूं कि हमने Ease of business का जो initiative लिया है। एक के बाद एक जो कदम उठा रहे हैं, हमें उस गोल को भी achieve करने में भी शायद देर नहीं लगेगी। I assure you that we are working very seriously on these issues. We want to make them:

- Not only easier than earlier;

- Not only easier than the rest;
- But, we want to make them the easiest.

Friends! Many of you might be interested to know - Why India? आखिरकार क्यों लोग यहां पूंजी लगाएंगे? और यही सवाल का जवाब उनको भारत में निवेश करने के लिए भारत में अपना नसीब अजमाने के लिए एक प्रेरणा भी देता है, ताकत भी देता है और एक नया विश्वास भी देता है - Why India? India has three things to its credit - Democracy, Demography and Demand. This is what you are looking for.

And I am sure, you will not find all of them together at any other destination in the world. India offers you the potential of low cost manufacturing. India has low cost and high quality manpower. 65% of our population is below 35 years of age. We are trying to further harness these strengths through better management and good governance and skill development mission.

In the recently launched Mars Orbiter Mission, everything was made indigenously. In fact, most mission components were made in very small factories.

और हमने जो मंगलयान पर सफलता प्राप्त की है, उसका जो खर्चा हुआ है। हॉलीवुड की मूवी से भी कम खर्च में हम मंगल पर पहुंचे हैं और पहले प्रयास में पहुंचे। इतना ही नहीं अहमदाबाद में ऑटो रिक्शा में अगर आप जाएं और एक किलोमीटर जीना है तो कम से कम 10 रुपया किराया लगता होगा। हम मंगल तक पहुंचे हैं सिर्फ सात किलोमीटर तक के खर्च से।

Friends! We have large number of hands to work. And, we have even larger number of dreams to be realised. Therefore, employment opportunities are being enhanced by promoting manufacturing, agro-based industries, tourism as well as services. We have undertaken labour reforms to encourage enterprise and to create a bigger job market for our youth.

I have always said that development process should benefit the common man as well as the business sector.

Therefore, my Government has established a new Ministry for Skill Development to enhance our human resource potential. For this, we are placing equal emphasis on knowledge, technology, innovation and research and development. This includes the use of ICT for improving governance and resource management. I understand this because I use modern tools of communication myself. And people are very familiar with my social media activities.

Friends! Today, India is a land of opportunities. We have to build fast track roads and railways. We have to energise homes and factories on a continuous basis. We have to build infrastructure for cities where almost half of our population lives. We have to take the taste of modern amenities to our rural areas, to every village. We have to propel our growth through value addition in our natural resources and agri-produce. We have to provide services to our people which are of global standards. At the same time, the whole world is looking for certain services. If our human resources can be equipped with skills and technology, we may serve the world in many areas.

Thus, there are immense possibilities for global investors in India. The process of development we are taking up is not incremental. We are planning to take a quantum leap. It is not limited to one sector or region, it is truly unlimited. And we want to do things in a cleaner and greener way. We are open to ideas, investments and innovations:

Friends!

- We have made commitments to our people

- We have made commitments to ourselves
- We have made commitments for India's great future
- We have to write our new destiny
- And we have to write it in a very short time

We know that to do this, we need an enabling policy framework. We are working constantly to improve it further.

However, I can say with confidence that even today, the strength of Indian democracy and independence of our judicial system provide a level playing field for long lasting business.

I would conclude by saying that-

- We are dreaming big;
- And our dreams are numerous;
- Our dreams can become the seeds of your growth;
- Our aspirations can propel your ambitions.

Friends! On behalf of the Government, let me give an assurance. We assure you that we will be available to hold your hands whenever you need us. You will find us standing with you in your journey. If you walk one step; we will walk two steps for you.

At the end, I urge you to see and realise for yourself that -

- India is changing fast;
- India is growing fast;
- India is moving faster than expected;
- India is learning even faster;
- India is ready than ever before.

Let us join hands! Let us work together for progress, prosperity and peace.

मुझे विश्वास है कि गुजरात का यह प्रयास.. मैं गुजरात सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि अब तक जितने Vibrant Summits हुए हैं उससे ज्यादा ताकतवर, ज्यादा ऊंचाई वाला, और न सिर्फ गुजरात को, पूरे देश को एक नया विश्वास जगाने वाला, महात्मा मंदिर की धरती पर हुआ यह समागम देश की युवा पीढ़ी को नया विश्वास देगा, देश को विकास की नई ऊंचाईयों पर पहुंचने के लिए एक रास्ता दिखाएगा और इस बात के लिए मैं गुजरात की जनता का, गुजरात सरकार का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सब भारत के विकास में शरीक होने के लिए यहां पधारे हैं। दुनिया के 100 देशों से अधिक देशों के लोग पधारे हैं। मैं उन सबका स्वागत करते हुए आपको निमंत्रण देता हूँ - आओ, हम साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।

Thank you.

\*\*\*

महिमा वशिष्ट / तारा, सोनिका

**पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय**

02-जनवरी-2015 10:42 IST

**ICICI के 'डिजिटल ग्राम' के राष्ट्र को समर्पण समारोह के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गये भाषण का मूल पाठ**

उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं,

किसी संस्था के जीवन में 60 साल की यात्रा बहुत बड़ी नहीं होती है। 60 साल का कार्यकाल भारत जैसे विशाल देश में किसी Institution को build up करने में, उसे लोगों तक पहुंचाने में ये समय बहुत कम पड़ता है। व्यक्ति के लिए जीवन में 60 साल बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन संस्था के जीवन में एक प्रकार से उसका प्रारंभ होता है। मैं मानता हूं कि अब ICICI Group उस स्थिति में पहुंच रहा है जिसकी बदौलत, जिन आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर उसका जन्म हुआ, जिन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उसने यात्रा की, उसको Achieve करने का अब उसके सामने समय आया है और तब उसको 60 साल की जो गति है वो काम नहीं आती है। 60 साल का जो canvass है, वो भी छोटा पड़ता है। उसे बड़े canvass पर लंबी दौड़ के साथ अपनी योजनाएं करनी होती हैं। लेकिन, 60 साल का ये अनुभव भारत की विकास यात्रा में, banking Sector के योगदान में एक बहुमूल्य भूमिका निभाने का, उसकी सफलता का आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक ताकतवर बनाने में बहुत-बहुत उपयोगी होगा। मेरी आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं।

कभी-कभी मुझे लगता है कि इस ग्रुप के नाम पर ICICI में समझता हूं 60 साल हो गए, आई को बहुत देखा, अब ICU होना चाहिए। मैं आपको देख रहा हूँ, हिंदुस्तान के गरीब को देख रहा हूँ और उस रूप में मैं आशा करता हूँ कि जब 60 साल मनाए जा रहे हैं, क्यों न group के प्रमुख लोग बैठें। Grass root level के बैंक के साथ जुड़े हुए सभी लोग बैठें और हम जब 75 साल के होंगे, तब तक क्या क्या achieve करेंगे, हमारा social charter क्या होगा? और एक देश के सामने उस रूप में बैंकिंग क्षेत्र में ICICI lead कर सकता है क्या? for fifteen years, next fifteen years 75 celebrate करने से पहले हम ये social charter ले करके आ रहे हैं। 10 हों, 12 हों, इन चीजों को हम देश में ला करके रहेंगे।

कभी कभार एक आध Institution lead करती है तो बाकी सब उसको follow करते हैं और अपने आप में एक momentum बन जाता है और उस दिशा में हम काम कर सकते हैं। 2022 में भारत की आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं और 25 में, 30 में आपके 75 साल होंगे। उस अर्थ में बीच में आपको एक अवसर मिलता है कि भारत के 75 साल के समय का क्या goal हो और Next आपके 75 होंगे तब क्या हो। एक social charter के साथ देश के सामने, financial Sector किस प्रकार से नई दिशा दे सकता है, इसके सपनों को ले करके आप आएंगे। मैं समझता हूँ कि देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। देश को एक नई दिशा मिलेगी।

मैं चंदा जी का विशेष रूप से इसलिए भी अभिनंदन करता हूँ कि इस काम को मैं बड़े आग्रह से करना चाहता हूँ। स्वच्छ भारत! उन्होंने उस बीड़े को उठाया, स्वयं ने भी इस काम को किया। लेकिन साथ-साथ उन्होंने अपनी सभी Branches को सप्ताह में एक दिन सफाई का कुछ-न-कुछ करने के लिए प्रेरित किया है। एक momentum खड़ा हुआ है। उनके इन प्रयासों का मैं अभिनंदन करता हूँ और सभी ग्रुप को, सभी Branches को, उन Branches में बैठे हुए सभी बैंक के कर्मचारियों को इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।

लेकिन बैंक सेक्टर से मेरी एक और अपेक्षा है। क्या हम इस काम को तो आगे बढ़ाएं, ज़रूर बढ़ाएं। लेकिन हम हमारे finance के जो areas हैं, उसमें एक नए क्षेत्र का इज़ाफा कर सकते हैं क्या और उसको प्राथमिकता दे सकते हैं क्या? क्या हमारा group एक साल के भीतर- भीतर bank finance की मदद से नौजवानों को प्रेरित करके कम से कम एक लाख स्वच्छता के entrepreneur तैयार कर सकते हैं? Waste management एक बहुत बड़ा Business है। solid waste management के क्षेत्र में नौजवान आएं, बहुत बड़ा Business है, Waste water treatment के Business में आएं, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम इस प्रकार के नए entrepreneur तैयार कर सकते हैं। हमारी young generation को, उसकी training करना, उसको model करना और financial व्यवस्था देना।

मैं समझता हूँ कि जो काम स्वच्छता के अभियान में आपकी बैंक कर रही है, लेकिन वो स्वच्छता के entrepreneur तैयार करती है तो शायद एक sustainable व्यवस्था, एक लंबे समय तक काम आने वाली व्यवस्था को हम उभार सकते हैं और हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप infrastructure में पैसे देते होंगे, आप पावर प्रोजेक्ट में देते होंगे आप और development में देते होंगे, बहुत बहुत बड़े कारोबार आपके चलते होंगे। यहां जिस प्रकार का audience है, उसको लगता है कि बड़े काम आपके चलते होंगे। इस audience को भी देख कर मैं तय कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक और क्षेत्र में ले जाने के लिए कह रहा हूँ, छोटे छोटे लोग जो entrepreneur के रूप में इस field में आए, उनको प्रेरित करें। एक बहुत बड़ा काम होगा।

उसी प्रकार से यहां पर video conference से हमारे साबरकांठा को एक छोटे से गांव के लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। मजा में बैदा बिदा! इस गांव की एक और भी विशेषता है। देश का पहला गांव ऐसा है जहां पर cattle hostel है। हमारे यहां गांवों में पशु अपने घर के बाहर ही बांध कर रखते हैं और सारी गंदगी वहीं होती है और बीमारी की जड़ भी वहीं होती है। आजकल लड़कियों को गांव में शादी करने में एतराज नहीं है, लेकिन ये पशु वाला काम करना पड़ता है तो उसके लिए उसकी तैयारी कम है। तो हमें एक नई समाज रचना करनी पड़ेगी और उसी विचार में से एक प्रयोग यहां शुरू हुआ है। गांव के सारे cattle hostel में रहते हैं और मालिक लोग hostel में जाते हैं, अपने पशु की देखभाल करते हैं। दूध लेने के समय, दूध के समय पहुँच जाते हैं। पूरा गांव साफ-सुथरा रहता है। एक hostel का प्रयोग आने वाले दिनों में देशभर में ये होने वाला है। अगर हम हमारे प्रिय से प्रिय बच्चों को hostel में रख सकते हैं तो हमारे cattle के लिए hostel क्यों नहीं बना सकते! और उसके कारण उनकी देखभाल भी अच्छी होती है। जब मैं वहां था, मुझे तब तो मालूम है, उनकी income में 20 percent बढ़ोतरी हुई थी, केवल hostel के कारण, क्योंकि वो उसमें से fertilizer निकालने लगे, गैस बनाने लगे, बिजली पैदा करने लगे, कई चीजें उनकी हुई, दूध में बढ़ोतरी हुई, अब उसी गांव को बैंक ने Digital Village बनाने के लिए और उसको बहुत सारा काम पूरा कर दिया है।

अब गांव भी बहुत इंतजार करने वाला नहीं है, उसके expectations भी वही हैं जो शहर में बैठे समृद्ध वर्ग के हैं और ये समय की मांग है कि हम उस पर Focus करें। Rural Development भी भारत की GDP को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर है। नए तरीके से उसकी संभावनाएं बढ़ी हैं, उसके Infrastructure पर बल दे दिया है, Agri-structure पर बल दिया जाए, Agri-structure valuation पर बल दिया जाए। बहुत बड़ी संभावनाएं हमारे Rural life में आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा Power Station एक नया हम खड़ा कर सकते हैं, ये संभावनाएं बढ़ी हैं। ये Digital Village की कल्पना आने वाले दिनों में, जो Digital India का सपना हम पूरा करना चाहते हैं, उसमें ये भी चीजें एक Model के रूप में हमारे सामने आएंगी और काम आएंगी। मैं इस Initiative के लिए भी आपको बधाई देता हूँ।

अकोद्रा गांव के लोग तो अब Cashless उनका कारोबार चले लेकिन हम ये सपना कब पूरा करेंगे कि भारत में भी Cashless आर्थिक व्यवस्था विकसित हो और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के बैंकिंग सेक्टर में इसकी Competition होनी चाहिए। कौन बैंक है जिसका Maximum Transaction है और Cashless है। कालेधन के उपायों में एक महत्वपूर्ण उपाय ये है, Cashless Transaction एक बहुत बड़ा उसका कारण और हमें इसको Promote करना चाहिए, लोगों का आदत डालनी चाहिए और बैंक के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूँ वो ये है, एशिया के ये वो भू-भाग है। भारत के उसके आस-पड़ोस के देश Including China विश्व में ये एक ऐसा भू-भाग है जहां परंपरागत रूप से Saving का स्वभाव है। सदियों से परंपरा है हर पीढ़ी के मां-बाप आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ-कुछ बचाना ये सोच रखते हैं। दुनिया के और हिस्से हैं कि जहां पर Credit Card की दुनिया है, जहां पर बच्चों के हिस्से में Credit Card आता है और कुछ नहीं आता है। यहां वो सोच नहीं है, यहां पर Saving की सोच है लेकिन काल क्रम स्थिति ये बन गई कि उसका स्वभाव तो बन गया है कि भई बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जाना। Security के लिए कुछ व्यवस्था रखनी चाहिए लेकिन वो उसके लिए Gold की तरफ चला गया है। उसको लगता है कि सोना खरीदकर रख लो भाई, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। शायद सौ में से एक इंसान भी नहीं निकलता होगा कि जिसको अचानक सोना बेचकर के कहीं जाना पड़ा हो, सौ में से एक भी नहीं निकलता है लेकिन Psychological Effect है कि भई सोना होगा तो आधी रात काम आएगा। बैंकिंग सेक्टर के सामने Challenge है वो Credibility हर इंसान के दिमाग में हम पैदा कर सकते हैं कि जिसको कभी उसकी इच्छा न हो कि अब सोने खरीदने की इच्छा न हो, गांव में अब बैंक की ब्रांच है, एटीएम है, मुझे कभी अब पैसों के लिए संकट नहीं होगा, सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं अब मुझे सोना खरीदकर के कोने में रखकर के जरूरत नहीं है। भारत की Economy में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बहुत बड़ा वर्ग है जो आवश्यकता से अधिक होड़ रखता है उसका मूल कारण उसके दिमाग में Safety, Security और Future होता है। अगर बैंक के द्वारा उसे Assurance मिलता है, उसमें विश्वास पैदा होता है कि हां भई इसके साथ अब मेरा नाता जुड़ गया यानि अब मेरे जीवन के संकट के काल में भी ये मेरा साथी है। मैं समझता हूँ कि ये एक Gold Hub का Alternative बनने के लिए एक Golden Opportunity मैं देख रहा हूँ।



क्या हम 75 साल मनाएं तब इन चीजों को Achieve करने की दिशा में कुछ कर सकता हूँ क्या। आप देख सकते हैं कि एक बैंक Social Transformation का Agent बन सकता है। सिर्फ बैंकिंग सेवाएं नहीं.... Social Transformation का Agent बन सकता है। हम उस दिशा में नए तरीके से हमारे Banking Sector सोचें। मुझे विश्वास है कि हम बहुत कुछ देश को दे सकते हैं।

मैं फिर एक बार आज इस अवसर पर इस 60 साल की यात्रा में जिन-जिन्होंने योगदान दिया है, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं क्योंकि एक कालखंड में सब होता नहीं है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये परिणाम मिलता है इसलिए इस Group के सभी उन वरिष्ठजनों को हृदय से बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

\*\*\*\*\*

अमित कुमार/ रजनी

**पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय**

28-फरवरी-2015 17:08 IST

**आम बजट 2015 पर दूरदर्शन समाचार को दी गयी प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का मूल पाठ**

Pro-Poor Budget है, Pro-Growth Budget है। जन-जन की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, जन-धन से लेकर के जन-कल्याण तक का, पूरा मार्ग प्रशस्त किया गया है।

एक तरफ राज्यों को सक्षम बनाना; दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को बल देना। SC, ST, OBC, दलित, पीडित, शोषित - जो पीछे रह गए हैं - उनको विशेष बल देना।

जिस MGNREGA की बड़ी चर्चा होती थी, इतने सालों में MGNREGA में पहली बार, गांव के गरीब को रोजी-रोटी मिले, इसलिए सर्वाधिक धनराशि, गरीबों के रोजगार के लिए लगाई गई है।

हमारे देश के छोटे-छोटे व्यापारी - रेकड़ी चलाते होंगे, सब्जी बेचते होंगे, कपड़े की फेरी करते होंगे - उनको धन प्राप्त करने के लिए - बैंक हाथ ऊपर कर देती है - उनको पैसा मिलता नहीं है। उनके लिए, धन-राशि सरलता से मिले, जितनी चाहिए उतनी मिले, उसके लिए "मुद्रा" की एक अलग योजना हमने प्रस्तुत की है, जो आने वाले दिनों में उनको काम आने वाली है।

इस बजट में, काले धन के संबंध में हमारी क्या सोच है, हमारा क्या commitment है, इसको पूरी तरह हमने देश के सामने रखा है। अब काले धन वालों की खैर नहीं है। सिवाए जेल, अब उनके नसीब में कुछ नहीं है। नया कानून हम ला रहे हैं, और आज बहुत विस्तार से काले धन के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई करने की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। साथ-साथ अब काला धन नया तैयार न हो। उसके लिए भी, बेनामी transaction का जो कारोबार चलता है, उसके खिलाफ भी कानून ला रहे हैं।

बजट निवेश बढ़ाने वाला भी होना चाहिए। हमारी आर्थिक क्षमताओं को मजबूत बनाने वाला होना चाहिए। इस बजट की सारी योजनाएं, निवेश को बढ़ावा देने वाली हैं, Infrastructure को आगे बढ़ाने वाली है और सामान्य मानव के सपनों को पूरा करने वाली है, और मैं कह सकता हूं, सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर जुटाने वाला, यह बजट है।

इस बजट में, सामान्य मानव के लिए इतनी सारी योजनाएं लगाई हैं। चाहे वो आकस्मिक बीमा की बात हो, जीवन बीमा की बात हो, पेंशन की बात हो, हमारे नौजवानों को पढ़ने के लिए कॉलेज में जो खर्च होता है, उसके लिए बैंक में easily loan की व्यवस्था हो। एक के बाद एक सुचारु रूप से व्यवस्थाएं विकसित की हैं।

और सबसे बड़ी बात, खासकर के मेरे किसान भाई-बहन, खासकर के मेरे गरीब भाई-बहन, जिनको अपने बुढ़ापे की चिंता है, हिंदुस्तान के हर गरीब से गरीब को भी, किसान को भी, खेत-मजदूर को भी, बुढ़ापे में जब काम करने की स्थिति न रहे, उसको पेंशन मिले, ऐसी योजना हमने रखी है। पहली बार इस देश में हर नागरिक, पेंशन के अंदर कोई न कोई लाभ लेगा। ऐसा एक बहुत बड़ा भगीरथ काम इस बजट के माध्यम से हम करने जा रहे हैं।

‘सबका साथ सबका विकास’ इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।

मैं, मेरे मित्र और साथी, वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी को गरीबों के लिए, growth के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, सामान्य से सामान्य मानव को नये उमंग और उत्साह के साथ नई चीजें करने के लिए प्रेरित करने वाला बजट देने के लिए, बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

मुझे विश्वास है यह बजट आने वाले दिनों में हमें, और नई ऊंचाईयों पर ले जाने का एक अवसर प्रदान करेगा।

\*\*\*\*

AK/TARA

पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय

13-मार्च-2015 21:06 IST

सिलोन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा कोलम्बो, श्रीलंका में आयोजित व्यापारिक बैठक में प्रधानमंत्री का वक्तव्य

भारत और श्रीलंका के व्यापार प्रतिनिधियों,  
विशिष्ट अतिथियो !

सिलोन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में आने पर मुझे अत्यन्त खुशी हुई है।  
बड़ी संख्या में आप सबकी मौजूदगी के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।  
यह श्रीलंका की यात्रा का वास्तविक गौरव है।

इन दो दिनों में मैं जीवन के सभी क्षेत्रों से सम्बद्ध लोगों से मिलूंगा।

मेरे लिए यह बैठक श्रीलंका की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है।

ऐसा इसलिए है कि संबंध चाहे कितने ही प्राचीन और प्रगाढ़ क्यों न हों, आर्थिक सहयोग अक्सर उन्हें गति प्रदान करने वाले इंजन का काम करता है।

यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे इस क्षेत्र में हम सभी के लिए सबसे जरूरी लक्ष्य लोगों के जीवन में बदलाव लाना है।

हमारा मार्ग हमारे आर्थिक लक्ष्यों और शासन की गुणवत्ता से निर्धारित होगा। परन्तु, व्यापारिक उपक्रम हमारी सफलता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होंगे।

मैं अक्सर यह कहा करता हूँ कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके पड़ोस पर निर्भर करता है। भारत में अनेक लोग यह कहते हैं कि भारत इतना बड़ा है कि वह अपने पड़ोसी देशों की मदद करने में असमर्थ है। इस क्षेत्र में अनेक लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें भारत की अर्थव्यवस्था के आकार से स्वयं को क्षति पहुंचने की आशंका है।

मैं इन दोनों तरह के विचारों से असहमत हूँ।

मेरे विचार में हमें स्थिर और शांतिपूर्ण पड़ोस की आवश्यकता है ताकि हम राष्ट्रीय विकास पर ध्यान केन्द्रित कर सकें।

मेरा यह भी मानना है कि जब समूचा क्षेत्र एक साथ आगे बढ़ता है तो किसी राष्ट्र की तरक्की भी बेहतर ढंग से होती है। मैंने सार्क की बैठक में कहा था कि सीमाओं की अड़चने हमारी प्रगति को रोकती हैं; अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी उसे गति देती है। यही वजह है कि आज विश्वभर में क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग की लहर चल रही है।

हमारा क्षेत्र संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। हमारे पास एक विस्तृत बाजार है। हम परस्पर पूरक हैं। अतः हमारा सहयोग हम सबके लिए भारी लाभदायक हो सकता है। दक्षिण एशिया में जीवंत उदाहरण पहले से मौजूद हैं, जिनसे पता चलता है कि आकार में अंतर का कोई विपरीत प्रभाव भागीदार के लाभों पर नहीं पड़ता है।

भूटान पनबिजली भारत को निर्यात करके लाभान्वित होता है। नेपाल भारत को महत्वपूर्ण विनिर्मित वस्तुएं निर्यात करता है, जो भारतीय निवेशकों की भागीदारी से तैयार की गई होती हैं। बुनियादी ढांचा, आपूर्ति श्रृंखलाएं, परम्परागत हस्तशिल्प, आधुनिक विनिर्माण, पर्यटन और सेवाएं- हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।

यहां मौजूद जानकारी श्रोताओं को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में पिछले 10 महीनों में कितने बदलाव हुए हैं। हमारी नीतियों में स्पष्टता आयी है, हमने समावेशी विकास की नयी धारा अपनायी है, शासन में नए मानदंड अपनाए जा रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में नयी जान आयी है। पिछली तिमाही में भारत की अर्थ-व्यवस्था विश्व की सर्वाधिक तीव्र विकास वाली अर्थ-व्यवस्था रही है। हमें विश्वास है कि हम और तेजी से विकास करेंगे।

मानवता के छोटे हिस्से की प्रगति से दुनियाभर के लिए प्रमुख आर्थिक अवसर पैदा हुए हैं।

भारत में वैश्विक विश्वास बहाल हुआ है। भारत के साथ दुनिया की सम्बद्धता एक नए स्तर पर पहुंच गई है। परन्तु, भारत पर पहला अधिकार उसके पड़ोसी देशों का है। मुझे खुशी होगी यदि भारत अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास का उत्प्रेरक बनेगा। इसलिए मैं ऐसे पास-पड़ोस की बात करता हूँ जिसमें व्यापार, निवेश, ज्ञान और लोगों का सीमा पार आवागमन बेहतर हो।

और, जैसा कि मैंने नवम्बर में काठमांडू, नेपाल में कहा था, कि भारत इस क्षेत्र के लिए अपना योगदान अवश्य करेगा। हम अपने बाजारों को अधिक एकीकृत करने के लिए काम करेंगे। हम सर्वाधिक सीधे मार्गों से व्यापार को सुचारू और संभव बनाएंगे। हम क्षेत्रीय संचार व्यवस्था में निवेश करेंगे। और, हम चिकित्सा से लेकर आपदा प्रबंधन या अंतरिक्ष विज्ञान तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अपनी क्षमताओं को दक्षिण एशिया के साथ साझा करेंगे।

एक मित्र और पड़ोसी के नाते हम श्रीलंका की आर्थिक प्रगति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं।

श्रीलंका अनेक उपलब्धियों और व्यापक क्षमताओं वाला राष्ट्र है। यह शिक्षा, कौशल और उद्यम की दृष्टि से सम्पन्न है। इसकी भौगोलिक स्थिति उत्कृष्ट है। और, अब यहां शांति भी स्थापित हो चुकी है। श्रीलंका के व्यापारियों ने यह दर्शाया है कि वे विश्व के उत्कृष्ट व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हमारा वस्त्र और चाय उद्योग यह बात अच्छी तरह से समझता है।

हम श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और सबसे बड़ा निवेश स्रोत बनना चाहते हैं। वर्ष 2000 में हमने जो मुक्त व्यापार समझौता किया था, वह इस क्षेत्र में एक अग्रणी उपाय था। इससे हमारे व्यापार को व्यापक बढ़ावा मिला है। उसके बाद से भारत को श्रीलंका के निर्यात में 16 गुणा वृद्धि हुई है। किसी भी मानक से देखें, यह अत्यन्त प्रभावशाली है।

मैं जानता हूँ कि व्यापार के क्षेत्र में भारी संतुलन को लेकर यहां कुछ चिंताएँ हैं। मैं इन चिंताओं को दूर करने में आपके साथ मिल कर काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि व्यापार में संतुलित बढ़ोतरी हो। मेरी कोशिश होगी कि आपके लिए भारतीय बाजारों में प्रवेश करना आसान और सुविधाजनक हो। ऐसा करना मेरी उस सोच का हिस्सा है कि भारत में व्यापार करना आसान होना चाहिए। सीमा शुल्क में सहयोग के लिए किया गया समझौता इस दिशा में एक कदम है। भारत विश्व के लिए खुल रहा है। हम दक्षिण एशिया सहित अल्पविकसित राष्ट्रों को शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति देते हैं। और, भारत ने आसियान तथा अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस परिवर्तनशील और प्रतिस्पर्धात्मक विश्व में श्रीलंका किसी से पीछे न रहे। यही वजह है कि भारत और श्रीलंका को व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको भारत को निर्यात करने के लिए भारत से निवेश को भी आकर्षित करना चाहिए। ऐसा करना हमारी निकटता और आपकी क्षमताओं का सहज नतीजा होना चाहिए।

भारतीय निवेश से आपके यहां बुनियादी ढांचे का उन्नयन और विस्तार भी किया जा सकता है। यह भी स्वाभाविक है कि समानताओं और निकटता के कारण भारतीय निवेशकों द्वारा अधिक निवेश किए जाने की संभावना है। वे यहां मौजूद हैं। और मैं जानता हूँ कि अनेक बड़ी प्रतिबद्धताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उनके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। इस यात्रा के दौरान मुझे समपुर ताप बिजली परियोजना और ट्रिन्कोमाली ऑयल फार्म की प्रगति संतोषजनक दिखायी दी है। यह श्रीलंका की प्रगति और हमारी भागीदारी के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समुद्री अर्थव्यवस्था का स्थायी विकास सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र हो सकता है

मेरा यह भी मानना है कि हम जब हम लोगों की जिंदगी को परस्पर जोड़ते हैं, तो हम राष्ट्रों के बीच संबंधों को और सुदृढ़ बनाते हैं। हमने 14 अप्रैल से श्रीलंका के लोगों को आगमन पर वीजा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। हमें हवाई और समुद्र मार्ग से दोनों देशों के बीच संचार बढ़ाने की दिशा में और उपाय करने चाहिए। भारत और श्रीलंका कुछ मायनों में वर्तमान की तुलना में अतीत में एक-दूसरे के साथ बेहतर ढंग से जुड़े हुए थे। कोलम्बो में रहने वाला कोई व्यक्ति रेल टिकट खरीद कर रेल और नौका, दोनों से सफर करते हुए चेन्नई पहुंच सकता था। कोलम्बो और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान प्रारंभ करने का एयर इंडिया का निर्णय उसी स्थिति को बहाल करने में मदद पहुंचायेगा।

पर्यटन लोगों को जोड़ता है और आर्थिक अवसर प्रदान करता है। भारत के पर्यटकों के लिए श्रीलंका पहले से सबसे बड़ा स्रोत है। हम इस प्रवाह को बढ़ाने के लिए मिल कर काम करेंगे।

अंत में, मैं उसी बिन्दु पर लौटता हूँ, जो बात मैंने प्रारंभ में की थी। भारत की प्रगति हमें अपने पड़ोसियों के लिए अवसर पैदा करने की क्षमता प्रदान करती है। विकास में हमारी भागीदारी से श्रीलंका के लिए भारत की ओर से 1.6 अरब डॉलर की सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त हुई है। इससे श्रीलंका में बुनियादी सुविधाओं के पुनर्निर्माण और उन्नयन में मदद मिली है। आज हमने रेलवे क्षेत्र के लिए करीब 31.8 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधाएं प्रस्तावित की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका के सेन्ट्रल बैंक के लिए 1.5 अरब डॉलर की मुद्रा विनिमय व्यवस्था प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे श्रीलंका के रुपये की सस्थिरता बढ़ेगी।

यह केवल विकास में भागीदारी तक सीमित नहीं है। हम आपके वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने में भी सहयोग करेंगे। मुझे श्रीलंका की क्षमताओं पर भरोसा है। हमें अधिक सहयोग करना चाहिए। हमें एक-दूसरे के प्रति सहयोग के अधिक क्षेत्र खोलने की आवश्यकता है।

हमें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखते हुए; एक-दूसरे पर अधिक विश्वास करते हुए; और अपनी भागीदारी के परिणामों के प्रति आश्वस्त होकर आगे बढ़ना चाहिए।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि श्रीलंका में हमारा महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार बनने की क्षमता है। ऐसी भागीदारी कायम करने के लिए हम आपके सहयोग पर निर्भर हैं। आप सब का धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं। आभार।

वि कासोटिया/डीके/एम/-1304



**पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय**

23-अप्रैल-2015 11:41 IST

**सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी के उदघाटन समारोह में प्रधानमंत्री के वक्तव्य का मूल पाठ**

मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे सभी साथी,

मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव,

दुनिया के भिन्न-भिन्न देशों से आये हुए प्रतिनिधि बंधु,

मैं Department के सभी साथियों को बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम की रचना करने के लिए क्योंकि बहुत वर्षों से हम एक बात सुनते आये हैं और उसका हमारे मन पर प्रभाव भी बहुत रहा है। हर जगह पर हम सुनते थे एक शब्द, Brain Drain. और आलोचना भी होती रहती थी कि ये देश का क्या होगा Brain Drain का, ऐसी आलोचना होती थी। और आज से 15-20 साल पहले शायद यहां बैठे हुए लोगों ने बहुत सारी चिंता व्यक्त की होगी। वो एक Mind Set था हमारा, लेकिन आज Brain Drain से Brain Gain तक की यात्रा है यह हमारी यात्रा आई है। अब Brain Drain से बाहर निकल करके, उस सोच से बाहर निकल करके, Brain Gain के लिए हमारी क्या Strategy होनी चाहिए उसको हमने सोचना चाहिए।

और इसलिए कोशिश यह है कि अब वो... हम लोगों ने चिंता करने की जरूरत नहीं है पांच 50 लोग दुनिया में पहुंचेंगे तो यहां खाली हो जाएगा। यह बहुरत्ना वसुंधरा है, कोई कमी पड़ने वाली नहीं है, Talented Manpower की कभी कमी नहीं पड़ने वाली है। दूसरी बात है, भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का लेखा-जोखा लेना चाहिए। और वो भी global prospective में लेना चाहिए। और आज अगर global prospective में देखें तो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है भारत का human resource, हमारा Manpower. यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, तो हमारे विकास की यात्रा के केंद्र बिंदु में इस विचार को प्राथमिकता देनी चाहिए कि जिस देश के पास 65 percent population 35 से नीचे हो, और आने वाले दिनों में यह एवरेज और कम होने वाली है। भारत आने वाले दिनों में अधिक युवा होने वाला है। अगर यह हमारी संपत्ति है तो संपत्ति को ध्यान में रख करके, हमारी विकास यात्रा की Model को हमने तैयार करना चाहिए।

और अगर उसको तैयार करना है तो हमने Globally भी देखना चाहिए कि नहीं दुनिया की क्या स्थिति है। कितना ही Development किया होगा, Technology की नई-नई ऊंचाईयों को पार किया होगा, उसके बाद भी विश्व का बहुत एक हिस्सा ऐसा होगा, आने वाले दिनों में - जो Manpower के बिना एक प्रकार से Handicap हो सकता है। अभी जैसे त्रेहान जी बता रहे थे कि अगर हम Sport System खड़ी न करें तो दुनिया के कई देशों का Health Sector ही Collapse कर जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों के पास ये सामर्थ्य है। अब इसको Scientific ढंग से हम आगे कैसे बढ़ाएं?

भारत में व्यक्तिगत संबंधों के कारण कोई Middle east में चले गये होंगे, वहां कोई मजदूरी शुरू की होगी। कोई पांच लोग पहले गये होंगे, कोई 50 को ले गये होंगे। फिर एक जिले के ज्यादा लोग उसी देश में चले जाते होंगे वो परंपरा चली होगी। लेकिन इस बात को institutionalized करके इस सेक्टर में काम करने वाले सब लोगों का सहयोग ले करके, सरकार के सभी Department को भी coordinate करते हुए एक Road map बना करके उसमें सबका Involvement कैसे हो, हमारा destination क्या हो, हमारी way and means क्या हो, इन सारे विषयों में जब तक हम वैज्ञानिक तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे एक Perfect Mechanism खड़ा नहीं करेंगे, तो इतनी बड़ी संपदा होने के बावजूद भी उधर लोग workforce के लिए तरसते होंगे और इधर हम काम न देने के कारण तक परेशान रहते होंगे। और इसलिए समय रहते हम global requirement को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य योजना को करना चाहिए। उसी दिशा का यह महत्वपूर्ण एक प्रयास है कि जिसमें दुनिया के देश के लोगों से मिले, बैठे बात करें। सार्क देशों ने उसे विशेष रूप से उसमें योगदान दिया है। अब मिल बैठकर हम किसकी क्या आवश्यकता है, उसको सोचे, समझें और उसकी दिशा में हमारा जाने का प्रयास है।

एक तो हमें एक काम की प्रयास करना है - और मैं चाहूंगा उसमें राज्य सरकारें हो सकती हैं, Private कंपनियां, फिल्म में काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, भारत सरकार भी हो सकती है - सब मिल करके काम करें। हिंदुस्तान में भी हमारे



पास, जो भी workforce है उसमें भी अलग-अलग इलाके की, अलग-अलग ताकत है। अलग-अलग विशेषताएं हैं। जो काम कर्नाटक की तरफ नौजवान कर सकता होगा, संभव है कि असम का नौजवान उस प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जो काम असम का नौजवान कर पाएगा वो शायद कर्नाटक का नहीं कर पाएगा। तो भारत इतना विशाल है हमारे यहां जो मानव संपदा है उसकी शक्तियों में भी अनेक विविधताएं भरी पड़ी हुई हैं।

हमारा काम होगा कि हम इस प्रकार की शक्तियों का Mapping करें। अब देखा होगा हमने Sports - हमें मालूम है कि कुछ ही इलाके से Sportsmen मिलते हैं हमें, सब जगह से नहीं मिलते। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह खेल नहीं चल रहा है, स्कूल में तो खेल हर कोई खेलता है तो एक-एक भू-भाग विशेषता बनी होती है। आप देखें होंगे Mathematics में अच्छे Student कुछ ही इलाके होंगे जहां पर Best quality Mathematics Student मिलते होंगे, तो एक Traditional develop हुई होगी। हमने, हमारे पास जो ये मानव संपदा है उस मानव संपदा का किस भू-भाग में किस प्रकार का का स्वभाव है, जरूरी नहीं है एक प्रकार का होगा, अनेक प्रकार का होगा, उसमें Priority हम तय करेंगे, फिर फोकस वही करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि हर प्रकार की Talent हर प्रकार के Scale हिंदुस्तान के हर कोने में develop हो - आवश्यक नहीं है। मान लीजिए हमने एक State को दो Skill के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना और उसी को Center for Excellence खड़ा किया। और हिंदुस्तान भर में जिसको उसमें रुचि हो उसको वहां ले गये और वहां जो लोग तैयार हों, उनको दुनिया में जहां जरूरी है Export किया, तो आप देखिए हम कितना Qualitative अपने काम को हम Improve कर सकते हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण काम है हमारा अपना Mapping.

दूसरा महत्वपूर्ण काम है Human Resource Development. जब तक हम हमारे Manpower को तैयार नहीं करते... मान लीजिए हमारे यहाँ एक Carpenter है, इस Carpenter को U.A.E में काम मिल रहा है। अगर कोई एक यहां छोटी सी भी Institute हो, Private हो, जैसे कोचिंग क्लासेस चलते हों। अगर कहीं पर एक कोचिंग क्लासेस चलाता है, Private अपना, कि वो 25-25 ऐसे युवकों को जिस देश में जाने वाला है वहां की Manner क्या होती है, खान-पान क्या होता है, वहां के 50 ऐसे वाक्य याद कर ले तो क्या अर्थ होता है। अगर आपने इसको इस प्रकार से भी Soft Skill Develop किया तो उसके बाद जो real strength है उसके प्लस Soft Skill हो गई तो उसका value addition कितना हो जाएगा? मान लीजिए आप उसको भेज रहे हैं लेकिन वो देश Technological Advance है, तो हमारी पुरानी पद्धति में उसको जो भी आता है.. हो सकता है, वो वहां मकान बनाने के लिए गया लेकिन Deign मिलेगी, ईमेल से आएगी Deign तो उसको फिर Computer Reading आता है या नहीं आता है, वो Deign को समझ सके.. उसको Value Addition कैसे हो? अगर हम उसकी दिशा में हम अगर थोड़ा भी करें...

आज दुनिया में हमारी नर्सिंग की मांग है। हमारी नर्सिंग रूटीन में हमारे यहां जो पढ़ाई होती है, वहां से जाती है पढ़ाई करती हैं, और बड़ी प्रतिष्ठा पाई हैं। लेकिन क्या हम भी रिसर्च कर सकते हैं कि और अधिक Value Addition क्या हो सकता है? और और कौन सी चीजें जोड़ी जा सकती हैं? उस दिशा हम प्रयास करें। मान लीजिए हम तय करें कि भाई इस प्रकार से जाने वालों के लिए हम Language class चलाएंगे। इन language class की हमें Double benefit हो सकते हैं। हिंदुस्तान में हमें अगर Tourism बढ़ाना है और हमारे पास इस प्रकार के language classes हैं, तो कुछ लोग विदेश जाएंगे, लेकिन जो यहां रहेंगे वो language जानते होंगे तो Tourist के समय जब जरूरत पड़ेगी तो हमें वो काम आएगा। एक प्रकार से वो अनेक क्षेत्रों में काम आ सकता है।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम within India हमारी जो ताकत है, उसको वैज्ञानिक तरीके से नापना, नाप करके उसको और अधिक Develop करना, यह एक आवश्यक काम मुझे लगता है।

दूसरा Globally भी हमने Target करना चाहिए। भारत को एक लाभ है - अंग्रेजी language का। लेकिन हमने पूरे दुनिया का हिसाब-किताब लगाया। एक उन देशों में कुछ चीजें अनिवार्य हैं, और ये उनके बस की ताकत नहीं है। किस देश में वो कौन सी चीजें हैं? और अगर हम उसको Target करके उनकी अनिवार्यता, उनकी मुसीबत जो है उसको अगर identify करते हैं और फिर हमारे यहां काम करते हैं, Immediate आपको मार्केट मिल सकता है। तुरंत उनको Requirement होगी अगर मान लीजिए कोई जगह पर पता है कि वहां Health Sector में उनके यहां Develop ही संभव नहीं है, आने वाले 25 साल तक संभव नहीं है, Ok, हम उस देश में Health Sector के लिए ही Focus करेंगे। देखिए एक दम से आपको काम मिलना शुरू हो जाता है।

इसलिए दुनिया के किस देश में अनिवार्यता है? और वहां पर सबसे ज्यादा deficiency हो, उस area में हम हमारे देश में तैयारी करके enter कर सकते हैं क्या? उनका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा।

दूसरा part है कि वहां establish चीजें हैं लेकिन cost is a problem, work force is a problem. तो फिर हमारा काम

रहता है कि हम उसको address करें और उसको address करने के लिए हम किस प्रकार की तैयारी करें? हम जितनी ज्यादा मात्रा में हमारे man power को value addition करके यहां से भेजेंगे और targeted काम के लिए भेजेंगे, हम बहुत बड़ा contribution global economy में भी कर सकते हैं। और of course भारत के नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो भारत की economy को तो लाभ होना ही होना है और उसका फायदा होगा।

कई क्षेत्र ऐसे हैं। जैसे हम कहें tourism. अब tourism कहने के मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ tourist destination होता है। Tourism कहने के बाद उसके पीछे अनेक चीजें हैं। Even food habits का होगा, soft skill का होगा, language का होगा, guide का होगा, even आपके cab के drivers होंगे तो उनकी training होंगी, पचासों चीजें होंगी। हमें अपना tourism बढ़ाना है तो हमारे देश में भी, हमारी service को कैसे हम qualitatively improve करें? Qualitatively improve करने के लिए कौन-कौन से हमारे पहलू हो? तो, हमारे यहां अपने देश की आवश्यकता के लिए भी उस प्रकार की नई पचासों institutions विकसित हो सकती हैं और ये public private partnership के model पर हो सकती हैं और करनी भी चाहिए। हम उसमें बहुत बड़ी मात्रा में role कर सकते हैं।

अभी मैं जर्मनी गया था। तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के साथ ऐसे ही बात हो रही थी, लंच के समय पर जब हम मिले तो और guest अभी set हो रहे थे, meeting शुरू होना बाकी था। उन्होंने बातों ही बातों में, जब उनको पता चला कि मैं vegetarian हूं तो उन्होंने विषय निकाला। उन्होंने कहा कि मैं खुद Indian कढ़ी बनाती हूं, बोले मैं सीखी हूं। लेकिन फिर भी मुझे अभी perfect नहीं आती है। और कभी-कभी ingredient के संबंध में मुझे problem रहता है। ये जब मैंने सुना, तो तुरंत मुझे मेरे देश के service sector की तरफ ध्यान गया। इसका मतलब कि दुनिया में आजकल holistic health care की तरफ जब योगा ने एक ध्यान लिया है वैसे ही एक हवा चल पड़ी है vegetarianism की। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि vegetarianism में भी इतना development हो चुका है। क्या हम इस दिशा में service देने का तय करें। हमारे जितने यहां बड़े-बड़े होटल वाले हैं, वे अगर दुनिया के लोगों को इस प्रकार से सिखाने का काम करें, special classes करें, even tourist के लिए भी package बनाएं। 3 दिन cooking class, 3 दिन field visit. आप देखिए service के कितने पहलू हो सकते हैं, कितने प्रकार से उसको पढ़ाया जा सकता है, हमने कितने नए innovative हैं क्योंकि हमारे पास विपुल मात्रा में मानव संपदा है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम उन सेवाओं को दें ताकि हमारी अपनी product भी साथ-साथ चलती जाए। कभी-कभार ऐसा होता है कि भई आप ये लेंगे तो साथ में ये मिलेगा, तो साथ में ये भी जोड़ा जा सकता है। इसलिए हम सिर्फ IT के द्वारा सेवा करें, ये जो limited हमारी सोच बनी है, उसमें से हमने बाहर आना चाहिए, इसका दायरा बढ़ाना चाहिए। और सिर्फ बहुत ऊंचे पढ़े-लिखे लोग दुनिया को जरूरत, ऐसा नहीं है, अनेक प्रकार के लोगों की दुनिया को जरूरत है और ये आवश्यकता बढ़ने वाली है। और इसलिए हमने हमारे सेवा के layers, multiple layers सेवा के हमने दायरे पर सोचना होगा। वो अगर हम करते हैं तो बहुत लाभ पाएंगे, देश की सेवा करेंगे, दुनिया की भी सेवा करेंगे।

कुछ तो हम लोगों ने पुराने जमाने में जो नियम बनाए हैं, उस भय से बनाए हुए हैं - कहीं दुनिया आ जाएगी, खा जाएगी। आत्मविश्वास का अभाव रहा क्योंकि बहुत सालों तक हम गुलाम रहे। हमें उस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि arbitration हमारे देश में क्यों न हो? Global arbitration हमारे देश में क्यों न हो? Arbitration के लिए आज भी हमें London क्यों जाना पड़े? क्या हमारे पास उस प्रकार के chartered accountant, उस प्रकार के lawyer नहीं है क्या? हैं! लेकिन हमने कानून ऐसे बना के रखे हैं कि हमारा ही.. हां और कुछ लोगों को डर लगता है, नहीं-नहीं ये यहां मत शुरू करो, ये सब दुनिया भर के बड़े-बड़े बुद्धिमान वकील आ जाएंगे, तो हमारा काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है ये।

जो सोच किसे जमाने में थी कि technology आएगी तो job चली जाएगी, computer आएगा तो job चली जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि technology के कारण job का global scope पैदा हो गया है। वक्त बदल चुका है। हमने स्थितियों को visualise करना चाहिए और हमें भयभीत रहने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा, सवा सौ करोड़ का देश है। हम दुनिया से दबकर क्यों जीना चाहिए? हम अपनी ताकत खड़ी करें, दुनिया में हम अपना अस्तित्व दिखा सकते हैं, इस मिजाज से हमारी योजना और रचनाएं होनी चाहिए।

उसी प्रकार से finance का sector, हम देख रहे हैं अब via मॉरिशस आइए, via सिंगापुर आइए, हमें डर लगता है कहीं अपने यहां कर लिया तो? क्यों न करें हम? ये हम अपनी ताकत को मॉरिशस, सिंगापुर या मलेशिया को क्यों divert करें? हम अपने कानूनों और नियमों को इस प्रकार से बनाएं ताकि इन चीजों को हम भी हजम कर सकें और अपनी व्यवस्थाओं को विकसित कर सकें। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में देखेंगे आप, हम उन व्यवस्थाओं को विकसित करना चाहते हैं कि जो globally भारत को.. हां कुछ हमने उसकी सीमाएं भी बांधनी पड़ती हैं। जैसे intellectual property right, अब हम global parameter के intellectual property right की दिशा में काम नहीं करेंगे तो दुनिया

हमारे साथ नाता नहीं जोड़ेगी।

हम जानते हैं हमारी entertainment industry बहुत बड़ी ताकत रखती है। सिर्फ हिंदुस्तान में फिल्म बनाने की ताकत रखती है, ऐसा नहीं है। लेकिन intellectual property right में उनको भरोसा दुनिया को हम दे दें, मुझे विश्वास है हम globally एक बहुत बड़ा destination बन सकते हैं, उनके अपने creative work के लिए। भारत में creative work के लिए इतनी बड़ी संभावनाएं पड़ी हैं - दुनिया में कोई कार बनाए, कार की manufacturing वाला होगा वहां लेकिन कार में अंदर की seat की design क्या हो? वो बनाने की ताकत हिंदुस्तानी में है। और वो ही कार ज्यादा तब बिकेगी, इसलिए नहीं कि तुम्हारा मशीन कैसा है, सीट कैसी है, इसके आधार पर कार बिकती है कि भई बैठना कितना comfortable है, उतरना कितना comfortable है और उस काम को करने वाले भी लोग होते हैं। Service! Creative services! इसके लिए हमारे पास इतनी संभावनाएं हैं और हम उसका लाभ उठा सकते हैं।

आज योगा और IT - दो क्षेत्र ऐसे हैं, जिन्होंने दुनिया में हिंदुस्तान को भी पहुंचाया है और इसके माध्यम से हिंदुस्तान भी पहुंचा है। लेकिन एक विशेषता है, ये दोनों पहुंचे हैं क्योंकि वहां सरकार नहीं है... बड़ी देर लगी आपको, ये इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम नहीं हैं वहां। क्योंकि सरकार का mind set ऐसा बना हुआ है वहां, सालों से, ये हिंदुस्तान के 20, 22, 24 साल के नौजवान हैं, जिन्होंने दुनिया में भारत के IT माध्यम से पहचान खड़ी की है, ताकत के रूप में पहचान बना दी है। उसी प्रकार से दुनिया का मानव जो कि stress के कारण परेशान है, frustration से जी रहा है, बहुत कुछ पाने के बाद भी संतोष अनुभव नहीं कर रहा है तो वो दूढ़ता-दूढ़ता आया, वो योग उठाकर ले गया। कोई आकर के ले गया, कोई जाकर के दे आया, ये दो route से हमारा हुआ है।

हम इसको और अधिक scientific बनाकर के एक बहुत ही, यानी भारत की अपनी सोच के रूप में, हम ऐसे किन-किन क्षेत्रों में.. मान लीजिए संगीत, दुनिया को, दुनिया को, मैं मानता हूं संगीत के माध्यम से हम बहुत कुछ दे सकते हैं। दुनिया को अभी तक ये भी पता नहीं है कि तन डोले इसलिए संगीत होता है कि मन डोले इसके लिए संगीत होना चाहिए। ज्यादातर परिचय यही है कि संगीत यानी तन डोले, संगीत से मन डोलना चाहिए और ये ताकत हिंदुस्तान में है! ये ताकत हिंदुस्तान में है! ये देश है कि किस प्रहर में कौन सा राग हो, किस बीमारी में कौन सा राग हो, बालक अवस्था हो तो कौन सा राग हो, निवृत्त अवस्था हो तो कौन सा राग हो। यहां तक जहां वैज्ञानिक काम हुआ हो, क्या दुनिया को हम ये सेवा नहीं दे सकते हैं? फिर से एक बार गुरु-शिष्य परंपरा revive हो और मान लीजिए हिंदुस्तान में एक हजार अच्छे सितारवादक हैं। और दुनिया के एक हजार शिष्य उनके यहां आ जाएं, उनके यहां रहें, सितार सीखें, साल भर का अपना गुरु-दक्षिणा दें और वापिस चले जाएं। क्या भारत का, संगीत की दुनिया में जिसने साधना की है, उसको कभी भूखे रहने की नौबत आएगी क्या? कभी नहीं आएगी और जो यहां से सीखकर गया, वो सिर्फ सितार ही सीखकर जाएगा कि पूरा हिंदुस्तान लेकर के जाएगा? हिंदुस्तान अपने आप पहुंच जाएगा कि नहीं जाएगा?

हमारी service sector की ताकत ये है कि विश्व में हमें अपने आप को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने आया है। सिर्फ विश्व की सेवा करेंगे, ऐसा नहीं, विश्व को अपना बनाने की ताकत हमने पाई है.. और समय-समय पर इस देश ने किया है। मैं अभी फ्रांस गया था। फ्रांस में मैं युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी हुई। सेवा कैसी हमारे लोग कर सकते हैं, इसका एक उत्तम उदाहरण है। एक सौ साल हो गए हैं, प्रथम विश्व युद्ध में करीब 14 लाख हिंदुस्तान के जवानों ने किसी और के लिए लड़ाई लड़ी थी, अपने लिए नहीं, हमारी जमीन को बढ़ाने के लिए नहीं, हम मर रहे थे इसलिए बचने के लिए नहीं, किसी और के लिए। और करीब-करीब 75 हजार लोगों ने शहादत दी। मैं मानता हूं कि दुनिया समझे किसी भी प्रकार की सेवा यानी अपना जीवन आहुत कर देने तक की सेवा देना, इस देश ने करके दिखाया है। अगर उसने किसी की रक्षा के लिए अपनी जान देकर के दिखाया है तो जीवन बचाने के लिए हमारे डॉक्टरों ने दुनिया में जाकर के अपने करतब दिखाए हैं।

और इसलिए मैं कहता हूं कि हम इस क्षेत्र को सीमित न मानें। ये बहुत बड़ी मानवता की सेवा है। ये बहुत बड़ी देश की सेवा है। उसको हमारी ताकत को जल्दी पहचाने, हम अपनी ताकत को दूढ़े, उसको हम globally requirement के अनुसार value addition करें, दुनिया की requirement का हम mapping करें, और हम कर सकते हैं। 2025 में किस देश की किसकी जरूरत पड़ेगी, ये हम कर सकते हैं। आज इतनी सारी चीजें हो सकती हैं और उस प्रकार से हम तैयारी करें।

मुझे विश्वास है सेवा के क्षेत्र में हम इन कामों को करेंगे तो जरूर ही भारत अपनी एक जगह बना सकता है। सरकार में जो नियमों को बदलना होगा, उसको भी बदलते हुए इन कामों को करना चाहिए। मैं फिर एक बार.. सबने मिलकर के इस बात को आगे बढ़ाया है और भी इसको बल दिया जाए। सरकार में भी इस बदले हुए brain drain के जमाने को छोड़कर के brain gain की दिशा में हम अपनी योजनाएं को केंद्रित करें। इस अपेक्षा के साथ बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

धन्यवाद।

\*\*\*

महिमा वशिष्ट / रजनी, सोनिका, मुस्तकीम खान

**पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय**

23-अप्रैल-2015 11:41 IST

**सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी के उदघाटन समारोह में प्रधानमंत्री के वक्तव्य का मूल पाठ**

मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे सभी साथी,

मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव,

दुनिया के भिन्न-भिन्न देशों से आये हुए प्रतिनिधि बंधु,

मैं Department के सभी साथियों को बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम की रचना करने के लिए क्योंकि बहुत वर्षों से हम एक बात सुनते आये हैं और उसका हमारे मन पर प्रभाव भी बहुत रहा है। हर जगह पर हम सुनते थे एक शब्द, Brain Drain. और आलोचना भी होती रहती थी कि ये देश का क्या होगा Brain Drain का, ऐसी आलोचना होती थी। और आज से 15-20 साल पहले शायद यहां बैठे हुए लोगों ने बहुत सारी चिंता व्यक्त की होगी। वो एक Mind Set था हमारा, लेकिन आज Brain Drain से Brain Gain तक की यात्रा है यह हमारी यात्रा आई है। अब Brain Drain से बाहर निकल करके, उस सोच से बाहर निकल करके, Brain Gain के लिए हमारी क्या Strategy होनी चाहिए उसको हमने सोचना चाहिए।

और इसलिए कोशिश यह है कि अब वो... हम लोगों ने चिंता करने की जरूरत नहीं है पांच 50 लोग दुनिया में पहुंचेंगे तो यहां खाली हो जाएगा। यह बहुरत्ना वसुंधरा है, कोई कमी पड़ने वाली नहीं है, Talented Manpower की कभी कमी नहीं पड़ने वाली है। दूसरी बात है, भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का लेखा-जोखा लेना चाहिए। और वो भी global prospective में लेना चाहिए। और आज अगर global prospective में देखें तो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है भारत का human resource, हमारा Manpower. यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, तो हमारे विकास की यात्रा के केंद्र बिंदु में इस विचार को प्राथमिकता देनी चाहिए कि जिस देश के पास 65 percent population 35 से नीचे हो, और आने वाले दिनों में यह एवरेज और कम होने वाली है। भारत आने वाले दिनों में अधिक युवा होने वाला है। अगर यह हमारी संपत्ति है तो संपत्ति को ध्यान में रख करके, हमारी विकास यात्रा की Model को हमने तैयार करना चाहिए।

और अगर उसको तैयार करना है तो हमने Globally भी देखना चाहिए कि नहीं दुनिया की क्या स्थिति है। कितना ही Development किया होगा, Technology की नई-नई ऊंचाईयों को पार किया होगा, उसके बाद भी विश्व का बहुत एक हिस्सा ऐसा होगा, आने वाले दिनों में - जो Manpower के बिना एक प्रकार से Handicap हो सकता है। अभी जैसे त्रेहान जी बता रहे थे कि अगर हम Sport System खड़ी न करें तो दुनिया के कई देशों का Health Sector ही Collapse कर जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों के पास ये सामर्थ्य है। अब इसको Scientific ढंग से हम आगे कैसे बढ़ाएं?

भारत में व्यक्तिगत संबंधों के कारण कोई Middle east में चले गये होंगे, वहां कोई मजदूरी शुरू की होगी। कोई पांच लोग पहले गये होंगे, कोई 50 को ले गये होंगे। फिर एक जिले के ज्यादा लोग उसी देश में चले जाते होंगे वो परंपरा चली होगी। लेकिन इस बात को institutionalized करके इस सेक्टर में काम करने वाले सब लोगों का सहयोग ले करके, सरकार के सभी Department को भी coordinate करते हुए एक Road map बना करके उसमें सबका Involvement कैसे हो, हमारा destination क्या हो, हमारी way and means क्या हो, इन सारे विषयों में जब तक हम वैज्ञानिक तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे एक Perfect Mechanism खड़ा नहीं करेंगे, तो इतनी बड़ी संपदा होने के बावजूद भी उधर लोग workforce के लिए तरसते होंगे और इधर हम काम न देने के कारण तक परेशान रहते होंगे। और इसलिए समय रहते हम global requirement को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य योजना को करना चाहिए। उसी दिशा का यह महत्वपूर्ण एक प्रयास है कि जिसमें दुनिया के देश के लोगों से मिले, बैठे बात करें। सार्क देशों ने उसे विशेष रूप से उसमें योगदान दिया है। अब मिल बैठकर हम किसकी क्या आवश्यकता है, उसको सोचे, समझें और उसकी दिशा में हमारा जाने का प्रयास है।

एक तो हमें एक काम की प्रयास करना है - और मैं चाहूंगा उसमें राज्य सरकारें हो सकती हैं, Private कंपनियां, फिल्म में काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, भारत सरकार भी हो सकती है - सब मिल करके काम करें। हिंदुस्तान में भी हमारे

पास, जो भी workforce है उसमें भी अलग-अलग इलाके की, अलग-अलग ताकत है। अलग-अलग विशेषताएं हैं। जो काम कर्नाटक की तरफ नौजवान कर सकता होगा, संभव है कि असम का नौजवान उस प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जो काम असम का नौजवान कर पाएगा वो शायद कर्नाटक का नहीं कर पाएगा। तो भारत इतना विशाल है हमारे यहां जो मानव संपदा है उसकी शक्तियों में भी अनेक विविधताएं भरी पड़ी हुई हैं।

हमारा काम होगा कि हम इस प्रकार की शक्तियों का Mapping करें। अब देखा होगा हमने Sports - हमें मालूम है कि कुछ ही इलाके से Sportsmen मिलते हैं हमें, सब जगह से नहीं मिलते। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह खेल नहीं चल रहा है, स्कूल में तो खेल हर कोई खेलता है तो एक-एक भू-भाग विशेषता बनी होती है। आप देखें होंगे Mathematics में अच्छे Student कुछ ही इलाके होंगे जहां पर Best quality Mathematics Student मिलते होंगे, तो एक Traditional develop हुई होगी। हमने, हमारे पास जो ये मानव संपदा है उस मानव संपदा का किस भू-भाग में किस प्रकार का का स्वभाव है, जरूरी नहीं है एक प्रकार का होगा, अनेक प्रकार का होगा, उसमें Priority हम तय करेंगे, फिर फोकस वही करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि हर प्रकार की Talent हर प्रकार के Scale हिंदुस्तान के हर कोने में develop हो - आवश्यक नहीं है। मान लीजिए हमने एक State को दो Skill के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना और उसी को Center for Excellence खड़ा किया। और हिंदुस्तान भर में जिसको उसमें रुचि हो उसको वहां ले गये और वहां जो लोग तैयार हों, उनको दुनिया में जहां जरूरी है Export किया, तो आप देखिए हम कितना Qualitative अपने काम को हम Improve कर सकते हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण काम है हमारा अपना Mapping.

दूसरा महत्वपूर्ण काम है Human Resource Development. जब तक हम हमारे Manpower को तैयार नहीं करते... मान लीजिए हमारे यहाँ एक Carpenter है, इस Carpenter को U.A.E में काम मिल रहा है। अगर कोई एक यहां छोटी सी भी Institute हो, Private हो, जैसे कोचिंग क्लासेस चलते हों। अगर कहीं पर एक कोचिंग क्लासेस चलाता है, Private अपना, कि वो 25-25 ऐसे युवकों को जिस देश में जाने वाला है वहां की Manner क्या होती है, खान-पान क्या होता है, वहां के 50 ऐसे वाक्य याद कर ले तो क्या अर्थ होता है। अगर आपने इसको इस प्रकार से भी Soft Skill Develop किया तो उसके बाद जो real strength है उसके प्लस Soft Skill हो गई तो उसका value addition कितना हो जाएगा? मान लीजिए आप उसको भेज रहे हैं लेकिन वो देश Technological Advance है, तो हमारी पुरानी पद्धति में उसको जो भी आता है.. हो सकता है, वो वहां मकान बनाने के लिए गया लेकिन Deign मिलेगी, ईमेल से आएगी Deign तो उसको फिर Computer Reading आता है या नहीं आता है, वो Deign को समझ सके.. उसको Value Addition कैसे हो? अगर हम उसकी दिशा में हम अगर थोड़ा भी करें...

आज दुनिया में हमारी नर्सिंग की मांग है। हमारी नर्सिंग रूटीन में हमारे यहां जो पढ़ाई होती है, वहां से जाती है पढ़ाई करती हैं, और बड़ी प्रतिष्ठा पाई हैं। लेकिन क्या हम भी रिसर्च कर सकते हैं कि और अधिक Value Addition क्या हो सकता है? और कौन सी चीजें जोड़ी जा सकती हैं? उस दिशा हम प्रयास करें। मान लीजिए हम तय करें कि भाई इस प्रकार से जाने वालों के लिए हम Language class चलाएंगे। इन language class की हमें Double benefit हो सकते हैं। हिंदुस्तान में हमें अगर Tourism बढ़ाना है और हमारे पास इस प्रकार के language classes हैं, तो कुछ लोग विदेश जाएंगे, लेकिन जो यहां रहेंगे वो language जानते होंगे तो Tourist के समय जब जरूरत पड़ेगी तो हमें वो काम आएगा। एक प्रकार से वो अनेक क्षेत्रों में काम आ सकता है।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम within India हमारी जो ताकत है, उसको वैज्ञानिक तरीके से नापना, नाप करके उसको और अधिक Develop करना, यह एक आवश्यक काम मुझे लगता है।

दूसरा Globally भी हमने Target करना चाहिए। भारत को एक लाभ है - अंग्रेजी language का। लेकिन हमने पूरे दुनिया का हिसाब-किताब लगाया। एक उन देशों में कुछ चीजें अनिवार्य हैं, और ये उनके बस की ताकत नहीं है। किस देश में वो कौन सी चीजें हैं? और अगर हम उसको Target करके उनकी अनिवार्यता, उनकी मुसीबत जो है उसको अगर identify करते हैं और फिर हमारे यहां काम करते हैं, Immediate आपको मार्केट मिल सकता है। तुरंत उनको Requirement होगी अगर मान लीजिए कोई जगह पर पता है कि वहां Health Sector में उनके यहां Develop ही संभव नहीं है, आने वाले 25 साल तक संभव नहीं है, Ok, हम उस देश में Health Sector के लिए ही Focus करेंगे। देखिए एक दम से आपको काम मिलना शुरू हो जाता है।

इसलिए दुनिया के किस देश में अनिवार्यता है? और वहां पर सबसे ज्यादा deficiency हो, उस area में हम हमारे देश में तैयारी करके enter कर सकते हैं क्या? उनका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा।

दूसरा part है कि वहां establish चीजें हैं लेकिन cost is a problem, work force is a problem. तो फिर हमारा काम

रहता है कि हम उसको address करें और उसको address करने के लिए हम किस प्रकार की तैयारी करें? हम जितनी ज्यादा मात्रा में हमारे man power को value addition करके यहां से भेजेंगे और targeted काम के लिए भेजेंगे, हम बहुत बड़ा contribution global economy में भी कर सकते हैं। और of course भारत के नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो भारत की economy को तो लाभ होना ही होना है और उसका फायदा होगा।

कई क्षेत्र ऐसे हैं। जैसे हम कहें tourism. अब tourism कहने के मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ tourist destination होता है। Tourism कहने के बाद उसके पीछे अनेक चीजें हैं। Even food habits का होगा, soft skill का होगा, language का होगा, guide का होगा, even आपके cab के drivers होंगे तो उनकी training होंगी, पचासों चीजें होंगी। हमें अपना tourism बढ़ाना है तो हमारे देश में भी, हमारी service को कैसे हम qualitatively improve करें? Qualitatively improve करने के लिए कौन-कौन से हमारे पहलू हो? तो, हमारे यहां अपने देश की आवश्यकता के लिए भी उस प्रकार की नई पचासों institutions विकसित हो सकती हैं और ये public private partnership के model पर हो सकती हैं और करनी भी चाहिए। हम उसमें बहुत बड़ी मात्रा में role कर सकते हैं।

अभी मैं जर्मनी गया था। तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल के साथ ऐसे ही बात हो रही थी, लंच के समय पर जब हम मिले तो और guest अभी set हो रहे थे, meeting शुरू होना बाकी था। उन्होंने बातों ही बातों में, जब उनको पता चला कि मैं vegetarian हूं तो उन्होंने विषय निकाला। उन्होंने कहा कि मैं खुद Indian कढ़ी बनाती हूं, बोले मैं सीखी हूं। लेकिन फिर भी मुझे अभी perfect नहीं आती है। और कभी-कभी ingredient के संबंध में मुझे problem रहता है। ये जब मैंने सुना, तो तुरंत मुझे मेरे देश के service sector की तरफ ध्यान गया। इसका मतलब कि दुनिया में आजकल holistic health care की तरफ जब योगा ने एक ध्यान लिया है वैसे ही एक हवा चल पड़ी है vegetarianism की। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि vegetarianism में भी इतना development हो चुका है। क्या हम इस दिशा में service देने का तय करें। हमारे जितने यहां बड़े-बड़े होटल वाले हैं, वे अगर दुनिया के लोगों को इस प्रकार से सिखाने का काम करें, special classes करें, even tourist के लिए भी package बनाएं। 3 दिन cooking class, 3 दिन field visit. आप देखिए service के कितने पहलू हो सकते हैं, कितने प्रकार से उसको पढ़ाया जा सकता है, हमने कितने नए innovative हैं क्योंकि हमारे पास विपुल मात्रा में मानव संपदा है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम उन सेवाओं को दें ताकि हमारी अपनी product भी साथ-साथ चलती जाए। कभी-कभार ऐसा होता है कि भई आप ये लेंगे तो साथ में ये मिलेगा, तो साथ में ये भी जोड़ा जा सकता है। इसलिए हम सिर्फ IT के द्वारा सेवा करें, ये जो limited हमारी सोच बनी है, उसमें से हमने बाहर आना चाहिए, इसका दायरा बढ़ाना चाहिए। और सिर्फ बहुत ऊंचे पढ़े-लिखे लोग दुनिया को जरूरत, ऐसा नहीं है, अनेक प्रकार के लोगों की दुनिया को जरूरत है और ये आवश्यकता बढ़ने वाली है। और इसलिए हमने हमारे सेवा के layers, multiple layers सेवा के हमने दायरे पर सोचना होगा। वो अगर हम करते हैं तो बहुत लाभ पाएंगे, देश की सेवा करेंगे, दुनिया की भी सेवा करेंगे।

कुछ तो हम लोगों ने पुराने जमाने में जो नियम बनाए हैं, उस भय से बनाए हुए हैं - कहीं दुनिया आ जाएगी, खा जाएगी। आत्मविश्वास का अभाव रहा क्योंकि बहुत सालों तक हम गुलाम रहे। हमें उस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि arbitration हमारे देश में क्यों न हो? Global arbitration हमारे देश में क्यों न हो? Arbitration के लिए आज भी हमें London क्यों जाना पड़े? क्या हमारे पास उस प्रकार के chartered accountant, उस प्रकार के lawyer नहीं है क्या? हैं! लेकिन हमने कानून ऐसे बना के रखे हैं कि हमारा ही.. हां और कुछ लोगों को डर लगता है, नहीं-नहीं ये यहां मत शुरू करो, ये सब दुनिया भर के बड़े-बड़े बुद्धिमान वकील आ जाएंगे, तो हमारा काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है ये।

जो सोच किसे जमाने में थी कि technology आएगी तो job चली जाएगी, computer आएगा तो job चली जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि technology के कारण job का global scope पैदा हो गया है। वक्त बदल चुका है। हमने स्थितियों को visualise करना चाहिए और हमें भयभीत रहने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा, सवा सौ करोड़ का देश है। हम दुनिया से दबकर क्यों जीना चाहिए? हम अपनी ताकत खड़ी करें, दुनिया में हम अपना अस्तित्व दिखा सकते हैं, इस मिजाज से हमारी योजना और रचनाएं होनी चाहिए।

उसी प्रकार से finance का sector, हम देख रहे हैं अब via मॉरिशस आइए, via सिंगापुर आइए, हमें डर लगता है कहीं अपने यहां कर लिया तो? क्यों न करें हम? ये हम अपनी ताकत को मॉरिशस, सिंगापुर या मलेशिया को क्यों divert करें? हम अपने कानूनों और नियमों को इस प्रकार से बनाएं ताकि इन चीजों को हम भी हजम कर सकें और अपनी व्यवस्थाओं को विकसित कर सकें। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में देखेंगे आप, हम उन व्यवस्थाओं को विकसित करना चाहते हैं कि जो globally भारत को.. हां कुछ हमने उसकी सीमाएं भी बांधनी पड़ती हैं। जैसे intellectual property right, अब हम global parameter के intellectual property right की दिशा में काम नहीं करेंगे तो दुनिया

हमारे साथ नाता नहीं जोड़ेगी।

हम जानते हैं हमारी entertainment industry बहुत बड़ी ताकत रखती है। सिर्फ हिंदुस्तान में फिल्म बनाने की ताकत रखती है, ऐसा नहीं है। लेकिन intellectual property right में उनको भरोसा दुनिया को हम दे दें, मुझे विश्वास है हम globally एक बहुत बड़ा destination बन सकते हैं, उनके अपने creative work के लिए। भारत में creative work के लिए इतनी बड़ी संभावनाएं पड़ी हैं - दुनिया में कोई कार बनाए, कार की manufacturing वाला होगा वहां लेकिन कार में अंदर की seat की design क्या हो? वो बनाने की ताकत हिंदुस्तानी में है। और वो ही कार ज्यादा तब बिकेगी, इसलिए नहीं कि तुम्हारा मशीन कैसा है, सीट कैसी है, इसके आधार पर कार बिकती है कि भई बैठना कितना comfortable है, उतरना कितना comfortable है और उस काम को करने वाले भी लोग होते हैं। Service! Creative services! इसके लिए हमारे पास इतनी संभावनाएं हैं और हम उसका लाभ उठा सकते हैं।

आज योगा और IT - दो क्षेत्र ऐसे हैं, जिन्होंने दुनिया में हिंदुस्तान को भी पहुंचाया है और इसके माध्यम से हिंदुस्तान भी पहुंचा है। लेकिन एक विशेषता है, ये दोनों पहुंचे हैं क्योंकि वहां सरकार नहीं है... बड़ी देर लगी आपको, ये इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम नहीं हैं वहां। क्योंकि सरकार का mind set ऐसा बना हुआ है वहां, सालों से, ये हिंदुस्तान के 20, 22, 24 साल के नौजवान हैं, जिन्होंने दुनिया में भारत के IT माध्यम से पहचान खड़ी की है, ताकत के रूप में पहचान बना दी है। उसी प्रकार से दुनिया का मानव जो कि stress के कारण परेशान है, frustration से जी रहा है, बहुत कुछ पाने के बाद भी संतोष अनुभव नहीं कर रहा है तो वो दूढ़ता-दूढ़ता आया, वो योग उठाकर ले गया। कोई आकर के ले गया, कोई जाकर के दे आया, ये दो route से हमारा हुआ है।

हम इसको और अधिक scientific बनाकर के एक बहुत ही, यानी भारत की अपनी सोच के रूप में, हम ऐसे किन-किन क्षेत्रों में.. मान लीजिए संगीत, दुनिया को, दुनिया को, मैं मानता हूं संगीत के माध्यम से हम बहुत कुछ दे सकते हैं। दुनिया को अभी तक ये भी पता नहीं है कि तन डोले इसलिए संगीत होता है कि मन डोले इसके लिए संगीत होना चाहिए। ज्यादातर परिचय यही है कि संगीत यानी तन डोले, संगीत से मन डोलना चाहिए और ये ताकत हिंदुस्तान में है! ये ताकत हिंदुस्तान में है! ये देश है कि किस प्रहर में कौन सा राग हो, किस बीमारी में कौन सा राग हो, बालक अवस्था हो तो कौन सा राग हो, निवृत्त अवस्था हो तो कौन सा राग हो। यहां तक जहां वैज्ञानिक काम हुआ हो, क्या दुनिया को हम ये सेवा नहीं दे सकते हैं? फिर से एक बार गुरु-शिष्य परंपरा revive हो और मान लीजिए हिंदुस्तान में एक हजार अच्छे सितारवादक हैं। और दुनिया के एक हजार शिष्य उनके यहां आ जाएं, उनके यहां रहें, सितार सीखें, साल भर का अपना गुरु-दक्षिणा दें और वापिस चले जाएं। क्या भारत का, संगीत की दुनिया में जिसने साधना की है, उसको कभी भूखे रहने की नौबत आएगी क्या? कभी नहीं आएगी और जो यहां से सीखकर गया, वो सिर्फ सितार ही सीखकर जाएगा कि पूरा हिंदुस्तान लेकर के जाएगा? हिंदुस्तान अपने आप पहुंच जाएगा कि नहीं जाएगा?

हमारी service sector की ताकत ये है कि विश्व में हमें अपने आप को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने आया है। सिर्फ विश्व की सेवा करेंगे, ऐसा नहीं, विश्व को अपना बनाने की ताकत हमने पाई है.. और समय-समय पर इस देश ने किया है। मैं अभी फ्रांस गया था। फ्रांस में मैं युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी हुई। सेवा कैसी हमारे लोग कर सकते हैं, इसका एक उत्तम उदाहरण है। एक सौ साल हो गए हैं, प्रथम विश्व युद्ध में करीब 14 लाख हिंदुस्तान के जवानों ने किसी और के लिए लड़ाई लड़ी थी, अपने लिए नहीं, हमारी जमीन को बढ़ाने के लिए नहीं, हम मर रहे थे इसलिए बचने के लिए नहीं, किसी और के लिए। और करीब-करीब 75 हजार लोगों ने शहादत दी। मैं मानता हूं कि दुनिया समझे किसी भी प्रकार की सेवा यानी अपना जीवन आहुत कर देने तक की सेवा देना, इस देश ने करके दिखाया है। अगर उसने किसी की रक्षा के लिए अपनी जान देकर के दिखाया है तो जीवन बचाने के लिए हमारे डॉक्टरों ने दुनिया में जाकर के अपने करतब दिखाए हैं।

और इसलिए मैं कहता हूं कि हम इस क्षेत्र को सीमित न मानें। ये बहुत बड़ी मानवता की सेवा है। ये बहुत बड़ी देश की सेवा है। उसको हमारी ताकत को जल्दी पहचाने, हम अपनी ताकत को दूढ़े, उसको हम globally requirement के अनुसार value addition करें, दुनिया की requirement का हम mapping करें, और हम कर सकते हैं। 2025 में किस देश की किसकी जरूरत पड़ेगी, ये हम कर सकते हैं। आज इतनी सारी चीजें हो सकती हैं और उस प्रकार से हम तैयारी करें।

मुझे विश्वास है सेवा के क्षेत्र में हम इन कामों को करेंगे तो जरूर ही भारत अपनी एक जगह बना सकता है। सरकार में जो नियमों को बदलना होगा, उसको भी बदलते हुए इन कामों को करना चाहिए। मैं फिर एक बार.. सबने मिलकर के इस बात को आगे बढ़ाया है और भी इसको बल दिया जाए। सरकार में भी इस बदले हुए brain drain के जमाने को छोड़कर के brain gain की दिशा में हम अपनी योजनाएं को केंद्रित करें। इस अपेक्षा के साथ बहुत-बहुत शुभकामनाएं।



धन्यवाद।

\*\*\*

महिमा वशिष्ट / रजनी, सोनिका, मुस्तकीम खान

**पत्र सूचना कार्यालय**  
**भारत सरकार**  
**प्रधानमंत्री कार्यालय**

08-अप्रैल-2015 14:35 IST

**प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए वक्तव्य का मूल पाठ**

उपस्थित सभी महानुभाव,

हमारे देश में एक अनुभव ये आता है कि बहुत सी चीजें Perception के आसपास मंडराती रहती हैं। और जब बारीकी से उसकी ओर देखें तो चित्र कुछ और ही नजर आता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति को पूछो तो उसको लगेगा कि “भई, ये जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, बड़े-बड़े उद्योग घराने हैं, उससे रोजगार ज्यादा मिलता है।” लेकिन अगर बारीकी से देखें तो चित्र कुछ और होता है, इसमें इतनी ज्यादा पूंजी लगी है। इतने सारे ताम-झांम, हवाबाजी, ये सब हम देखते आए हैं।

लेकिन अगर बारीकी से देखें तो ultimately हम विकास में हैं। रोजगार हमारी प्राथमिकता है और भारत जैसा देश जिसके पास Demographic dividend हो, जहां पर 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, उस देश ने अपने विकास की जो भी नीतियां बनानी हो, उसके केंद्र में ये युवा शक्ति होना चाहिए। अगर वो बराबर match कर लिया, तो हम नई ऊंचाईयों को पार कर सकते हैं। ये जितने बड़े-बड़े उद्योगों की हम चर्चा सुनते आए हैं, उसमें सिर्फ एक करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। सवा सौ करोड़ देश में सवा करोड़ लोगों को रोजगार, ये जो बहुत बड़े-बड़े लोग जिसके लिए दुनिया में चर्चा रहती है, आधा अखबार जिनसे भरा पड़ा रहता है, वो देते हैं।

लेकिन इस देश में छोटा-छोटा काम करने वाला व्यक्ति करीब 5 करोड़ 70 लाख लोग, 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। उन सवा करोड़ को रोजगार देने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं सक्रिय हैं। लेकिन 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी हम मदद करें, तो कितना बड़ा फर्क आ सकता है इसका हम अंदाज कर सकते हैं। और इस 5 करोड़ 75 लाख इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो स्वरोजगार एक प्रकार से हैं - दर्जी होंगे, कुम्हार होंगे, टायर का पंकचर करने वाले लोग हैं, साइकिल की repairing करने वाले लोग हैं, अपनी एक ऑटो रिक्शा लेकर के काम करने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले, गरीब-गरीब लोग हैं। उनका पूरा जो कारोबार है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हिसाब लगाएं जाएं, तो 11 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा उसमें पूंजी नहीं लगी है। यानी सिर्फ 11 लाख करोड़ रुपयों की पूंजी लगी है, 5 करोड़ 75 लाख उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और 12 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं।

ये बातें जब सामने आईं तो लगा कि देश में स्वरोजगारी के अवसर बढ़ाने चाहिए। देश की Economy को ताकत देने वाला जो नीचे पायरी पर जो लोग हैं, उनकी शक्ति को समझना चाहिए। और उनके लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए और इस मूल चिंतन में से ये मुद्रा की कल्पना आई है। मेरा अपना एक अनुभव इसमें काम कर रहा था, क्योंकि सिर्फ आर्थिक जगत के लोगों के आंकड़ों के आधार पर निर्णय करना, इतना सरल नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी अनुभव बहुत काम आता है।

मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहा तो मैंने पतंग उद्योग की तरफ थोड़ा ध्यान दिया। अब गुजरात में पतंग एक बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जाता है, और ज्यादातर, अब वो पूरा Environment Friendly Industry है, Cottage Industry है। और लाखों की तादाद में गरीब मुसलमान उस काम में लगा हुआ है 90 प्रतिशत से ज्यादा पतंग बनाने व कबाड़ का काम गुजरात में मुसलमान कर रहा है, लेकिन वो वही पुरानी चीजें करता था। वो पतंग अगर उसको तय तीन कलर का बनाना है तो तीन कलर के कागज लाता था पेस्टिंग करता था और फिर पतंग बनाता था। अब दुनिया बदल चुकी है तीन कलर का कागज प्रिंट हो सकता है, टाइम बच सकता है। तो मैंने चेन्नई की एक Institute को काम दिया कि जरा सर्वे किजिए कि इनकी मुसीबत क्या है, कठिनाईयां क्या है, अनुभव ये आया कि छोटे-छोटे लोगों को थोड़ी मदद दी जाए थोड़ा Skill Development हो जाए, थोड़ी पैकेजिंग सिखा दिया जाए, आप उसमें कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मुझे आज कहने से आनंद होता है कि जो करीब 35 करोड़ का पतंग का बिजनेस था थोड़ी मदद की वो पतंग का उद्योग 500 करोड़ cross कर गया था।

फिर मेरी उसमें जरा रुचि बढ़ने लगी तो मैं कई चीजें नई-नई करने लगा। बांस, बांस वो लाते थे असम से। कारण क्या तो पतंग में जिस बांस के पट्टे की जरूरत होती है वो साइज का बांस गुजरात में होता नहीं था तो मैंने ये जेनेटिक

इंजीनियरिंग वालों को पकड़ा। मैंने कहा बांस हमारे यहां ऐसा क्यों न हो दो गांठ के बीच अंतर ज्यादा हो ताकि वो हमारा ही लोकल बांस का product उसको काम आ जाए। बांस वो बाहर से लाता है तो उसको फाइनेंस की व्यवस्था हो फिर मैंने एडवर्टाइजमेंट कम्पनी को बुलाया। मैंने कहा जरा पतंग वालों के साथ बैठो पतंग के ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट का काम हो सकता है क्या उनकी कमाई बढ़ सकती है।

छोटी-छोटी चीजों को मैंने इतना ध्यान दिया था और मुझे उतना आनंद आया था उस काम में - I'm Talking about 2003-04 - कहने का मेरा तात्पर्य यह था कि जो बिल्कुल उपेक्षित सा काम था उसमें थोड़ा ध्यान दिया गया, फाइनेंस की व्यवस्था की गई, उसने तेज गति से आगे बढ़ाया। ये ताकत सब दूर है। आप देखिए हर गांव में दो-चार मुसलमान बच्चे ऐसे होंगे, इतने Innovative होते हैं technology में ईश्वरदत्त उनको कृपा है। वो तुरंत चीजों को पकड़ लेते हैं। आप एक ताला उसको रिपेयर करने को दीजिए वो दूसरे दिन वो ताला वैसा बना के दे देगा। जिनके हाथों में ये परम्परागत कौशल है। ऐसे लोगों को अगर हम मदद करें और वो कुछ गिरवी रखें तब मिले तो उसके पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है - सिवाय कि उसका ईमान। उसकी सबसे बड़ी पूंजी है उसका ईमान। ये गरीब इंसान की जो पूंजी है, ईमान। उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है, ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं।

कुम्हार है, अब बिजली गांव में पहुंच गई है। वो भी चाहता है कि मैं मटकी बनाता हूं और चीजें बनाता हूं। लेकिन अगर Electric motor लग जाए तो मेरा काम तेज हो जाएगा। लेकिन Electric motor खरीदने के लिए पैसा नहीं है। बैंक के लिए उनके पास इतना समय भी नहीं है और उतना नेटवर्क भी नहीं है। लेकिन मैं आज, यहां बैंक के बड़े-बड़े लोग बैठे हैं। मेरे शब्द लिख करके रखिए। एक साल के बाद बैंक वाले Queue लगाएंगे मुद्रा वालों के यहां और कहेंगे भई 50 लाख हमको client दे दीजिए।

क्योंकि अब देखिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना में हिन्दुस्तान की बैंक सेक्टर ने जो काम किया है, मैं जितना अभिनंदन करूं उतना कम है जी, जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि बैंक के संबंध में एक सोच बनी हुई थी कि बैंक यानी इस दायरे से नीचे नहीं जा सकते। तो बैंक के लोगों ने गर्मी के दिनों में गांव-गांव घर-घर जा करके गरीब की झोपड़ी में जा करके उसको देश की फाइनेंस की Main Stream में लाने का प्रयास किया और इस देश के 14 करोड़ लोगों को, 14 करोड़ लोगों को बैंक खाते से जोड़ दिया। तो ये ताकत हमने अनुभव की है तो उसका ये अलग एक नया step है।

आज वैसे एक ओर भी अवसर है SIDBI का रजत जयंती वर्ष है SIDBI 25 साल की उम्र हो गई और मूलतः SIDBI का कारोबार इसी काम से शुरू हुआ था, छोटे-छोटे लोगों को... लेकिन जितनी तेजी से क्योंकि भारत देश rhythmic way में progress करे तो अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी। हमने उस rhythm को बदलकर के jump लगाने की जरूरत है। हमने दायरा बढ़ाने की जरूरत है। हमने अधिक लोगों को इसके अंदर जोड़ने की आवश्यकता है और सामान्य मानवी का अपना अनुभव है।

आप देखिए हिन्दुस्तान में जहां भी women self help group चलते हैं, पैसों के विषय में शायद ऐसी ईमानदारी कहीं देखने को मिलेगी नहीं। उनको अगर 5 तारीख को पैसा जमा करवाना है तो 1 तारीख को जाकर के जमा करवाकर आ जाती हैं। बचत हमारे यहां स्वभाव है, उसको और जरा ताकत देने की आवश्यकता है। हमारी परंपरागत वो शक्ति है।

मुद्रा बैंक के माध्यम से व्यवसाय के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जो निचले तबके पर आर्थिक व्यवस्था में रहे हुए लोग हैं, वे हमारा सबसे बड़ा client, हमारा सबसे बड़ा target group है। हम उसी पर focus करना चाहते हैं। इन 5 करोड़ 75 लाख जो छोटे व्यापारी हैं... और उनका average कर्ज कितना है? पूरे हिन्दुस्तान में 11 लाख करोड़ की उनके पास पूंजी है total पूरे देश में कोई ज्यादा amount नहीं है वो और average कर्ज निकाला जाए तो एक यूनिट का average कर्ज 17 thousand है सिर्फ। 17 thousand हैं, यानी कुछ नहीं है। अगर उसको एक लाख के कर्ज की ताकत दे दी जाए। उसको इतना अगर जोड़ दिया जाए और ये 11 लाख करोड़ है वो एक करोड़ तक अगर पहुंच जाए। हम कल्पना कर सकते हैं देश की economy को GDP को, नीचे से ताकत देने का इतना बड़ा force जो कि कभी untapped था।

और इसलिए जब हम प्रधानमंत्री जन-धन योजना लेकर के आए थे तब हमने कहा था, जहां बैंक नहीं उसको बैंक से जोड़ेंगे। आज जब हम मुद्रा लेकर के आए हैं, तो हमारा मंत्र है जिसको funding नहीं हो रहा है, जो un-funded है, उसको funding करने का हम बीड़ा उठाते हैं।

ये एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें शुरू के समय में सामान्य व्यक्ति जाएगा ये संभव नहीं है क्योंकि बेचारों को अनुभव बहुत

खराब है। वो कहता है भई मुझे तो साहूकार से ही पैसा लेना पड़ता है। 24 percent, 30 percent interest देना पड़ता है, वो ही मुझे आदत हो गई है। वो विश्वास नहीं करेगा कि उसको इस प्रकार से ऋण मिल सकता है। हम ये एक नया विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि आप देश के लिए काम कर रहे हो, देश के विकास के भागीदार हो, देश आपके लिए चिंता करने के लिए तैयार है। ये message मुझे देना है।

और ये मुद्रा के concept के द्वारा, उसी दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे देश में agriculture sector में value addition - इतनी बड़ी संभावनाएं हैं। अगर उसकी एक विधा को develop कर दिया जाए तो हमारे किसान को कभी संकटों से गुजरना नहीं पड़ेगा। और ये छोटे-छोटे entrepreneur के माध्यम से ये पूरा network खड़ा किया जा सकता है जो सामान्य किसान, जो सामान्य पैदावार करता है, उसमें value addition का काम करे। और स्थानीय स्तर पर करे। कोई बहुत बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। अपने आप उसका काम आगे बढ़ जाएगा।

और हम देखते हैं आम उसको बेचना है, तो बेचारे को बड़ा कम पैसा मिलता है लेकिन एक अगर एक छोटा सा unit भी हो, आम में से अचार बना दे तो ज्यादा पैसा मिलता है और अचार को भी अच्छा बढ़िया bottle में packing करे और ज्यादा पैसा मिलता है और कोई नटी bottle लेकर खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसा मिलता है advertising होता है तो।

यानि वक्त बदल चुका है, branding, advertising इन सारी चीजों की जरूरत पड़ गई है। हम ऐसे छोटे-छोटे लोगों को ताकत देना चाहते हैं। और उनको अगर ताकत मिलती है तो देश की economy की नीचे की धरातल, जितनी ज्यादा मजबूत होगी, उतनी देश की economy को लाभ होने वाला है। और जब मैंने ये आकड़े बताए तो आप भी चौंक गए होंगे कि इतना बड़ा तामझाम सवा करोड़ लोग रोजगार पाते हैं। और जिसकी ओर कोई देखता नहीं है, वो 12 करोड़ लोगों के पेट भरता है। कितना बड़ा अंतर है। ये जो 12 करोड़ लोग हैं 25 करोड़ को रोजगार देने की ताकत देते हैं। वो Potential पड़ा है। और ज्यादा कोई शासकीय व्यवस्था में बड़े बदलाव की भी जरूरत नहीं है। थोड़ी संवेदनशीलता चाहिए, थोड़ी समझ चाहिए और थोड़ा Pro-Active role चाहिए।

मुद्रा एक ऐसा platform खड़ा किया गया है, जिस platform के साथ इसको... आज छोटी-मोटी finance की व्यवस्थाएं चल पड़ी हैं। दुनिया में कई जगह पर प्रयोग हुए हैं Micro finance के। लिए मैं चाहूंगा कि हम पूरे विश्व में Micro finance के जो Successful Model हैं हम भी उसका अध्ययन करें। उसकी जो अच्छाइयां हैं जो हमारे लिए suitable हैं, हम उसको adopt करें। और हिन्दुस्तान इतना बड़ा देश है कि जो चीज नागालैंड में चलती है वो महाराष्ट्र में चलेगी जरूरी नहीं है। विविधता चाहिए। और विविधताओं के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपने मॉडल बनाएं उसकी requirement करें। वरना हम दिल्ली में बैठ करके tailor के लिए ये और फिर कहेंगे कि तुमको ये मिलेगा तो मेल नहीं बैठेगा। वो वहां है उसी को पूछना पड़ेगा कि भई बताओं तुम्हारे लिए क्या जरूरत है? ये अगर हमने कर दिया तो हम बहुत बड़ी मात्रा में समाज के इस नीचे के तबके को मदद कर सकते हैं।

जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति की चिंता करना ये हमारा प्रयास है... और आपने इस सरकार के एक-एक कदम देखें होंगे, गतिशीलता तो आप देखते ही होंगे। वरना सामान्यतः देश में योजनाओं की घोषणा को ही काम माना जाता था और आप रोज नई योजना की घोषणा करो तो अखबार के आधार पर देश को समझने वाले जो लोग हैं वो तो यही मानते हैं कि वाह देश बहुत आगे बढ़ गया। और दो-चार साल के बाद देखते हैं कि वही कि वही रह गए। हमारी कोशिश है योजनाओं को धरती पर उतारना।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना ये सीधा-सीधा दिखता है। पहल योजना - दुनिया में सबसे बड़ा Cash Transfer का काम। गैस सब्सिडी में। 13 करोड़ लोगों के गैस सब्सिडी सिलेंडर, सब्सिडी सीधी उसके बैंक खाते में चली गई। यानी अगर एक बार निर्णय करें कि इस काम पूरा करना है और हर काम को आप देखिए... जब हमने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जन-धन योजना की बात कही करीब-करीब सवा सौ दिन के अंदर उस काम को पूरा कर दिया।

जब हम प्रधानमंत्री जन-धन योजना के बाद हम आगे बढ़े सौ दिन के भीतर-भीतर हमने पहल का काम पूरा कर दिया।

और आज जब बजट के अंदर घोषणा हुई, 50 दिन भी नहीं हुए, वो आज योजना आपके सामने रख दी। और ये Functional होगी और उसका परिणाम मैं कहता हूं एक साल में ज्यादा समय नहीं कहता। एक साल के भीतर-भीतर हमारी जो Established Banking System है, वो मुद्रा के मॉडल की ओर जाएगी मैं दावे से कहता हूं क्योंकि इसकी ताकत इसकी ताकत पहचान में आने वाली है। वे अपना एक लचीली बैंकिंग व्यवस्था खड़ी करेंगे, एक बहुत बड़ी ऑफिस चाहिए, कोई एयरकंडीशन चाहिए कोई जरूरत नहीं है। ऐसे Bare footed बैंकर्स तैयार हो सकते हैं जो मुद्रा के मॉडल पर बड़ी-बड़ी बैंकों का काम भी कर सकते हैं।

आने वाले दिनों में कम से कम धन लगा करके भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम इसके साथ सरलता से हो सकता है और ये लोग जो संकट से गुजरते हैं, ब्याज के चक्कर में गरीब आदमी मर जाता है। उसको बचाना है और उसकी जो ताकत है उसके लिए अवसर देना है उस अवसर की दिशा में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश में ये जो वर्ग है उसकी जितनी चिंता करते हैं, उतनी ही देश के किसान की चिंता करना उतना ही जरूरी है।

किसी न किसी कारण से देश का किसान प्राकृतिक संकटों से जूझ रहा है। गत वर्ष, वर्षा कम हुई। वर्षा कम होने के कारण वैसे ही किसान मुसीबत से गुजारा कर रहा था और इस बार जितनी मात्रा में बेमौसमी वर्षा और ओले गिरना। इतनी तबाही हुई है किसान की। हमने मंत्रियों को भेजा था। खेतों में जा करके किसानों से बात करके परिस्थिति का जायजा लिया। कल इन सारे मंत्रियों से मैंने डिटेल में रिपोर्ट ली थी। इन किसानों को हम क्या मदद कर सकते हैं। और मैंने पहले दिन कहा था कि किसान को इस मुसीबत से बचाना, उसका साथ देना, उसको संकटों से बाहर लाना। ये सरकार की, समाज की, हम सबकी जिम्मेवारी है और किसान की चिंता करना ये आवश्यक है।

Natural calamity पहले भी आई है। लेकिन सरकार के जो parameter रहे हैं, उन parameters में आज के संकट में किसान को ज्यादा मदद नहीं मिल सकती है। और इसलिए ये संकट की व्यापकता इतनी है और उस समय है जबकि उसको फसल लेकर के बाजार में जाना था। एक प्रकार से उसके नोटों का बंडल ही जल गया, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इतना बड़ा उसका, उसका पूरा पसीना बहाया हुआ उसका, ये हालत हुई है। और इसलिए हमने insurance company को भी आदेश किया है कि बहुत ही proactive होकर के उनकी मदद की जाए। बैंकों को हमने आदेश किया है कि बैंक उनके जो कर्ज हैं, उनके संबंध में किस प्रकार से restructure करे ताकि उनको इस संकट से बाहर लाया जाए।

सरकार की तरफ से भी एक बहुत बड़ा अहम निर्णय हम करने जा रहे हैं। अब तक खेत में 50 प्रतिशत से ज्यादा अगर नुकसान हुआ हो, तभी वो उस मदद पाने की list में आता है। 50 प्रतिशत से ज्यादा अगर नुकसान हुआ होगा तभी आपको मदद मिल सकती है। अगर 50 प्रतिशत से कम हुआ है तो मदद नहीं मिल सकती है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी ये एक सुझाव था कि साहब ये norms बदलना चाहिए। हमारे मंत्री अभी जाकर के आए, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, और ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि अब किसान के वो जो 50 प्रतिशत के नुकसान वाला दायरा था उसको बदलकर के 33 percent भी अगर नुकसान हुआ है तो भी वो किसान हकदार बनेगा।

उसके कारण मुझे मालूम है बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, बहुत बड़ा बोझ आने वाला है लेकिन किसान को 50 प्रतिशत वाले हिसाब में रखने से उसको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। 33 percent जो कि कईयों की मांग थी, उसको हमने स्वीकार किया है।

दूसरा विषय है उसको जो मुआवजा दिया जाता है। देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा निर्णय पहली बार हुआ है 50 प्रतिशत को 33 प्रतिशत लाना। और दूसरा महत्वपूर्ण आजादी के बाद इतना बड़ा jump नहीं लगाया है, किसानों को मदद करने में हम इतना बड़ा jump इस बार लगा रहे हैं। और आज उसको जो मदद करने के सारे parameters हैं, उसको अब डेढ़ गुना कर दिया जाएगा। अगर उसको नुकसान में पहले 100 रुपया मिलता था, 150 मिलेगा, लाख मिलता था तो डेढ़ लाख मिलेगा, उसकी मदद डेढ़ गुना कर दी जाएगी।

कभी हमारे यहां incremental होता था 5 percent, 2 percent, 50 प्रतिशत वृद्धि। और ये किसान को तत्काल मदद मिले। राज्यों ने सर्वे का काम किया है। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के उसको आगे बढ़ाएगी लेकिन मैं चाहता हूं हमारे देश के किसानों को जितनी मदद हो सके, उतनी मदद करने के लिए ये सरकार संकल्पबद्ध है। क्योंकि आर्थिक विकास की यात्रा में किसान का भी बहुत बड़ा योगदान है और हमारी जीवन नैया चलाने में भी किसान का बहुत बड़ा योगदान है। बैंक हो, insurance company हो, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम सब मिलकर के किसान को इस संकट की घड़ी से हम बाहर लाएंगे। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।

फिर एक बार मैं SIDBI की इस रजत जयंती वर्ष के प्रारंभ पर उनको मैं बहुत-बहुत शुभकामना देता हूं और SIDBI आने वाले दिनों में नए लक्ष्य को लेकर के और नई ऊंचाइयों को पार करने में सफल होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।

और मुद्रा platform प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आने वाले दिनों में देश की आर्थिक, जो पक्की धरोहर है उसको जानदार बनाना, शानदार बनाने के काम में मुद्रा बहुत बड़ा role play करेगी। और ये पूंजी उसकी सफलत की कुंजी बने, ये मंत्र को हम चरितार्थ करेंगे। इसी एक शुभ आशय के साथ आज इस महत्वपूर्ण योजना को प्रारंभ करते हुए मुझे खुशी हो रही है, मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

धन्यवाद।

\*\*\*

महिमा वशिष्ट / सुरेन्द्र कुमार, मुस्तकीम खान, लक्ष्मी

**पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय**

02-अप्रैल-2015 16:54 IST

**वित्तीय समावेशन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के सम्मलेन के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गये भाषण का मूल पाठ**

वित्त विश्व के सभी महानुभाव,

रिज़र्व बैंक की 80 साल की यात्रा पर हम लोग आज मिले हैं। हमारे देश में 80 साल का विशेष महत्व रहता है। दुनिया में 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, उस हिसाब से अवसरों को याद किया जाता है लेकिन शायद भारत इकलौता ऐसा देश है कि जिसमें 80 साल को भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है और उसका कारण ये है कि हमारे यहां इसको सहस्त्र-दर्शन, चंद्र-दर्शन के रूप में माना जाता है। जब 80 साल होते हैं तब Full moon एक हजार बार देखने का अवसर मिलता है, तो रिज़र्व बैंक को एक हजार पूर्ण चंद्र के शीतलता के आशीर्वाद मिले हैं और उस अर्थ में इस अवसर का एक विशेष महत्व होता है।

मैं ज्यादा इस दुनिया का इंसान नहीं हूं, इसलिए जो भाषण आपने सुने अभी, वो मेरे Software के विषय नहीं हैं। ईश्वर ने मुझे जो Software दिया है, उससे ये सब बाहर है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इन सब चीजों को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हर दो महीने में एक बार रघुराम से मिलना होता है और मैं देखता हूं वो 3 या 4 Slides लेकर के आते हैं और मुझे इतना Perfectly समझाते हैं यानी शायद वो Best teacher भी रहे होंगे? कोई मुझे Question नहीं करना पड़ता। मुझे बिल्कुल समझ आता है कि हां ये...ये कहना चाहते हैं और ये इसका ये मतलब होता है, इसके ये परिणाम होता है और इसका मतलब ये हुआ कि शायद सरकार की और आरबीआई की सोच में बहुत साम्यता होगी तब ये संभव होता होगा और मैं मानता हूं ये बहुत आवश्यक होता है और उस विषय में मैं एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपना संतोष व्यक्त करता हूं। आरबीआई अपनी जो भूमिका अदा कर रहा है, मैं रघुराम जी और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और 80 साल की यात्रा में श्रीमान देशमुख और उनकी टीम से लेकर के अब तक जिन-जिन लोगों ने योगदान दिया है, कई लोगों ने अपनी जवानी इस काम के लिए खपाई होगी? तब जाकर के ये Institution इस ऊंचाई पर पहुंचती है।

Global Perspective में भी अपने आपको ढाला होगा, बदले हुए वैश्विक परिवेश में आरबीआई के Relevance को बनाए रखने के लिए यहां भी काफी जददोजहद हुई होगी। इस समय पर जो नेतृत्व दिया होगा, वे सब भी अभिनंदन के अधिकारी हैं और मेरी तरफ से अब तक जिन-जिन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है, उन सबको भी हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं और देशवासियों की तरफ से उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। अमीर से अमीर व्यक्ति भी अपने Family doctor को Time देता हो या न देता हो, लेकिन Banker को अवश्य Time देता है। उसके जितने Lunch-dinner होते होंगे, उसमें ज्यादातर Banker के साथ होते होंगे। अमीर को भी जहां जाने पड़ता है मांगने के लिए, वो जगह है बैंक तो मैं भी आज यहां मांगने के लिए आया हूं और मैं भी यहां मेरे परिवार के लिए मांगने के लिए आया हूं और मेरा परिवार है, जिनके बीच में पैदा हुआ, जिनके बीच में पला-बढ़ा, वो गरीब परिवार हैं। गरीबों के बीच में मैं पला-बढ़ा हूं। मेरा बचपन वहां गया है। मेरी जिंदगी के उन चीजों को देखा है और अब प्रधानमंत्री बना हूं तो मेरा ये परिवार इतना विस्तृत हो गया है कि एक प्रकार से Below poverty line के नीचे जीने वाले सारे गरीब, एक प्रकार से marginal farmer, एक प्रकार से दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी ये सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं और उस परिवार के एक प्रतिनिधि के रूप में मैं आज, ये वित्त विश्व के पास मैं कुछ मांगने आया हूं और जब आप 80 साल मना रहे हो तो जरूर किसी को निराश नहीं करोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है और मैं आरबीआई के सभी नीति-निर्धारकों का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने Financial inclusion को अपना विषय के रूप में पसंद किया है और 80 साल के समय इस अवसर को मना रहे हैं। इसका मतलब आप जब 100 साल के होंगे और जब शताब्दी मनाते होंगे, वो शताब्दी इस Financial inclusion को लेकर के कहां पर पहुंची होगी, मैं समझता हूं उसके Target भी Set करोगे तो 20 साल के अंदर भारत की बैंकिंग व्यवस्था गरीब के दरवाजे तक पर किस प्रकार से काम कर रही है इसका एक खाका तैयार हो जाएगा और जब 20 साल का पड़ाव आप सोचते हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा।

2019 महात्मा गांधी के 150 वर्ष हो रहे हैं। 2022 देश की आजादी को 75 साल हो रहे हैं। 2025 आपको 90 हो रहे हैं और 2035 ये आपके 100 होंगे। ये चार महत्वपूर्ण पड़ाव मानकर के हम अपना एक मैप तैयार कर सकते हैं कि ये Financial inclusion में जाने के लिए ये-ये हमारे Target group होगा, ये हमारा रोडमैप होगा और हम ये Achieve करके रहेंगे और पूरे भारत में चाहे Corporative Sector का बैंकिंग हो या Micro Finance करने वाले Institutions हो या हमारी Nationalised बैंक हो या हमारी रिजर्व बैंक स्वयं हो, हम सब एक ही दिशा में सोचे, ऐसा हो सकता है क्या?

अगर प्रधानमंत्री जन-धन योजना सफल न होती, मैं नहीं मानता हूँ कि वित्त व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसकी इतनी ताकत का अंदाजा था। ये बड़ा ही उपेक्षित वर्ग रहा। आजादी के इतने साल के बाद भी 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग, अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ होती है, बैंकिंग व्यवस्था उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे। मैं सभी बैंकों के छोटे-मोटे हर व्यक्ति को आज बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया और आज देश ने Achieve किया है। ये छोटा Achievement नहीं है। भारत की आजादी के बाद गरीब से गरीब व्यक्ति का देश की आर्थिक मुख्यधारा से जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ा Achievement है। उसने Financial world में एक नया विश्वास पैदा किया है और एक नई दिशा का संकेत दिया है।

दूसरी तरफ जब तक हम गरीब की तरफ देखना का अपना नजरिया नहीं बदलेंगे। Individual level पर नहीं, एक समाज के आर्थिक ढांचे के रूप में तब तक हम शायद Project लेंगे, परिणाम लेंगे लेकिन जब तक वो Conviction नहीं बनता है, Article of faith नहीं बनता है, हम शायद परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते और Article of faith बनने के पीछे या Conviction बनने के पीछे कुछ घटनाएं होती हैं, जो हमारी सोच को बदलती हैं।

मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जन-धन योजना की सफलता उस बात की ओर संकेत करती है। सरकार ने तो तैयार किया था, आरबीआई ने माना था, बैंकों ने मदद की थी कि हम Zero balance account खोलेंगे और आप देखिए गरीब की अमीरी देखने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है। बैंक वालों ने अमीरों की गरीबी बहुत बार देखी होगी, समय पर पैसा न जमा करने वाले कई अमीर उन्होंने देखे होंगे। Risk लेने वाले बैंक मैनेजर भी परेशान रहते होंगे? यार March ending नहीं हुआ, तो मर जाऊंगा मैं तो? तो आपने अमीरों की गरीबी देखी होगी लेकिन इस जन-धन की योजना से गरीबों की अमीरी देखने का सौभाग्य मिला है। Zero balance से account खोलने के कहने के बावजूद भी, जो 14 करोड़ लोगों ने Bank account खोले, उसमें 41 Percent लोग ऐसे हैं कि जिनका लगा कि नहीं-नहीं मुफ्त में नहीं करना चाहिए। कुछ न कुछ तो रखना चाहिए और 14 हजार करोड़ रुपया उन्होंने जमा कराया। 14 हजार करोड़ रुपया। देश का गरीब Zero balance account खोलने के बावजूद भी 14 Thousand crore रुपया बैंक में जमा करता है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी गरीबी की अमीरी नहीं हो सकती है।

अगर इसको हम एक ताकत समझे और ये जो उनके संस्कार हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक भूमिका है, उनके जो मन के आदर्श हैं, ये भी राष्ट्र की एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं। हमें उनको nurture करना चाहिए, उस सामर्थ्य को हमें पहचानना चाहिए और मैं मानता हूँ Banking sector के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे पुरुषार्थ से 14 करोड़ Bank account खुल गए, हम बधाई के पात्र हैं लेकिन 41 Percent लोग पैसे जमा कराएं, वो मैं समझता हूँ वो हमारे लिए inspiration का कारण हैं। हमारी नई योजनाओं के लिए वो एक हमारे लिए एक land mark बन सकता है और मैं आशा करूंगा कि आने वाले दिनों में, ये बात ठीक है कि 5-50 client के साथ बड़ा काम करना, सरल रहता है और हम जब स्कूल में पढ़ते थे, तभी सिखाया जाता है कि जो सरल example है, वो पहले solve करो, तो उसी से हम पले-बढ़े हैं, इसलिए कठिन example की तरफ कोई जाएगा नहीं लेकिन अब सोच बदलन की आवश्यकता है और ये आवश्यकता है कि हम इस बड़े mass को हम कैसे अपने में समेटें? हमारी विकास यात्रा का वो हिस्सा कैसे बने? उसके लिए हमारा रोडमैप क्या हो? अब मैं मानता हूँ कि हमारे सामने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति जिसका बैंक खाता खुला है, वो operational कैसे हो?

सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं। वो योजनाएं ऐसी हैं जो बैंक के route से ही आगे बढ़ने वाली हैं। बैंक के route से आगे बढ़ने वाली हैं, करने के बाद न हो इसके लिए क्या? ये योजना है। जिसमें प्रधानमंत्री जन-धन योजना और direct cash transfer की व्यवस्था और 8 हजार करोड़, मैं बताता हूँ कि, मैं ये आंकड़ा बताता नहीं हूँ, लेकिन अभी बताऊंगा कि political पंडित जरा निकाले कि कितनी extra subsidy जाती थी। जिसमें cylinder भी नहीं होता था, cylinder लेने वाला भी नहीं होता था लेकिन cheque फटता था। अब इस व्यवस्था से यानि transparency भी लाई जा सकती है। बैंकिंग व्यवस्था से इतना बड़ा reform हो सकता है तो शायद हमारे यहां सोचा नहीं गया था, आज हो रहा है और उस अर्थ में बैंक के लोगों के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि देश में transparency लाने में बहुत बड़ी भूमिका आज बैंकिंग सेक्टर ने करना शुरू किया है। ये भी हमें एक नया विश्वास पैदा करता है हमारे में, एक नई आशा को जन्म देता है।



कुछ बातें ऐसी हैं कि हम, आपने देखा होगा कि आपके बैंक में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, जितने भी लोग होंगे, उनको खुश रखने के लिए आपको कितनी मेहनत पड़ती है। हर काम की तारीफ करनी पड़ती है, हर बार लेकिन आपको जो वर्ग 4 का कर्मचारी है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। सुबह-शाम ऐसे, चलो भई ठीक हो? बस वो दिन-भर दौड़ता रहता है, ये आपका अनुभव होगा। आपके ड्राइवर को इतना पूछ ले, अरे यार तुम्हारे बेटे की exam है, फिर भी तुम आज नौकरी पर आए? बस उसका जीवन धन्य हो जाता है अरे! मेरे बेटे की exam है और मेरे boss ये भी याद रखते हैं। आपने देखा होगा गरीब को बस इतना सा चाहिए। आपका नंबर 2, नंबर 3, आपका नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 उसको दौड़ाने के लिए आपका पसीना छूट जाता है। उस गरीब को दौड़ाने के लिए सिर्फ दो शब्द काफी होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो जिसको हमने चौथी पायदान पर रखा हुआ है। उसके डीएनए में वो कौन सी चीज है, जो इतना बड़ा परिणाम देती है, आपके लिए risk लेती है, रात भर सोता नहीं है। जो वो आपके लिए करता है, वही वो देश के लिए भी कर सकता है। ये गरीब जो है, उसको थोड़ा सहारा चाहिए। जो आपके व्यक्तिगत जीवन में परिणाम देता है, वही गरीब राष्ट्र जीवन में परिणाम दे सकता है। जब तक intellectual इस चीज को हम convince नहीं होंगे, जब तक ये हमारा article of faith नहीं बनेगा और हमारी रोजमर्रा की घटनाओं को मैं जिस नजरिए से कह रहा हूँ, उस नजरिए से नहीं देखें, तब तक inclusion एक programme बनेगा, inclusion स्वभाव नहीं बनेगा।

मुझे inclusion programme नहीं, inclusion स्वभाव बनाना है और एक बार आप सोचिए फिर आपका आनंद कुछ और होगा। आपने देखा होगा जो women self-help group को जो पैसा देता है बैंक, आप उनमें से किसी का भी interview ले लीजिए, 100 लोगों को सर्वे करा लीजिए, वो आपको बताएंगे कि women self-help group में जो महिलाएं हैं, गरीब से गरीब हैं लेकिन अगर उसको बुधवार को 100 रुपया वापस करना है तो मंगल को आकर दरवाजा खटखटाती है कि मेरे 100 रुपए ले लो। आप देखिए इतनी बड़ी ताकत है, इस ताकत को हम राष्ट्र के विकास में कैसे जोड़े? मुझे विश्वास है, अब जो माहौल बना है और वो परिणाम बहुत बड़ा देंगे। अभी हम जो मुद्रा बैंक का concept आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आगे एक mobile banking के रूप में ही evolve हो जाए। इस देश में गरीब सवा 5 करोड़ से ज्यादा ऐसे छोटे-छोटे लोग हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं और आज finance की जो स्थिति देखें तो average इन लोगों का 17 thousand rupees से ज्यादा कर्ज नहीं है। Only 17 thousand rupees, Only 17 thousand rupees के कर्ज से वो किस प्रकार से economy को drive कर रहा है, कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, GDP में कितना बड़ा contribution कर रहा है।

अगर ये 5-6 करोड़ लोग हैं। जो कोई सब्जी बेचता होगा, दूध बेचता होगा, अखबार बेचता होगा, छोटे लोग हैं। उनको क्या चाहिए? हजार रुपया, दो हजार रुपया, पांच हजार रुपए, उसको कुछ नया करने की ताकत आएगी। सुबह अखबार बेचता है, अगर दो हजार रुपया है तो दोपहर को गुब्बारे बेचने जाएगा, शाम को बर्फ की लॉरी चला लेगा। वो अपना दिन भर में चार प्रकार के काम करके, अपनी income को 2 हजार से 20 हजार तक ले जाएगा और देश की economy को drive कर देगा और 6 लोगों को रोजगार देने की उसकी ताकत होगी। क्या हम उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं क्या? हम हमारा किसान आत्महत्या करता है ये दर्द सिर्फ अखबारों के पन्नों पर और टीवी स्क्रीन पर नहीं होना चाहिए? ये हमारा किसान जब मरता है क्या बैंकिंग सेक्टर के हृदय को हिला देता है? साहूकार से पैसे लेने के कारण कभी-कभी उसको मरने की नौबत आ जाती है। 60 साल के बाद हम आज 80 साल मना रहे हैं आरबीआई के तब, हमारे दिल में ये आवाज उठ सकती है कि भई हम हमारी बैंकिंग व्यवस्था के हाथ इतने पसारेंगे कि किसान को कम से कम कर्ज के कारण आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी? क्या ये सपना हमारा नहीं हो सकता है?

मैं नहीं मानता हूँ कि इसके कारण कोई बैंक डूब जाएगी? हम कभी ये तो सोचते हैं कि कोई कंपनी हमारे पास आए और वो कहे कि भई हमारा जो factory है, हम उसकी technology upgrade करना चाहते हैं, हम environment friendly technology लाने वाले हैं, carbon emission कम करने वाली लाने वाले हैं, हमें बैंक से इतना पैसा चाहिए। हम खुशी से देते हैं कि नहीं देते? हमारे brochure में भी छापते हैं कि हमने carbon emission कम करने वालों को इतना-इतना initiative किया, बड़ा गर्व करते हैं लेकिन कोई किसान आकर के कहे कि मुझे 50 पेड़ लगाने हैं, मुझे बैंक की लोन दो। मुझे बताइए carbon emission के लिए ये बहुत बड़ी-बड़ी से फैक्ट्री लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? लेकिन मुझे, मेरे तराजू में वो तो है, लेकिन ये नहीं है। क्या हमारा बैंकिंग सेक्टर आप देखिए हम timber import करते हैं, किसान मर रहा है। अगर हम initiative लें, एक नई योजना बना सकते हैं कि हमारे देश में जो marginal farmer है, उसकी ज्यादा जमीन एक खेत और दूसरे खेत demarcation में जो ज्यादा जगह जाती है, उसमें वो बाड़ लगा देता है, इतना wastage है। भारत जैसे देश को ये जमीन बर्बाद होने की चिंता करने की आवश्यकता है। उसकी दिशा में कोई ध्यान नहीं देता है लेकिन हम बैंकिंग के द्वारा initiative लें कि भाई जो demarcation का जो तुम्हारा border है वहां अगर तुम पेड़ लगाते हो तो हम तुम्हें इतना finance करेंगे और ये पेड़ तुम्हारी मालिकी बनेगा और चलकर के हमारी partnership होगी, तुम्हारी बेटी की शादी होगी और चार पेड़ काटने होंगे, टिम्बर के रूप में बेचना होगा तो बैंक को इतना पैसा देना, तो मुझे बताइए कि होगा कि नहीं होगा?

हम carbon neutral development की दिशा में हमारा contribution होगा कि नहीं होगा और जिस किसान की फसल तो बर्बाद हो जाएगी, लेकिन पेड़ खड़ा होगा तो उसको लगेगा, अभी तो मेरी कोई छाया है, मैं जिंदगी में मरने की जरूरत नहीं है, ये पेड़ के सहारे मैं फिर से एक नई जिंदगी खड़ी कर दूंगा। विश्वास पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें समाज के भिन्न-भिन्न तबके और बड़े creative mind के साथ हम किस प्रकार से finance की व्यवस्था करें, जिसके कारण वो एक long term stability के लिए फायदा कर सके। हम उस एक नए तरीकों को कैसे सोचें? जिस प्रकार से finance inclusion में immediately हमारा दो चीजों पर ध्यान जाता है।

एक आर्थिक layer income के आधार पर, रहन-सहन के आधार पर दूसरा सामाजिक ताने-बाने, जाति-प्रथा का थोड़ा प्रभाव रहता है लेकिन inclusion में एक नए parameter की ओर देखने की जरूरत है और वो है geography inclusion। आज भी देश में देखिए हमारी economy को और ये हम सबने सोचना चाहिए। गोवा हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, देश का पश्चिमी छोर वहां तो आर्थिक गतिविधि दिखती है लेकिन जो देश का पूरब का छोर, जिसके पास सर्वाधिक प्राकृतिक संपदा है, वहां आर्थिक गतिविधि नहीं है। हमारे financial inclusion के model में, मैं देश के पश्चिमी छोर पर तो हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी बैंक व्यवस्था सबसे ज्यादा काम कर रही है लेकिन पूरब का इलाका जहां पर इतनी बड़ी प्राकृतिक संपदा पड़ी हुई है, जहां पर इतना सामर्थ्यवान मनुष्यता का बल है, मैं उसके विकास के लिए क्या करूंगा? इसलिए हमारे geographical inclusion आवश्यकता है, वो कौन से इलाके हैं जिसमें Potential है लेकिन हमारी reach नहीं है, हमारे inclusion में जिस प्रकार से समाज के भिन्न-भिन्न तबकों की ओर देखने की आवश्यकता है उसी प्रकार से भारत के भिन्न-भिन्न भू-भाग की ओर देखने की आवश्यकता है कि वो कौन सा भू-भाग है? कि जिसमें सामर्थ्य है लेकिन अवसर पैदा नहीं हुआ है और विकास करना है तो उसकी परंपरागत ताकत को सबसे पहले पहचानना पड़ता है। क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था में district को अगर एक block माने तो हमारे पास मैपिंग है क्या? कि भई वहां का Potential ये है, un-potential इतना है, tap करना है तो इतना। सरकार और बैंकिंग व्यवस्था मिलकर सोचें कि आप raw material के लिए decision ले लीजिए, आप human development resources के लिए कोई decision ले लीजिए, आप manager skill के लिए कोई decision ले लीजिए, आप वहां पर energy supply करने के लिए कर लीजिए, आप infrastructure के लिए कर लीजिए, banks are ready, हम यहां के नक्शे को बदल देंगे।

Inclusion में हमने, हमारे देश के विकसित इलाके, विकास की संभावना वाले इलाके, विकास से वंचित रहे गए इलाके इनके सारे parameter बनाकर के हमारे inclusion के मॉडल में इसको कैसे प्रतिस्थापित करें? मैं समझता हूं कि अगर ये हम करेंगे, तो बहुत है। भारत को दुनिया में आर्थिक ताकत की ओर बढ़ना है। 3 साल का बच्चा, 6 साल का होता है तो उसकी ऊंचाई बढ़ने में फर्क तुरंत आता है कि पहले वो दो फुट का था, अभी वो चार फुट का हो गया लेकिन 20 साल वाले को चार साल बाद भी दो इंच बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। आप जहां बढ़ चुके हैं, वहां बढ़ने की गति धीरे रहेगी लेकिन जहां कुछ नहीं है वहां थोड़ा सा डालने से बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो एक नए Confidence को जन्म देगा और आज विश्व में भारत के next 10 year के growth rate की जो चर्चा हो रही है, उसका potential यही है।

हिंदुस्तान की second green revolution करने की जगह अगर कहीं है तो हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका है। हिंदुस्तान के mines और mineral में अभी हमने जो decision लिए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के सभी धनी राज्य बनने की संभावना, जिनके पास कोयला था वो राज्य बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, ये राज्य एक नई ताकत के साथ उभरने वाले हैं। क्या हम बैंकिंग सेक्टर के लोगों को ध्यान है? कि भई इतना बड़ा वहां कल्पना भर का एकदम से Jump आया है, हम बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा वहां कैसे बदलाव लाएं? अगर हम इस बात को करेंगे, मैं मानता हूं कि परिणाम बहुत प्राप्त होंगे। एक और क्षेत्र है, जिसको भी मैं financial inclusion का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूं, जिसका संबंध न आर्थिक स्थिति से है, न सामाजिक स्थिति से है और न ही इसका संबंध भौगोलिक परिस्थिति से है और वो है Knowledge में हम financial partnership कैसे बनें?

हमारे देश को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 65 percent population, 35 से नीचे है। ये 35 से नीचे का जो population है, हमारी जो young generation है, उसे या तो skill चाहिए या Knowledge चाहिए। आज जो वर्तमान intuition हैं, उससे उसको जो प्राप्त होता है, globally competitive बनने के लिए कुछ कमी महसूस होती है। अब हम globally competitive knowledge institution लाते हैं तो हमारे देश के नौजवान के लिए वहां पढ़ना कठिन है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। क्या बैंक एक ऐसा mediator बन सकती हैं? कि कितना fee वाली institution क्यों न हो? गरीब से गरीब का बच्चा भी वहां पढ़ने जाएगा, हम खड़े हैं। हम ज्ञान उपार्जन के प्रयास में कभी पीछे नहीं हटेंगे। गरीब का बच्चा भी कितना ही धन खर्च करके अगर पढ़ाई करने ताकत रखता है, हम पूरा करेंगे। मैं समझता हूं कि लंबे समय के लिए benefit करने वाला ये सबसे बड़ा investment है, सबसे बड़ा financial inclusion है और इसलिए हम हमारी education system, हमारे students उनका अच्छे intuition में पढ़ने का इरादा और उसको, अगर हमारा human resource

development की ताकत जितनी ज्यादा होगी, देश को आने वाली शताब्दी में नेतृत्व करने की ताकत आएगी। हमारी इमारतें कितनी अच्छी बनीं हैं, इससे दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ने वाली नहीं है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ने वाली है, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी के पास कितना सामर्थ्य है, कितना ताकत है इनके अंदर, उस ताकत का आधार दंड-बैठक से नहीं आता है, उस ताकत के लिए ये शिक्षा का अवसर होना चाहिए।

अगर कोई educational institution world class बनाता है, बैंक मदद करें, student पढ़ने के लिए जाना चाहता है, बैंक मदद करें और मैं विश्वास दिलाता हूँ जी। अब तक का आपका जो NPA का अनुभव है, इसमें कभी ऐसा कटु अनुभव नहीं आएगा, मुझ पर भरोसा कीजिए। देश का नौजवान पाई-पाई लौटा देगा, लौटाएगा लेकिन देश बहुत आगे बढ़ेगा और इसलिए हम financial inclusion एक सब्जी बेचने वाले से लेकर के एक top class, high qualified man power तैयार करने तक पूरा chain कैसे बनाएं? मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा role कर सकते हैं और एक विषय मेरे मन में है। Make in India, मैं Make in India की विस्तार में और बातें नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पूरा ज्ञान भी नहीं है शायद सोचा जाए। हम आज आरबीआई के 80 साल मना रहे हैं। आज हम संकल्प कर सकते हैं क्या? कि फलां तारीख को जो हमारी currency छपेगी, उस currency का कागज भी Indian होगा और Ink भी Indian होगी। ऐसा नहीं चल सकता, जिस गांधी ने स्वदेशी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, वो विदेशी कागज पर उसकी तस्वीर छपती रहे, वो शोभा देता है क्या? क्या मेरे देश के पास ऐसे उद्योग कार नहीं हैं? उनको compel किया जाए कि ये फैक्ट्री लगानी है, पैसा नहीं है, दूंगा लेकिन ये लगाओ बगल में, लाओ दुनिया से technology लाओ और हमारी currency हमारी नोट, कागज हिंदुस्तानी होना चाहिए, ईक भी हिंदुस्तानी होनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आरबीआई इस बात को समझकर के एक नेतृत्व दे, ये Make in India तो यहीं से शुरू होता है जी।

मैं मानता हूँ कि हम इन चीजों को कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि देश आज जहां पहुंचा है, उसमें आप सबका बहुत योगदान है, इन institutions का बहुत योगदान है और वो इंसान हूँ, मैं मानता हूँ कि idea कितने ही होनहार क्यों न हो? अगर institutional frame ताकतवर नहीं हैं तो सारे विचार बाँझ रह जाते हैं और इसलिए institutional strengthen हो, आरबीआई की गरिमा और कैसे बढ़े? बैंकिंग सेक्टर की अपनी गरिमा कैसे बढ़े? सभी संस्थाएं अपने आप में ताकतवर कैसे बनें? जितना संस्थाओं का नेटवर्क ताकतवर होगा, स्वतंत्र रूप से निर्णय करने का होगा, ultimately देश का लाभ होने वाला है। जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार देश चलना चाहिए, देश आपने जिन values को स्वीकार किया है उन values के अनुसार चलेगा और देश आगे बढ़ेगा। ये मेरा विश्वास है और उस बात को लेकर के हमको चलना चाहिए।

हमने एक छोटा सा initiative लिया देखिए देश की ताकत देखिए। कभी-कभी हम अपने देशवासियों को कुछ भी कह देते हैं, मेरा अनुभव अलग है। हमने ऐसे ही कानों-कानों में एक बात शुरू की थी कि भई जो लोग afford करते हैं, इन लोगों ने gas subsidy नहीं लेनी चाहिए। अब जो लेते थे, वो कोई सरकार से 500 रुपया मिलने वाले थे, भूखे नहीं रहते थे लेकिन ध्यान नहीं था, ऐसा चलता है यार, ध्यान नहीं था। सहज रूप से हमने बातों-बातों में कहा, मैंने कहीं publically रूप से नहीं कहा था और मैं हैरान था, मैं सचमुच में हैरान था, 2 लाख लोगों ने voluntarily अपनी gas subsidy surrender कर दी। कानों-कानों पर बात पहुंची, ये देखकर के मेरा विश्वास बढ़ा तो मैंने अभी officially मैंने पिछले हफ्ते launch किया कि जो भाई afford करते हैं, उन्होंने gas subsidy को surrender करना चाहिए और सरकार का इरादा subsidy बचाकर के तिजोरी भरने का नहीं है, हमारे इरादे ये हैं कि आप अगर एक सिलेंडर छोड़ते हो, तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूँ, जिसमें लकड़ी का चूल्हा है और जिसके कारण pollution होता है और जिसके कारण उनके बच्चों को धुएँ में पलना पड़ता है और बीमारी का घर हो जाता है। मैं financial inclusion की जब बात करता हूँ तब आप जिस गैस सिलेंडर को छोड़ें, वो उस गरीब के घर में सिलेंडर जाएं ताकि उस महिला को लकड़ी जलाकर के धुएँ में अपने बच्चों को पालने की नौबत न आए। मुझे बताइए ये सेवा नहीं है क्या?

मैं विश्वास करता हूँ कि सभी हमारे बैंक अपने सभी कर्मचारियों को विश्वास में लें, एक-एक बैंक resolve करे कि हमारे बैंक के 20 हजार कर्मचारी हैं, हम subsidy छोड़ देंगे, सारे industrial house decide करें कि हमारे यहां जो 5 हजार employee हैं, हम subsidy छोड़ देंगे और इसका मतलब ये नहीं कि वो industry उनको पैसे दे, ये मैं नहीं चाहता। voluntarily देना यानि देना, हर व्यक्ति को। अगर हिंदुस्तान में हम एक करोड़ लोग ये गैस सिलेंडर की subsidy छोड़ दें इतनी ताकत रखते हैं। एक करोड़ गरीब परिवारों में जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है, जिसके कारण जंगल कटते हैं, जिसके कारण carbon emission होता है, जिसके कारण गरीब के बच्चे को धुएँ में पलना पड़ता है, financial inclusion हर छोटी चीज में संभव होता है। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने vision से ये संभव होता है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत आभारी हूँ, मैंने काफी समय ले लिया।

लेकिन मुझे विश्वास है मैंने पहले ही कहा था मेरे ये software नहीं है, मैं इस क्षेत्र का नहीं हूँ लेकिन मैं जिस बिरादरी में

पैदा हुआ हूँ, गरीबी मेंने देखी है और गरीब की गरीबी से बाहर निकलने की ताकत है। थोड़े hand holding की आवश्यकता है, थोड़ा सा hand holding करने की ताकत, बैंकिंग सेक्टर के पास है। आइए हम सब मिलकर के देश को गरीबी से मुक्त कराने के अभियान को, financial inclusion के इस mission से आगे बढ़ें।

मेरी आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।

\*\*\*\*\*

अमित कुमार / सुरेन्द्र कुमार / मुस्तकीम खान

**पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय**

01-अप्रैल-2015 17:00 IST

**राउरकेला स्टील प्लांट के 45 लाख टन विस्तार को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद आयोजित जनसभा को दिए गये  
प्रधानमंत्री जी के भाषण का मूल पाठ**

जय जगन्नाथ, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव। आजी पवित्र उत्कल दिवस, ओडिशा प्रतिष्ठा दिवस, समस्त ओडिशावासिन को ए अवसरे मोर अभिनंदन।

आज यह मेरा सौभाग्य है कि उत्कल दिवस के पावन अवसर पर मुझे जगन्नाथ जी की धरती पर आने का सौभाग्य मिला। इस उड़ीसा को बनाने के लिए, अनेक लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, साधना की और आज उत्कल दिवस पर मैं विशेष रूप से उत्कल मणि पंडित गोपबंदु दास को प्रणाम करता हूँ। उत्कल के गौरव मधुसुधन दास को नमस्कार करता हूँ। वीर सुरेंद्र साई को प्रणाम करता हूँ और महाराज कृष्णा चंद्र गजपति जी को मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूँ। यह बीरसा मुंडा की भी, क्रांति जोत से प्रज्वलित धरती है, मैं बीरसा मुंडा को भी प्रणाम करता हूँ और आधुनिक ओडिशा बनाने के लिए बीजू बाबू को हर ओडिशा वासी हमेशा याद करता हूँ। मैं इन सभी महानुभाव को और ओडिशा की जनता को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और मैं आज के ओडिशा दिवस पर ओडिशावासियों को हृदय से बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभिनंदन करता हूँ और ओडिशा विकास की नई ऊंचाईयों को पार करे। ओडिशा के नौजवानों का भविष्य ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, सामर्थवान हो, राष्ट्र के कल्याण में ओडिशा की नई पीढ़ी अपना अमूल्य योगदान देने के लिए उसको अवसर मिले।

उड़ीसा का किसान हो, उड़ीसा का मजदूर हो, उड़ीसा का मेरा मछुआरा भाई हो या उड़ीसा का आदिवासी हो। ये वो धरती हो। जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है, सम्मान करता है। यहां का सूर्य मंदिर आज भी हिंदुस्तान को प्रकाश दे रहा है, एक नई आशा का संचार करता है। ऐसी इस पवित्र भूमि को मैं आज नमन करता हूँ।

मैं पिछले वर्ष, अप्रैल महीने के पहले सप्ताह राउरकेला की धरती पर आया था। शायद 4 अप्रैल को आया था और आज एक साल के भीतर-भीतर, दोबारा मैं आपके बीच आया हूँ। मैं पिछले वर्ष आया था तब आपके सपनों को समझना चाहता था, आपकी आशा, आकांक्षाओं को समझना चाहता था। आज, जब मैं आया हूँ तो मेरा एक साल का हिसाब देने के लिए आया हूँ और लोकतंत्र में ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जनता-जर्नादन को हमारे काम का हिसाब दें। पल-पल का हिसाब दें, पाई-पाई का हिसाब दें। भाईयों-बहनों, ये राउरकेला एक प्रकार से लघु भारत है। हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है जो राउरकेला में बसता नहीं है। राउरकेला में कुछ भी होता है, हिंदुस्तान पूरे कोने में उसका तुरंत vibration पहुंच जाता है और भारत के किसी भी कोने में कुछ भी क्यों न हो पल दो पल में राउरकेला में पता चल जाता है कि हिंदुस्तान के उस कोने में ये हुआ है। इतना जीवंत नाता संपूर्ण भारत के साथ, इस धरती का नाता है। यहां के लोगों का नाता है। एक प्रकार से राउरकेला को बनाने में भारत को इस्पात की ताकत देने में ये लघु भारत में, राउरकेला का बहुत बड़ा योगदान है।

भारत को एक करने का काम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और आजादी के बाद किसी शहर ने भारत को इस्पात की ताकत दी है तो वो शहर का नाम है राउरकेला। ये बज्र सा सामर्थ्य दिया है और जहां से बज्र सा समर्थ्य मिलता है, वो राष्ट्र कभी भी पीछे नहीं हटता है। विकास की नई ऊंचाईयों को पार करता जाता है। यहां पर डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कई वर्षों पहले इस्पात के कारखाने की नींव डाली। यहां का जो मजदूर होगा, वो भी ये सोचता होगा कि मैं खनिज में से, आयरन में से मिट्टी जैसा जो लग रहा है, उसको कोशिश करके मैं स्टील तैयार करता हूँ, मजबूत स्टील तैयार करता हूँ, अच्छा स्टील तैयार करता हूँ लेकिन राउरकेला के मेरे भाईयों-बहनों आप सिर्फ प्लेट नहीं बनाते। आप सिर्फ इतनी चौड़ाई इतनी मोटाई, इसकी सिर्फ प्लेट का निर्माण नहीं करते हैं। आप जो पसीना बहाते हैं, आप जो मेहनत करते हैं, उस भंयकर गर्मी के बीच खड़े रहकर के, आप अपने शरीर को भी तपा देते हैं। सिर्फ स्टील की प्लेट नहीं पैदा करते हैं आप भारत की सैन्य शक्ति में, भारत की सुरक्षा शक्ति में एक अबोध ताकत पैदा करते हैं, एक बज्र की ताकत पैदा करते हैं।

आज भारत सामुद्रिक सुरक्षा में indigenous बनने का सपना लेकर के चल रहा है। हमारे युद्धपोत हमारे देश में कैसे बने इस पर आज भारत का ध्यान है। लेकिन यह युद्धपोत इसलिए बनना संभव हुआ है, क्योंकि राउरकेला में कोई मजदूर

भारत की सुरक्षा के लिए गर्मी के बीच खड़े रहकर के अपने आप को तपा रहा है, तब जाकर के भारत की सुरक्षा होती है, तब जाकर के युद्धपोत बनते हैं, तब जाकर के यहां बनाया, पकाया स्टील भारत की सुरक्षा के लिए काम आता है। दुश्मनों की कितनी ही ताकत क्यों न हो, उन ताकतों के खिलाफ लोहा लेने का सामर्थ्य हमारे सेना के जवानों में तब आता है, जब वो एक मजबूत टैंक के अंदर खड़ा है और दुश्मन के वार भी झेलता है और दुश्मन पर वार भी करता है। वो टैंक भारत में तब निर्माण होती है, जब राउरकेला में मजबूत स्टील तैयार होता है और इसलिए मेरे प्यारे भाईयों-बहनों दूर हिमालय की गोद में देश की सेना का जवान किसी टैंक पर खड़े रहकर के मां भारती की रक्षा करता है तो उसके अंदर आप के भी पुरुषार्थ की महक होती है। तब जाकर के राष्ट्र की रक्षा होती है और उस अर्थ में यह स्टील उत्पादन का काम राष्ट्र की रक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है।

यह स्टील उत्पादन का काम न सिर्फ ओडिशा के आर्थिक जीवन को, लेकिन पूरे देश के आर्थिक जीवन में एक नई ताकत देता है। इस पिछड़े इलाके में यह उद्योग के कारण रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। यहां के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए रोजी-रोटी का अवसर उपलब्ध हुआ है और आने वाले दिनों में उसके विकास के कारण और अधिक रोजगार की संभावनाएं होंगी। विकास के और नए अवसर पैदा होने वाले हैं।

आज इस प्रोजेक्ट का Expansion हो रहा है और Expansion भी दो-चार कदम नहीं, एक प्रकार से उसकी ताकत डबल होने जा रही है। इस ताकत के कारण देश के इस्पात की क्षमता में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। देखते ही देखते हिंदुस्तान ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है इस्पात के उत्पादन में। लेकिन अभी भी हम चाइना से काफी पीछे हैं और जब मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूं, तो हमें किसी के पीछे रहना मंजूर नहीं। हमें उसमें आगे बढ़ना है। देश, 65% नौजवानों से भरा हुआ देश है। भारत मां की गोद में 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवान मां भारती की गोद में पल रहे हैं, खेल रहे हैं। कितनी बड़ी ताकत है हमारे पास। उनको अगर अवसर मिलेगा, उन्हें अगर रोजगार मिलेगा, उनको अगर सही Skill Development होगा, तो यह हमारे नौजवान पिछले 60 साल में हिंदुस्तान जहां आ पहुंचा है 10 साल में उससे तेज गति में आगे ले जाएंगे, यह मुझे मेरे नौजवानों पर पूरा भरोसा है।

और इसलिए भाईयों-बहनों देश का औद्योगिक विकास हो। भारत के अंदर जो खनिज संपदा है। ये कच्चा माल विदेशों में भेजकर के, ट्रेडिंग करके, पेट भरकर के हमें गुजारा नहीं करना चाहिए। हमारी जो खनिज संपदा है। वो कच्चा माल, दुनिया के बाजार में बेचने से पैसा तो मिल जाएगा। ट्रेडिंग करने से अपना परिवार भी चल जाएगा। पांच-पचास लोगों का पेट भी भर जाएगा लेकिन भारत का भविष्य नहीं बनेगा और इसलिए हमारी कोशिश है कि भारत के पास जो कच्चा माल है, भारत के पास जो खनिज संपदा है। खान-खनिज में हमारा जो सामर्थ्य है। उसमें Value addition होना चाहिए, उसका Processing होना चाहिए, उसकी मूल्य वृद्धि होनी चाहिए और उसमें से जो उत्पादित चीजें हो, वो विश्व के बाजार में उत्तम प्रकार की चीजों के रूप में जाएगी तो भारत की आर्थिक संपन्न ताकत भी अनेक गुना बढ़ेगी और इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे देश में जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की जाल बिछाई जाए। नौजवानों को अवसर दिया जाए, बैंकों से धन उनके लिए उपलब्ध कराया जाए और देश में एक नई औद्योगिक क्रांति की दिशा में प्रयास हो।

भाईयो-बहनों एक समय था, भारत की ओर कोई देखने को तैयार नहीं था। पिछला एक दशक ऐसी मुसीबतों से गुजरा है कि जिसके कारण पूरे विश्व ने हमसे मुंह मोड़ लिया था लेकिन आज भाईयो-बहनों, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि 10 महीने के भीतर-भीतर निराशा के बादल छंट गए, आशा का सूरज फिर से एक बार आसमान के माध्यान पर पहुंचा है और पूरे विश्व का ध्यान आज हिंदुस्तान के अंदर पूंजी निवेश की ओर लगा है। रेल हो, रोड हो, गरीबों के लिए घर हो, उद्योग हो, कारखाने हो, दुनिया के लोगों का ध्यान आज हिंदुस्तान की तरफ आया है और हम इस अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं। हम विश्व को निमंत्रित करना चाहते हैं। आइए आप अपना नसीब आजमाइए। भारत की धरती उर्वरा है। यहां पर जो पूंजी लगाएगा, दुनिया में उसको कहीं जितना Return मिलता है, उससे ज्यादा Return देने की ताकत इस धरती के अंदर है और इसलिए मैं विश्व को निमंत्रित करता हूं और उस इलाके में करना चाहे।

मैं बेमन से कह रहा हूं कि भारत का विकास सिर्फ हिंदुस्तान के पश्चिम छोर पर होने से, भारत का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र आगे बढ़े, गुजरात आगे बढ़े, गोवा आगे बढ़े, राजस्थान आगे बढ़े, हरियाणा आगे बढ़े, पंजाब आगे बढ़े, इससे काम नहीं चलेगा। वो बढ़ते रहें और बढ़ते रहें, लेकिन देश का भला तो तब होगा, जब उड़ीसा भी आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ बढ़े, बिहार आगे बढ़े, पश्चिम बंगाल आगे बढ़े, आसाम आगे बढ़े, पूर्वी उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा देखिए। पूर्वी भारत का इलाका, ये भी उतना ही आगे बढ़ना चाहिए, जितना की हिंदुस्तान का पश्चिमी किनारा आगे बढ़ा है और इसलिए भाईयो-बहनों मेरा पूरा ध्यान इस बात पर है कि भारत का पूर्वी इलाका उड़ीसा से लेकर के पूर्वी इलाका ये कैसे सामर्थ्यवान बने। कैसे विकास की यात्रा में भागीदार बने इसलिए सरकार की सारी योजनाएं विकास की उस दिशा में ले जाने का हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है।

अब तक ये परंपरा रही दिल्ली वाले, दिल्ली में बैठने वाले ऐसे अहंकार में जीते थे कि राज्यों को वो छोटा मानते थे, नीचा मानते थे। हमने इस चरित्र का बदलने का फैसला किया है। ये परंपरा मुझे मंजूर नहीं है। केंद्र हो या राज्य हो बराबरी के भागीदार है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। कोई देने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, दोनों मिलकर के आगे बढ़ने वाले पार्टनर है, उसी रूप में देश को चलाना है और इसलिए हमने कोपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही है। भाईयों-बहनों राज्यों ने हमसे कुछ मांगा नहीं था। लेकिन हम मानते थे, क्योंकि मैं खुद अनेक वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा हूं और देश में पहली बार लम्बे अर्से तक रहा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है और इसलिए उसको मुख्यमंत्री की तकलीफें क्या होती है, राज्य की मुसीबतें क्या होती है। उसकी भली-भांति समझ है। मैं दिल्ली में बैठकर के भी ओडिशा के दर्द को भली-भांति समझ सकता हूं, पहचान सकता हूं, क्योंकि मैंने राज्य में काम किया है। एक जमाना था, यहां का खनिज खदानें आपके पास, लेकिन रोयल्टी के लिए दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे। हमारी सरकार बनने के कुछ ही दिनों में हमने निर्णय कर लिया। कई वर्षों से जो रोयल्टी का मामला अटका था, उसका निपटारा कर दिया और रोयल्टी में हमने बढ़ोतरी कर दी, क्योंकि हम मानते हैं अगर धन राज्यों के पास होगा, तो राज्य भी विकास के लिए पीछे नहीं हटेंगे और इसलिए हमने इस काम को किया।

भाईयों बहनों Finance Commission के द्वारा राज्यों को पैसे दिये जाते हैं। पिछले वर्ष ओडिशा को भारत सरकार की तरफ से Finance Commission ने करीब 18 हजार करोड़ रुपया दिया था। भाईयों बहनों हमने आते ही 60 साल में पहुंचते-पहुंचते 18 हजार करोड़ पहुंचा था। हमने एक ही पल में 18 हजार करोड़ का 25 हजार करोड़ कर दिया, 25 हजार करोड़। अगर राज्य आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। राज्य मिलजुलकर के प्रगति करेंगे तो देश प्रगति करेगा। इस मंत्र को लेकर के हम आगे चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से एक के बाद एक भारत सरकार ने विकास के नये आयामों को छूने का प्रयास किया है। जो राज्य Progressive होगा, जो राज्य लम्बे समय की योजनाओं के साथ इस धन का उपयोग करेगा, वो राज्य हिंदुस्तान में नंबर एक पहुंचने में देर नहीं होगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। अब जिम्मेवारी राज्यों की बनती है कि वे विकास के मार्ग तय करें, Infrastructure पर बल लगाएं। तत्कालीन लाभ वाला कार्यक्रम नहीं लम्बे समय के लिए राज्य को ताकत देने वाला कार्यक्रम हाथ में लें आप देखिए आने वाली पीढ़िया सुखी हो जाएगी और ओडिशा में वो ताकत पड़ी है। स्वर्णिम इतिहास रहा है, स्वर्णिम काल रहा है उडिया का। फिर से एक बार वो स्वर्णिम काल आ सकता है, उडिया का और मैं साफ देख रहा हूं वो अवसर सामने आकर के खड़ा है। भाईयों और बहनों आप जानते हैं।

कभी ओडिशा के लोगों को लगता होगा कि हमारा ऐसा नसीब है कि कोयले की काली मां हमारे पर छाई हुई है। कुछ मिलता नहीं था। कोयला बोझ बन गया था, आज कोयले को हमने हीरा बना दिया, हीरा बना दिया भाई, कोयले की खदानों का Auction किया, जो कोयले को हाथ लगाने से लोग डरते थे, आज उस कोयले को हीरे में प्रवर्तित करने का हमने काम किया। जब CAG की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि कोयले की खदानों की चोरी में देश के खजाने का एक लाख 76 हजार करोड़ रुपया लूट लिया गया है। मैं पिछले अप्रैल में मैंने भाषण में यह कहा था, तब मुझे कई लोग कहते थे कि साहब एक लाख 76 हजार नहीं होगा, थोड़ा बहुत लिया होगा, लेकिन इतना नहीं लिया होगा। कई लोग कहते थे साहब एक लाख 76 हजार नहीं होगा। थोड़ा बहुत लिया होगा लेकिन इतना नहीं लिया होगा। कुछ लोग कहते थे। लोग कहते थे, तो मैं भी भई ज्यादा Argument नहीं करता था। CAG ने कहा है लेकिन भाईयों-बहनों सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार में दे दी गई 204 Coal mines को, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये चोर-लूटेरे की जो बंटवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने लाल आंख दिखाई। 204 कोयले की खदानें रद्द हो गईं। हमने तय किया। हम Transparent पद्धति से Auction करेंगे, नीलामी करेंगे, दुनिया के सामने खुलेआम नीलामी करेंगे, मीडिया के लोगों की हाजिरी में नीलामी करेंगे और मेरे भाईयों-बहनों 204 में से अभी सिर्फ 20 की नीलामी हुई है, ज्यादा अभी बाकी है सिर्फ 20 की और आपको मालूम है, जिन 204 खदानों से हिंदुस्तान की तिजोरी में एक रुपया नहीं आता था। सिर्फ 20 की नीलामी से दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम सरकार के खजाने में आई है और ये पैसे दिल्ली के खजाने में जमा नहीं करेंगे। जिन राज्यों में कोयले की खदानें हैं, ये पैसे उनके खजाने में जाएंगे। उड़ीसा के खजाने में जाएंगे, छत्तीसगढ़ के खजाने में जाएंगे, झारखंड के खजाने में जाएंगे। राज्य में ताकत आएगी। भाईयों-बहनों, ईमानदारी के साथ अगर काम करें तो कितना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। ये उदाहरण आपके सामने है।

ये लोग जिम्मेवार नहीं हैं क्या? क्या उन्हें जवाब देना नहीं चाहिए? ये दो लाख करोड़ रुपया 20 खदानों का आया कहां से? तो पहले पैसे गया कहां था? भाईयों-बहनों मैंने आपको वादा किया था। दिल्ली में आप अगर मुझे सेवा करने का मौका देंगे तो ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा ताकि मेरे देशवासियों को माथा नीचे कर करके जीना पड़े और आज मैं सीना तानकर के आपके सामने हिसाब देने आया हूं, 10 महीने हो गए सरकार को एक दाग नहीं लगा मेरे भाईयों बहनों, एक दाग नहीं लगा मेरे भाईयों-बहनों। भाईयों-बहनों अभी हमने नए कानून पास किए। minerals के संबंध में कानून पास किया और मैं नवीन बाबू का आभारी हूं कि संसद में उन्होंने हमारा समर्थन किया तो राज्यसभा में भी वो बिल मंजूर होने में हमारी सुविधा हो

गई और हम मिलकर के देश हित के निर्णयों को करते चलेंगे और देश हित में हम काम करते जाएंगे।

भाईयों-बहनों में जब पिछली बार आया था तब तो मैं प्रधानमंत्री नहीं था लेकिन यहां के लोगों ने मेरे सामने एक मांग रखी थी। राजनीति का स्वभाव ऐसा है कि पुरानी बातें भुला देना, जितना जल्दी हो सके भुला देना लेकिन मेरे भाईयों-बहनों, मैं राजनेता नहीं हूं, मैं तो आपका सेवादार हूं। मुझे पुरानी बातें भुलाने में Interest नहीं है। मैं तो खुद होकर के याद दिलाना चाहता हूं और मैंने गत वर्ष 4 अप्रैल को इसी मैदान से, मैंने जो घोषणा की थी तब प्रधानमंत्री नहीं था। आपने प्रधानमंत्री बनाया और आज जब मैं पहली बार आया हूं, तो मैं उस वादे को पूरा करते हुए बताना चाहता हूं कि इस्पात General hospital, अब इस्पात General hospital, ये मेडिकल कॉलेज cum Super specialty Hospital के रूप में उसको विकसित करने का निर्णय भारत सरकार ने कर लिया है।

भाईयों-बहनों लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, कि इस अस्पताल में आपको कभी patient बनकर के जाना पड़े। मैं आप उत्कल दिवस पर आपको शुभकामना देता हूं कि अस्पताल तो हिंदुस्तान में बढ़िया से बढ़िया बने, लेकिन बारह महीने खाली रहे। कोई बीमार न हो, किसी के परिवार में मुसीबत न हो, किसी को अस्पताल जाना न पड़े। लेकिन यहां के मेडिकल कॉलेज से होनहार नौजवान तैयार हो करके देश के स्वास्थ्य के लिए भी तैयार हो। एक बात और भी हुई थी, ब्रह्मणी नदी पर दूसरा ब्रिज बनाने की। मैं आपकी कठिनाई जानता हूं। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ब्रह्मणी नदी पर दूसरे ब्रिज का काम भी कर दिया जाएगा और उसके कारण राउरकेला की connectivity कितनी बढ़ने वाली है इसका आपको पूरा अंदाज है भाईयों-बहनों।

भाईयों-बहनों आज मैं दूर से ही जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद ले रहा हूं, लेकिन पूरा ओडिशा और एक प्रकार से देश और दुनिया के जगन्नाथ के भक्त नव कलेवर के लिए तैयारी कर रहे हैं। कई वर्षों के बाद नवकलेवर आता है। पूरा ओडिशा पूरे विश्व का स्वागत करने के लिए सजग हो जाता है। रेल की सुविधा चाहिए, हवाई जहाजों की सुविधा चाहिए और कोई - संबंधी आवश्यकताएं हो satiation जैसी आवश्यकता हो, भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के ओडिशा के इस नवकलेवर पर्व में आपका साथ देगी और ऊपर से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से भी इसमें मुहैया किया जाएगा।

भाईयों-बहनों आज इस्पात के इस कारखाने के Expansion के साथ हम आगे तो बढ़ेंगे और आगे बढ़ने का संकल्प लेकर जाएंगे, विकास की नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ेंगे और मैं राज्यों को निमंत्रित करता हूं। आईए एक नए युग का ये शुभारंभ करने का अवसर है। लंबी सोच के साथ हम विकास की नींव मजबूत बनाएं। तत्कालीन फायदे से मुक्त होकर के हमारी भावी पीढ़ी के कल्याण के लिए हम अपने रास्तों को प्रशस्त करें।

मैं फिर एक बार SAIL के सभी मित्रों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहां के छोटे-मोटे इस्पात के कारखानों के मेरे भाईयों-बहनों को अनेक-अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उड़ीसा Government का बहुत आभारी हूं और मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं भाईयों-बहनों। मैं नहीं मानता हूं कि कभी सरकार किसी कार्यक्रम में इतनी भीड़ आती हो। चारों तरफ मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आपने मुझे जो प्यार दिया है, ये प्यार एक प्रकार से विकास के प्रति आपके समर्थन की अभिव्यक्ति है। देश के नौजवानों के भविष्य को बदलने के लिए आपके संकल्प की अभिव्यक्ति है। हिंदुस्तान के गरीब को, किसान को ताकतवर बनाने के, आपके सपनों को पूरा करने का जो संकल्प है, उसका खुला समर्थन करने का आपका ये प्रयास है। मैं इसके लिए मेरे उड़ियावासियों को शत-शत नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए। जय जगन्नाथ-जय जगन्नाथ-जय जगन्नाथ।

\*\*\*\*\*

महिमा वशिष्ट, तारा, मुस्तकीम खान



पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय

19-मई-2015 16:08 IST

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सियोल में एशियन लीडरशिप फोरम में संबोधन का मूल पाठ

महामहिम राष्ट्रपति पार्क ग्यून ही  
 महामहिम शिखा मोजाह  
 महामहिम श्री बान की मून  
 चोसून-इलबो के अध्यक्ष श्री बंग संग-हून  
 राष्ट्रपति पार्क और शिखा मोजाह और बान की मून के साथ मंच साझा करना मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है।  
 ये सभी एशिया के विख्यात नेता हैं। ये सभी एशिया की विविधता और उसकी समान भावना को दर्शाते हैं।  
 अपनी सरकार के पहले वर्ष में कोरिया गणराज्य का दौरा कर मैं प्रसन्न हूँ।  
 कोरिया के ब्रांडों के भारतीय घरों में पहुंचने से पहले ही कोरिया के लोगों ने भारतीयों के दिलों में अपना स्थान बना लिया था।

लगभग 100 वर्ष पहले भारत के महान कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कोरिया को पूर्व का दीप कहा था। आज कोरिया उन्हें सही साबित कर रहा है।

कोरिया की चमत्कारिक आर्थिक वृद्धि और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व से एशिया की सदी के दावे को और अधिक बल मिला है।

कोरिया एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लोकतंत्र और स्थायित्व के लिए स्तंभ है।

एशिया का पुनरुत्थान हमारे दौर की सबसे बड़ी घटना है।

इसकी शुरुआत जापान से हुई और इसके बाद यह चीन, कोरिया एवं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पहुंचा।

पश्चिम में कतर जैसे देश अपने रेगिस्तान जैसे परिदृश्य को प्रगति की अर्थव्यवस्था में बदल रहे हैं।

एशिया की प्रगति को जारी रखने की बारी अब भारत की है।

125 करोड़ आबादी का यह देश 80 करोड़ युवाओं के रूप में असाधारण संसाधनों का धनी है।

भारत की संभावनाओं पर कोई संदेह नहीं है और पिछले एक वर्ष से हम वादों को वास्तविकता और आशा को विश्वास में बदल रहे हैं।

भारत में वृद्धि दर प्रति वर्ष 7.5 प्रतिशत रही है तथा इसके और अधिक मजबूत होने की आशा है।

विश्व एक आवाज में यह कह रहा है कि विश्व और हमारे क्षेत्र के लिए भारत आशा की नई किरण है।

दुनिया की आबादी के छठे हिस्से की प्रगति विश्व के लिए एक अवसर होगी।

यह भारत को दुनिया के लिए और अधिक करने की क्षमता भी देगा।

इन सबसे ऊपर भारत की प्रगति एशिया की सफलता की कहानी होगी और यह एशिया के हमारे सपनों को सच करने में मददगार साबित होगी।

जब एशिया के सभी देश प्रगति करेंगे तब एशिया को अधिक सफलता मिलेगी।

एशिया के दो चेहरे नहीं होने चाहिए- एक आशा और समृद्धि का तथा दूसरा कष्ट और हताशा का।

यह विकास और अवनति के देशों का महाद्वीप नहीं होना चाहिए जहां एक ओर स्थायित्व है और दूसरी ओर बिखरे हुए संस्थान हैं।

भारत साझा समृद्धि वाले एशिया की आशा करता है जहां एक देश की सफलता दूसरे देश की मजबूती बने।

वृद्धि देश के अंदर और देशों के बीच समेकित होनी चाहिए। यह राष्ट्रीय सरकार का दायित्व होने के साथ एक क्षेत्रीय जिम्मेदारी भी है।

इसलिए भारत के भविष्य का जो सपना मैं देखता हूँ वही अपने पड़ोसियों के लिए भी चाहता हूँ।

एशिया में कुछ देश अधिक समृद्ध हैं। हमें अपने संसाधनों और बाजारों को ऐसे देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार होना चाहिए जिनकी उन्हें आवश्यकता है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एशिया में कई देशों ने यह जिम्मेदारी उठाई है।

यह वह सिद्धांत है जो भारत की नीतियों को दिशा प्रदान करता है और यह संपूर्ण विश्व को एक परिवार 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के रूप में देखने की नैतिकता से आता है।

हमें अपने युवाओं को कौशल और शिक्षा से सशक्त करना होगा ताकि वे अपने भविष्य की ओर आशा से देख सकें।

अगले 40 वर्षों में एशिया के तीन अरब निवासी समृद्धि के अगले स्तर पर पहुंचेंगे। एशिया की समृद्धि और बढ़ती हुई जनसंख्या से हमारे सीमित संसाधनों की मांग बढ़ेगी।

इसलिए हमारी आर्थिक वृद्धि के साथ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम होना चाहिए। मैं इसलिए जीवन शैली और समृद्धि के मार्गों में बदलाव की बात करता हूँ और मुझे विश्वास है कि यह हमारे भविष्य से समझौता किए बिना संभव है।

एशिया को नये उत्पादों के लिए अपनी क्षमता और मित्तव्ययी निर्माण का इस्तेमाल वहनीय नवीकरणीय ऊर्जा के लिए करना चाहिए।

प्रकृति के प्रति सम्मान हमारी साझा विरासत का अंग है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना हमारे स्वयं के सरोकारों के लिए आवश्यक है।

इसलिए भारत ने अगले पांच वर्षों में 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन कोयला और तेल लम्बे समय तक हमारी ऊर्जा के प्रमुख संसाधन बने रहेंगे। इसलिए उन्हें और अधिक स्वच्छ तथा पर्यावरण के लिए कम नुकसानदेह बनाने के लिए मिलकर काम करें।

समेकित वृद्धि के प्रति हमारी नीति तब तक अधूरी है जब तक कि हम अपने क्षेत्र में कृषि में बदलाव के लिए अपने नवाचार और प्रौद्योगिकी को साझा नहीं करते।

हम में से कड़ियों का समान पारिस्थितिक तंत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और एक-दूसरे से सीखने का हमारा लम्बा इतिहास रहा है।

वर्ष 2025 तक एशिया के अधिकतर निवासी शहरों में रह रहे होंगे। एशिया के शहरी क्षेत्रों की आबादी दुनिया के अन्य क्षेत्रों में मध्यम क्षेत्रफल के देशों से अधिक होगी। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में उस समय विश्व की 11 प्रतिशत शहरी जनसंख्या निवास कर रही होगी।

इसलिए रहने योग्य और भविष्य के लिए दीर्घकालिक शहरों का सृजन करना हम सबका सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए।

इसलिए हमने भारत में शहरों के नवीकरण और स्मार्ट शहर बनाने पर अधिक ध्यान दिया है और हम इस बारे में सियोल जैसे शहरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं।

अगर एशिया समान रूप से प्रगति करेगा तो वह क्षेत्रीय भागों के बारे में नहीं सोचेगा। आज पश्चिम एशिया में होने वाली किसी भी घटना का पूर्वी एशिया में मजबूत प्रभाव पड़ता है और समुद्री क्षेत्र में होने वाली किसी भी घटना का पर्वतीय क्षेत्रों में असर पड़ता है।

भारत एशिया के मध्य में है और हम एक-दूसरे से जुड़े एशिया के निर्माण की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे।

हमें अपने क्षेत्रों को आधारभूत ढांचे से जोड़ना होगा और उनका एकीकरण व्यापार तथा निवेश के जरिये करना होगा।

हमें एशिया में चिर शांति और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे।

इस वर्ष दो युद्धों की 100वीं और 70वीं बरसी पर हमें यह स्मरण करना चाहिए कि शांति अवश्यभावी नहीं है।

हमें ऐसे संस्थानों का निर्माण करना चाहिए जो समानता सह अस्तित्व और अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानकों को बढ़ावा देते हैं।

इसका अर्थ यह भी है कि हमें अपने समुद्रों बाहरी अंतरिक्ष और साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने और सभी को लाभ पहुंचाने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए।

यह हर देश की एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी भी है।

यह हम सबका एक जैसी चुनौतियों आतंकवाद अंतरदेशीय अपराधों प्राकृतिक आपदाओं और रोगों से निपटने में सामूहिक कर्तव्य भी है।

जोश से भरे एशिया में अनिश्चितताएं भी हैं लेकिन इसकी दिशा तय करने में एशिया को नेतृत्व के लिए पहल करनी होगी।

लेकिन एशिया के तेजी से बढ़ते प्रभाव के कारण इसे दुनिया में अधिक जिम्मेदारी भी उठानी होगी और इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।

हमें शासन प्रणाली के अंतरराष्ट्रीय संस्थानों जैसे संयुक्त राष्ट्र और इसकी सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा।

प्रतिद्वंद्विता का एशिया हमें आगे बढ़ने से रोकेगा जबकि एशिया की एकता विश्व की शक्ति निर्धारित करेगी।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ- इतिहास में एशिया धर्म संस्कृति ज्ञान और व्यापार के प्रवाह से जुड़ा रहा है।

और एशिया ने दुनिया को महान धर्म चाय और चावल बेहतरीन मानव सृजन और सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार और प्रौद्योगिकी प्रदान की है।

हम दुखद संघर्षों और उपनिवेशवाद की लम्बी छाया से बाहर निकले हैं।

हमने एशिया की शक्ति और जोश देखा है।

आइए मिलकर हमारी विरासत और सहक्रियता हमारी प्राचीन बुद्धिमत्ता और युवा ऊर्जा का उपयोग अपने और विश्व के लिए समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करें।

धन्यवाद।

आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**वि.कासोटिया/एएम/एजे/एनआर-2282**



पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय

19-मई-2015 13:13 IST

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का भारत-दक्षिण कोरिया सीईओ फोरम में वक्तव्य

कोरिया गणतंत्र के राष्ट्रपति पार्क ग्यून ही, दोनों देशों के प्रख्यात सीईओ, व्यापार और उद्योग जगत के अन्य प्रतिनिधियों तथा भाईयों और बहनों!

मैं आज सुबह यहां आप लोगों के साथ अति प्रसन्न हूं। मैं आप सभी का हमारा साथ निभाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि दोनों पक्षों के सीईओ के बीच बातचीत लाभप्रद होगी।

मित्रों! भारत और कोरिया के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंधों का प्राचीन इतिहास रहा है। दोनों देशों के बीच संबंधों की शुरुआत पहली सदी में हुई जब उत्तरी भारत के अयोध्या साम्राज्य से एक भारतीय राजकुमारी ने नाव से कोरिया की यात्रा की।

राजकुमारी ने कोरिया के राजा शुरी से विवाह किया और वह दक्षिण कोरिया साम्राज्य की पहली रानी बनी। कोरिया के कई निवासियों की वंश बेल उनसे जुड़ी हैं।

हम बौद्ध परंपरा से भी जुड़े हैं। कोरिया के एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हिचो ने आठवीं शताब्दी में बुद्ध की भूमि की भाषा और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए भारत का भ्रमण किया था। इस पर उन्होंने एक पुस्तक "पांच भारतीय साम्राज्यों के दौर का विवरण" लिखी थी।

हमारे बीच बहुत कुछ समानता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बॉलीवुड की फिल्मों कोरिया में बहुत लोकप्रिय हैं। मित्रों! मैं इस संबंध को और मजबूत करने यहां आया हूं। वास्तव में मैं हमेशा कोरिया से बहुत अधिक प्रभावित रहा हूं। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब यहां आया था और उससे पहले भी मैं कोरिया का दौरा कर चुका हूं। ईमानदारी से कहूं तो जब मैं गुजरात में था तो सोचा करता था कि गुजरात के क्षेत्रफल का यह देश इतनी अधिक आर्थिक प्रगति कैसे कर सकता है। मैं कोरिया के लोगों की उद्यम के जज्बे का सम्मान करता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने अपने ग्लोबल ब्रांड तैयार किए और उन्हें बनाए रखा उनकी मैं सराहना करता हूं।

आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल और स्टील तक कोरिया ने विश्व को अनुकरणीय उत्पाद दिए हैं। इसी प्रकार से कोरिया की कंपनियां निर्माण क्षेत्र में बहुत मजबूत हैं और दुनियाभर में प्रतिष्ठित भवन बनाने में शामिल हैं। आप लोगों के बीच एक प्रभावशाली आधारभूत ढांचे के साथ ही अनुसंधान, विकास और नवाचार में भी प्रगति के कीर्तिमान हैं।

हमें भारत में वो सब प्राप्त करना है जो कोरिया पहले ही हासिल कर चुका है। इसीलिए मैं एक बड़े व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां हूं। एक अच्छा समाचार यह है कि जनवरी 2010 में कोरिया- भारत सीपा पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत और कोरिया के बीच द्वीपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है।

राजस्थान में दक्षिण कोरिया निवेश क्षेत्र अच्छी प्रगति कर रहा है।

कई सौ कोरियाई कंपनियां भारत में कार्य कर रही हैं। आपके उत्पाद विशेष तौर पर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े उत्पाद भारतीयों की पहली पसंद है और इनमें से कई का उत्पादन यहां हो रहा है। हुंदै मोटर भारत में दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है।

हालांकि कई क्षेत्रों में अभी भी प्रगति की भारी संभावनाएं हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वालों में दक्षिण कोरिया का स्थान 14वां है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कारण हम से जुड़ा है आपसे नहीं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत संभावनाओं का देश था और है। अब भारत सुगम नीतिगत माहौल का देश भी है। मेरी सरकार देश के वातावरण में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने नागरिकों और उद्योग के आपसी लाभ के लिए मिलजुलकर काम कर सकते हैं। हम एकजुट होकर कई कार्य कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, भारत के सॉफ्टवेयर और कोरिया के हार्डवेयर उद्योग के बीच सहयोग की संभावना है। आपके कार निर्माण और हमारे डिजाइन करने की क्षमता को मिलाकर काम किया जा सकता है। हालांकि हम इस्पात के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक बन गए हैं, लेकिन हमें इसमें बहुत अधिक मूल्यवर्द्धन की आवश्यकता है। आपकी स्टील निर्माण की क्षमता और हमारी लौह अयस्क के संसाधन में समन्वय के साथ काम किया जा सकता है। आपके जहाज निर्माण की क्षमता और हमारे बंदरगाहों पर आधारित विकास का एजेंडा हमारे विकास को नई दिशा दे सकता है। आवास सहित आधारभूत ढांचागत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम मिलकर बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं।

पिछले बार मैं आपकी बेहतरीन सीमानगुयम परियोजना को देखा था। हमें ऐसी कई सीमानगुयम परियोजनाओं का निर्माण करना है। आइए दोनों देशों के फायदे के लिए यह कार्य करें।

मित्रों! मेरी सरकार के गठन के बाद से तीव्र और समेकित वृद्धि का वातावरण तैयार करने के लिए हम दिन-रात काम कर रहे हैं। हम इस सबमें कई गुणा प्रगति करना चाहते हैं। कोरिया जिन क्षेत्रों में मजबूत है वो हमारे देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से ज्यादातर भारत में उपस्थित हैं जो भारत में उपस्थित नहीं हैं मैं उनको भारत आने और संभावनाओं की खोज करने का निमंत्रण देता हूं।

भारत में आपकी उपस्थिति और हमारे सीईओ के साथ बातचीत के बाद आपको इस बात का आभास होगा कि हम क्या कर रहे हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस संबंध में संभावनाओं के स्तर पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं।

हमारे देश में जल, परिवहन, रेलवे, बंदरगाह, जहाज निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा सहित विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत ढांचा और सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण उद्योग क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं।

मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी वर्ष 2022 तक 50 मिलियन घर बनाने की योजना है इसके साथ ही हम स्मार्ट शहर, लम्बे औद्योगिक गलियारों और विशाल निवेश क्षेत्र भी विकसित करने वाले हैं। इस उद्देश्य के लिए हमने निर्माण क्षेत्र से संबंधित एफडीआई नीति में सुधार किए हैं। निवेश के लिए हमने रीयल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के शर्तों को सुगम बनाया है। हम इस क्षेत्र के लिए एक नियामक ढांचा भी लेकर आ रहे हैं।

अगले कुछ वर्षों में 175 गिगा वाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है। उत्पादन के साथ-साथ विद्युत वितरण और प्रेषण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

हम अपने रेलवे क्षेत्र को आधुनिक बनाना चाहते हैं। हमने 50 शहरों में मेट्रो रेल और विभिन्न कॉरिडोर में हाई स्पीड की ट्रेनों की योजना बनाई है। हमें अपने राजमार्गों की स्थिति में भी सुधार करना है।

हमने इस वर्ष इन दो क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक आवंटन किया है। इसके साथ ही हमने रेलवे को 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए खोला है।

हम एक महत्वाकांक्षी योजना सागरमाला के द्वारा पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और नये बंदरगाहों का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार से मौजूदा हवाई अड्डों के उन्नयन और आर्थिक तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों से संपर्क बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय हवाई अड्डों का निर्माण करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

हम विशेष तौर पर निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहते हैं जिससे हमारे युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य के लिए हमने मेक इन इंडिया की शुरुआत की है। इस अभियान और प्रतिबद्धता में हमारे औद्योगिक आधारभूत ढांचे नीतियों और प्रणालियों को विश्व के सर्वोत्तम स्तरों पर लाना शामिल है ताकि भारत को वैश्विक निर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके। देशभर में डिजिटल आधारभूत ढांचा प्रदान करने के लिए हमने एक अन्य अभियान डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की है।

स्वच्छ और हरित विकास और जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट निर्माण हमारी एक और प्रतिबद्धता है। हमने स्वच्छ इंडिया अभियान की शुरुआत की है जिसके द्वारा हम उन्नत पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी अपनाने पर जोर दे रहे हैं।

इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने पिछले 11 महीनों में व्यवसायिक वातावरण को सुधारने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हम मानते हैं कि 'व्यापार करने में सुगमता' भारत में निवेश आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम बना है। हम यह भी मानते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश महत्वपूर्ण है और यह वैश्विक प्रतिस्पर्धी व्यापारिक माहौल के बिना देश में नहीं आएगा। इसलिए हम भारत को व्यापार करने में सुगम देश बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

देश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए हमने स्किल इंडिया अभियान और अन्य अनूठे अभियानों की शुरुआत की है। दूसरी ओर हम उद्योग और आधारभूत ढांचे क्षेत्र में तेजी से अनुमति प्रदान कर रहे हैं। इसमें पर्यावरणीय मंजूरी, औद्योगिक और नौवहन लाइसेंस सम्मिलित हैं। इसके साथ ही हमने प्रमुख क्षेत्रों जैसे रक्षा और बीमा क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाया है। हमने स्वास्थ्य उपकरणों के क्षेत्र में देश में इनके निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में बदलाव किए हैं।

हमने बहुत ही कम समय में संसद में जीएसटी विधेयक को प्रस्तुत किया है। हम अपनी कर नीति को बहुत अधिक स्थाई, पारदर्शी और पूर्वानुमेय बना रहे हैं। हमने विदेशी निवेशकों को प्रभावित करने वाले कई कर विवादों का समाधान किया है जिससे भारत में व्यापार के लिए उचित माहौल बनाया जा सके और प्रौद्योगिकी और पूंजी को लाना सुगम हो।

इन शुरुआती कदमों से हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। निजी निवेश और विदेशी निवेश के सकारात्मक संकेत मिले हैं। हमारी वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक है। गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल 2014 से फरवरी 2015 की अवधि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ओईसीडी सहित कई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने आने वाले वर्षों में और अधिक वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में हमारे द्वारा उठाए गए मजबूत कदमों के चलते मूडी ने हाल ही में भारत की रेटिंग को सकारात्मक के रूप में परिवर्तित किया है।

राजनीति, प्रशासन और आर्थिक क्षेत्र में विश्व स्तर पर हमने भारत की पहले जैसी स्थिति को फिर से हासिल किया है। लेकिन हम यहां रुकने वाले नहीं हैं हमें इससे और अधिक बेहतर कार्य करना है और हम ऐसा करेंगे।

मित्रों! मैं एक बार फिर आप सबको भारत में बदलाव देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम आपके साथ कार्य करने के लिए स्थितियों को और सुगम बनाने के लिए तत्पर हैं।

मैंने कल कोरिया के निवेशकों पर अतिरिक्त ध्यान देने के लिए एक विशेष प्रक्रिया बनाने की घोषणा की थी। इसे कोरिया प्लस के नाम से जाना जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं आश्वासन देता हूं कि अगर कोई मुद्दा है तो मैं उस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दूंगा।

धन्यवाद

वि.कासोटिया/एएम/एजे/एनआर-2280





पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय

16-मई-2015 12:36 IST

---

भारत-चीन व्यापार मंच में प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

मित्रो,

मुझे यहां आप सबके बीच उपस्थित होकर सचमुच प्रसन्नता हो रही है। इस मंच में आने से पहले मैंने चीन की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों-सीईओ के साथ बहुत विस्तार में चर्चा की। मुझे विश्वास है कि आज के विचार विमर्श से दोनों देशों की जनता और व्यापार को फायदा होगा।

मेरे साथ कई अधिकारी और भारत के जाने-माने सीईओ भी यहां उपस्थित हैं।

जैसा कि आप जानते हैं चीन और भारत दोनों की विश्व में महान और पुरानी सभ्यताएं हैं। उन्होंने समूचे मानव समाज को ज्ञान के कई प्रकाश दिए हैं। आज हम दोनों मिलकर विश्व की कुल जनसंख्या के एक तिहाई से अधिक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत और चीन का पांच हजार वर्ष का साझा इतिहास है और तीन हजार चार सौ किलोमीटर से अधिक साझा सीमा है।

दो हजार वर्ष पहले चीन के सम्राट मिंग के निमंत्रण पर भारत के दो भिक्षुओं ने चीन की यात्रा की थी। वे अपने साथ सफेद घोड़ों पर संस्कृत के कई ग्रंथ लेकर आये थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के कई श्रेष्ठ ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था।

ऐसा माना जाता है कि उन्होंने चीन में बौद्ध धर्म के द्वार खोले। चीन के सम्राट ने इस अवसर को यादगार बनाने के लिए एक मंदिर बनवाया था। यह मंदिर व्हाइट हाउस टैंपल के रूप में प्रसिद्ध है। चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ इस मंदिर का महत्व बढ़ता गया। इसके साथ ही बौद्ध धर्म का प्रसार कोरिया, जापान और वियतनाम में हुआ।

एशियाई देशों में बौद्ध धर्म की पवित्रता और शुद्धता सफलता का बीज मंत्र साबित हुई। मेरा यह अडिग विश्वास है कि यह शताब्दी एशिया की शताब्दी है और बौद्ध धर्म एशियाई देशों के बीच और अधिक एकता और प्रेरक शक्ति के रूप में मौजूद रहेगा।

चीन से आये फाहियान और ह्यून सांग जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने भारतीयों को चीन की बुद्धिमत्ता के कई रहस्यों का पाठ पढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने भारत में कई रहस्यों का पता लगाया। वह गुजरात में मेरे गृहनगर भी आये थे। उनके कार्यों से आज हमें ज्ञात होता है कि वहां एक बौद्ध मठ हुआ करता था। ह्यून सांग जब अपने देश चीन लौटे तो वे अपने साथ संस्कृत के ग्रंथ और बौद्धिक ज्ञान की पुस्तकें लेकर आये। दोनों देशों की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां प्राकृतिक तत्वों पर आधारित हैं और उनमें बहुत समानता है।

वर्तमान में भी हमारी सीमाओं से दोनों ओर ज्ञान का प्रसार और आदान-प्रदान होता है। पेइचिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर Ji xianlin संस्कृत के महान विद्वान थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय वाल्मीकि रामायण का चीनी भाषा में अनुवाद करने में लगा दिया। भारत की सरकार ने उन्हें 2008 में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया था।

हाल ही में प्रोफेसर जिन डिंग हान ने तुलसी रचित रामायण का चीनी भाषा में अनुवाद किया। भागवत गीता और महाभारत भी चीन के लोगों में लोकप्रिय हैं। मैं चीन के इन विद्वानों का अपने देश के लोगों को भारतीय संस्कृति से अवगत कराने हेतु धन्यवाद करता हूं।

मित्रो, भारत सदैव ज्ञान आधारित समाज रहा है जबकि चीन को नवोन्मेषी समाज माना जाता है। पुरातन चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अति उन्नत था। चीन के लोगों की तरह भारतीय भी अपने जहाजों से अमरीका और विश्व के दूरदराज के कोनों तक पहुंचे थे। उनके पास मेरिनर कम्पास और गन पाउडर हुआ करता था।

मुझे, यह भी बताना है कि उस समय भारतीय खगोल शास्त्र और गणित भी चीन में बहुत लोकप्रिय था। भारतीय खगोल शास्त्रियों को कैलेंडर बनाने के लिए गठित आधिकारिक दल में नियुक्त किया जाता था।

भारत की शून्य की अवधारणा और 9 ग्रह होने का विश्वास चीन में आविष्कारों में मददगार रहा है। इसलिए हमारे विचारों की आपके नवोन्मेष में भूमिका थी।

इसलिए मैं कह सकता हूं कि हममें बहुत सी समानताएं हैं और हम मिलकर काफी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने आध्यात्मिक वृद्धि में एक-दूसरे की सहायता की उसी तरह हमें अर्थव्यवस्था की वृद्धि में भी एक-दूसरे की मदद करनी है। विगत में भी ऐसे आर्थिक आदान-प्रदान के अवसर मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि चीन ने भारत को रेशम और कागज दिया। हम दोनों ने वृद्धि की क्षमताएं और निर्धनता की समस्याएं हैं जिनका हम मिलकर समाधान कर सकते हैं। मैं, निजी तौर पर सहयोगी प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध हूं।

इसलिए मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी चीन की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री के रूप में भी मैं दोनों देशों के बीच सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आदान-प्रदान और सहयोग के लिए वचनबद्ध हूं और इसे मैं सही मानता हूं।

मैं और राष्ट्रपति शी जो संबंध बना रहे हैं उनसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। राष्ट्रपति शी की सितम्बर, 2014 में भारत यात्रा के दौरान भारत में चीन के 20 अरब अमरीकी डॉलर (12 लाख करोड़ रुपये) के निवेश की वचनबद्धता की गई थी। हमने 13 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश के औद्योगिक पार्क, रेलवे, ऋण और लीजिंग से संबंधित 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।

हम उन क्षेत्रों को विकसित करने के अत्यंत इच्छुक हैं जिनमें चीन मजबूत है। हमें आपके सहयोग की जरूरत है। भारत में बुनियादी ढांचे और संबंधित विकास का क्षेत्र और क्षमताएं अपार हैं। मैं इसके कुछ उदाहरण दे रहा हूं:

- हमने 2022 तक पांच करोड़ आवास बनाने की योजना बनाई है। इसके अलावा हम स्मार्ट सिटी और विशाल औद्योगिक गलियारे भी विकसित कर रहे हैं।

- इसके लिए निर्माण क्षेत्र में हमने अपनी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में अनुकूल सुधार किए हैं। हम इस क्षेत्र के लिए एक नियामक व्यवस्था बनाना चाहते हैं।
- हमने अगले कुछ वर्षों में 175 गीगा वॉट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके उत्पादन के अलावा बिजली का पारेषण और वितरण भी हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है।
- हम सिग्नल, इंजन और रेलवे स्टेशनों समेत रेलवे का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। पचास शहरों में मेट्रो रेल लाने और कई गलियारों में हाई स्पीड ट्रेन चलाने की हमारी योजना है।
- इसी तरह हम तेजी से राजमार्ग निर्माण करना चाहते हैं।
- हम महत्वाकांक्षी सागरमाला योजना के अंतर्गत नये पोतों का निर्माण और पुराने पोतों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है।
- वर्तमान हवाई अड्डों को उन्नत बनाने और आर्थिक तथा पर्यटन महत्व के स्थानों तक वायुयान सेवा की सुविधा पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय हवाई अड्डे स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- वित्तीय सेवाओं में भी हम बैंक ऋणों और बीमा समेत वित्तीय सेवाओं की अधिक समावेशी और त्वरित डिलीवरी की ओर बढ़ रहे हैं।
- इसके लिए हमने 14 करोड़ बैंक खाते खोले हैं, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया है और छोटे व्यापारियों को राशि उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा बैंक भी खोला है।
- हाल ही में मैंने देश के नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए बीमा और पेंशन की नई योजनाओं का शुभारंभ किया है।

इस वर्ष मार्च में मैंने दिल्ली में चीन की अलीबाबा कंपनी के सीईओ जैकमा के साथ भारत में लघु ऋण क्षेत्र मजबूत बनाने में संभव सहयोग के बारे में चर्चा की थी।

जैसा कि आपने सफलता हासिल की है हम भी देश के 65 प्रतिशत युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने हेतु विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं।

इसलिए हम भारत में माल और सामान बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमने 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की है। देश में नवोन्मेष, अनुसंधान विकास और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार प्रयास कर रही है। इस वर्ष के बजट में हमने इस उद्देश्य से कुछ नवोन्मेषी संस्थागत व्यवस्था बनाई है।

श्रम-सघन उद्योगों के विकास, सतत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुकूल माहौल विकसित करने, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और निर्यात के लिए विकास के मॉडल के बारे में हमें आपसे सीखना है।

यह सब चीन की कंपनियों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। आप मेरी सरकार की दिशा और उसके द्वारा उठाये गये कदमों से अवगत हैं। हमने अपने आप को व्यापारिक माहौल में सुधार लाने के प्रति समर्पित किया है। मैं, विश्वास दिला सकता हूँ कि आप भारत आने का निर्णय तो लें हम आपको अधिक से अधिक आरामदायक सुविधाएं देने का भरोसा दिलाते हैं।

चीन की कई कंपनियों द्वारा भारत की क्षमताओं का फायदा उठाने के लिए हमारे देश में निवेश करने की संभावना है। यह संभावनाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचे क्षेत्र में हैं।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत में आर्थिक माहौल बदल गया है। हमारा नियामक तंत्र अब अधिक पारदर्शी, सहयोगी और स्थिर है। हम संबंधित मुद्दों पर दीर्घकालिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण बना रहे हैं। इस दिशा में कई प्रयास किए गए हैं और भारत में व्यापार करने को सुविधाजनक बनाने के लिए सुधार जारी हैं। हमारा मानना है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश महत्वपूर्ण है और वैश्विक स्पर्धी व्यापारिक माहौल के बिना देश में ऐसा निवेश नहीं आ सकता। इसलिए हमने उन कई मुद्दों को तर्कसंगत बनाया है जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय बने हुए थे।

इनमें से मैं कुछ विशेष का उल्लेख कर रहा हूँ।

- हम कराधान प्रणाली को पारदर्शी, स्थिर और अनुमानजनक बना रहे हैं।
- हमने कई प्रतिगामी कराधान व्यवस्थाएं हटा दी हैं। हमारी सरकार के पहले बजट में यह कहा गया है कि हम पिछली तिथि से कराधान लागू नहीं करेंगे।
- हम जटिल प्रक्रियाओं में कमी ला रहे हैं और उन्हें एक ही स्थान पर उपलब्ध करा रहे हैं और ऑनलाइन बनाने की प्राथमिकता दे रहे हैं।
- प्रपत्रों और प्रारूपों को सरल बनाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है।
- निवेशकों को सहयोग देने के लिए बड़े केंद्र बनाये गए हैं और विशेष व्यवस्था की गई है। इन कार्यों के लिए 'इन्वेस्ट इंडिया' केंद्रीय एजेंसी के रूप में काम कर रही है।
- इस वर्ष के बजट में हमने एआईएफ के जरिये कर को आगे ले जाने, आरईआईटी से पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाने और पीई नियमों के संशोधन और दो वर्ष के लिए जीएएआर लागू करने को स्थगित करने की अनुमति दी है।

- उद्योग और बुनियादी ढांचा के लिए तेजी से अनुमति दी जा रही हैं। इनमें पर्यावरण मंजूरी, औद्योगिक लाइसेंस की अवधि बढ़ाना, रक्षा से संबंधित मदों को लाइसेंस मुक्त करना और सीमा पार व्यापार को सरल बनाना शामिल है।
- संसद में वस्तु और सेवा कर पर विचार किया गया है। इसी तरह बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हमने कई दूरगामी कदम उठाये हैं।
- पहली बार हमने सड़कों और रेलवे क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक आवंटन किया है।
- इसके अलावा हम भारत ढांचागत निवेश कोष गठित कर रहे हैं।
- हमने सड़कों और रेलवे समेत बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कर मुक्त बांड की अनुमति भी दी है।

हमें मालूम है कि अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है लेकिन हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध हैं। हम व्यापार के माहौल में और सुधार लाने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

हमारे प्रारंभिक उपायों से निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में मदद मिली है। निजी निवेश का उत्साह और विदेशी निवेश का प्रवाह अनुकूल है। विदेशी निवेश बढ़कर अप्रैल, 2014 में 39 प्रतिशत तक पहुंच गया और फरवरी, 2015 में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले अधिक निवेश हुआ।

हमारी वृद्धि दर सात प्रतिशत से अधिक है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ओइसीडी समेत अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने आने वाले समय में भारत की तेज़ वृद्धि का अनुमान लगाया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत की रेटिंग को अनुकूल बताया है क्योंकि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाये हैं।

मित्रो, भारत और चीन की मैत्री फले फूलेगी और मजबूत बनेगी। मैं दोनों देशों के साथ आने से बेहतर परिणाम की अपेक्षा करता हूं। विगत वर्षों में भी हमने एक-दूसरे की सहायता की है और हम वर्तमान में और आने वाले समय में भी ऐसा कर सकते हैं। एशिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्था के नाते महाद्वीप के आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए भारत और चीन की भागीदारी आवश्यक है। आप विश्व की कार्यशाला हैं जबकि हम विश्व के लिए सहायक कार्यालय हैं। आप हार्डवेयर उत्पादन पर जोर दे रहे हैं जबकि भारत सॉफ्टवेयर और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

इसी तरह भारत में हिस्से पुर्जों और घटकों का विनिर्माण करने वालों को अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है और उनकी जानी-मानी उच्च गुणवत्ता है और चीन के विनिर्माताओं ने बड़े पैमाने पर माल तैयार करने की कला में दक्षता हासिल की है। भारतीय इंजीनियरों की हिस्से पुर्जों और घटकों के डिजाइन की विशेषज्ञता और चीन के बड़े पैमाने पर माल तैयार करने की कम लागत बेहतर तरीके से वैश्विक बाजार के लिए फायदेमंद हो सकती है। चीन और भारत की यह औद्योगिक भागीदारी अधिक निवेश, रोजगार और लोगों की संतुष्टि का आधार बन सकती है।

मित्रो, आइये हम आपसी हितों के लिए और अपने महान देशों की प्रगति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करें।

मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि अब भारत व्यापार के लिए तैयार है आप भी भारत में परिवर्तन की चल रही हवा महसूस कर रहे होंगे। मैं आपको भारत आने और उसे महसूस करने की सलाह देता हूं।

मैं, आपकी सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद।

वि.कसोटिया/एएम/एसपी/सीसी-2609



**पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय**

18-सितम्बर-2015 23:45 IST

**वाराणसी में विभिन्न विकास योजनाओं के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ**

विशाल संख्या में पधारे मेरे बनारस के प्यारे भाइयों और बहनों,

ये कार्यक्रम तो बनारस की धरती पर हो रहा है लेकिन ये कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के लिए हो रहा है। ये बनारस की धरती है, जिसने सदियों से मानव जाति को ज्ञान का प्रकाश दिया और ज्ञान का प्रकाश देने वाली ये नगरी ऊर्जा वाला प्रकाश भी देने का नेतृत्व करने जा रही है और इसलिए मैं देशवासियों को बधाई देता हूं, बनारसवासियों को विशेष बधाई देता हूं।

वैसे तो ये समारोह एक है लेकिन इस एक समारोह में सात कार्यक्रम लगे हैं, सात। एक तो आपने अभी-अभी video देखा कि बिजली के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए पूरे देश में हम क्या करने जा रहे हैं। दूसरा, वाराणसी में एक कठिनाई लम्बे अर्से से चली है, वाराणसीवासियों की एक मांग अनेक वर्षों से रही है और वो है वाराणसी के रिंग रोड की मांग। आज इस मंच से उस रिंग रोड के कार्यक्रम का भी शिलान्यास हो रहा है। काशी तीर्थयात्रियों का धाम है, विश्व के टूरिस्टों का भी आकर्षण है, लेकिन एयरपोर्ट से काशी पहुंचने तक आने वाले यात्री के मन में से विश्वास उठा जाता है के मैं सही जगह पर जा रहा हूं कहीं और जा रहा हूं और उसका मूल कारण काशी से बाबतपुर हवाई अड्डे तक का जो मार्ग है उसकी दुर्दशा। आज यहां से उस काम का भी शिलान्यास हो रहा है कि जिसमें उस रास्ते को चौड़ा किया जाएगा, आधुनिक बनाया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा ताकि काशी पहुंचने वाला विश्व का या देश का कोई भी यात्री आते ही अनुमान करेगा कि मैं किस भव्य और पुरातन नगरी में प्रवेश कर रहा हूं उसका उसको अनुमान हो जाएगा।

आज ये जो देशभर के लिए IPDS योजना का प्रारंभ हुआ उस IPDS योजना को लागू करने के लिए बनारस में दो नए Substation...Chowk Substation का शिलान्यास भी आज इस मंच से हो रहा है और योजना को लागू करने का काम आज आरंभ हो रहा है। एक Chowk Substation, दूसरा Kazzakpura Substation, ये दो Substations का भी शिलान्यास आज इसी मंच से हो रहा है। बनारस में आरोग्य की सुविधा में एक नया नजराना...कुछ समय से जो Trauma Centre चालू हुआ है, यहां के नागरिकों को उसकी सेवाएं उपलब्ध हैं, आज उसका लोकार्पण भी यहां हो रहा है। उसी प्रकार से गंगा घाट पर ही बसा हुआ हमारा रामनगर, धीरे-धीरे उसकी आबादी बढ़ रही है, उस तरफ के नागरिकों के लिए सुविधा की आवश्यकता रहती थी कि रेलवे रिजर्वेशन के लिए उनको यहां तक आना पड़ता था अगर उसकी व्यवस्था वहां हो जाए तो आज रामनगर कस्बे में VSAT के माध्यम से रेलवे रिजर्वेशन सुविधा का भी आरंभ करने का यहां पर एक समारोह हो रहा है। एक प्रकार से इस एक मंच पर से देश के लिए एक योजना और काशीवासियों के लिए उस योजना के समेत कुल सात योजनाओं का लोकार्पण करते हुए मुझे गर्व हो रहा है।

मैं काशी बहुत बार आता था। पार्टी कार्यकर्ता के नाते संगठन का काम करने के लिए आता था, इस धरती का एक आकर्षण था उसके लिए भी आता था, लेकिन हर बार ऊपर की तरफ नजर करता था तो मैं चौंक जाता था। जहां भी देखो तार ही तार लगे रहते थे। इतने पुरातन शहर की शोभा उन तार के झुंड को देखते ही खराब हो जाती थी। तो जब मैं सांसद चुना गया और एक नागरिक अभिवादन था उसमें मैंने कहा था भाई इसको तो हटाना है। और आज मुझे खुशी है कि 572 करोड़ रुपया पूरे काशी में एक नई ऊर्जा भर देगा। कभी-कभी बिजली बंद हो जाना, तार पुराने हो जाना, Transmission लाइनें खराब हो जाना, बाबा आदम के जमाने की चीजें लटकी पड़ी हुई हैं किसी को ठीक करने के लिए फुरसत नहीं है, गाड़ी चलती रहती है, ये खराब हुआ चलिए ठीक कर लो, उधर खराब हुआ, ठीक कर लो, patchwork का काम चलता रहा है। और ये मुसीबत सिर्फ बनारस की नहीं है। हिंदुस्तान के कई शहर हैं और जिसके कारण बिजली का line loss भी बहुत होता है, नागरिकों को परेशानी भी बहुत होती है, और इसलिए बिजली को पहुंचाने वाला जो पूरा Infrastructure है उसको आधुनिक बनाने की आवश्यकता है, Smart बनाने की आवश्यकता है। और एक प्रकार से बनारस को जो Smart City बनाने की कल्पना है उसकी पहली शुरुआत ये बिजली के माध्यम से हो रही है। और ये बनारस, आज जो पसंद किया गया है, पूरे देश की योजना को लागू करने के लिए, लोगों को लगता होगा कि प्रधानमंत्री यहां से MP है इसलिए हो रहा है। मैं रहस्य बता देता हूं। ये कारण तो बाद में आता है। पहला कारण ये है कि हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनके पिताजी बनारस में इंजीनियर हुए, BHU में। वो यहीं पढ़ते थे और यहीं से इंजीनियर बने थे और यहीं से समाज सेवा के

लिए भी निकले थे, तो स्वाभाविक रीत है पीयूष जी को लगा होगा कि जो आपके पिताजी की शिक्षा-दीक्षा भूमि रही है वहीं से इस कार्यक्रम को आरंभ किया जाए, ताकि पिताजी को भी संतोष होगा और इसलिए आज बनारस से पूरे देश को ये नजराना मिल रहा है। पूरे देश में इस योजना के पीछे 45 हजार करोड़ रुपया लगने वाला है और उसके कारण ऊर्जा के क्षेत्र में जो धांधलियां चल रही हैं, जो परेशानियां चल रही हैं उनसे शहरी क्षेत्र को बहुत बड़ी मुक्ति मिलने वाली है। काम बड़ा है, काम कठिन है, लेकिन इसको किए बिना कोई चारा भी नहीं है और इसलिए क्योंकि हमारा एक सपना है कि 2022, जब देश आजादी के 75 साल मनाएगा। जब आजादी के 75 साल हम मनाएंगे तब जिन्होंने हमें आजादी दी, जो आजादी के लिए फांसी के तख्त पर चढ़ गए, जिन्होंने आजादी के लिए जवानी जेलों में खपा दी, जिन्होंने आजादी के लिए अपने शरीर पर ब्रिटिश सल्तनत के कोड़े झेले उनको हम जवाब क्या देंगे। यही देंगे कि आपने हमें आजादी दी, हमने मौज की। लेकिन जो सपना आपने देखा था वो तो हमने पूरा नहीं किया, ये बात तो हमें मंजूर नहीं हो सकती। क्या किसी हिन्दुस्तानी को ये बात मंजूर हो सकती है? क्या आजादी देने वाले को उनके सपनों के अनुकूल देश बनाके देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आजादी के 75 साल जब मनाए, तब देशवासियों का योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक अच्छा हिन्दुस्तान, देशभक्तों के सपनों का हिन्दुस्तान पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसमें एक महत्वपूर्ण काम है 24 घंटे, 365 दिन बिजली। आज बिजली चार घंटे, छ घंटे, आठ घंटे मिलती है। हमारा सपना है गांव हो, जंगलों का इलाका हो, दूर-सुदूर एक झोपड़ी हो, 2022 जब आजादी के 75 साल हो तब गरीब से गरीब के घर में भी 24 घंटे बिजली मिलती हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए एक महत्वपूर्ण काम उसके infrastructure का जिसमें आज 45 हजार करोड़ रुपया और अकेले काशी के लिए 572 करोड़ रुपया लगाकर के ये बदलाव का आज प्रारंभ हो रहा है।

मुझे आप सब के आशीर्वाद चाहिए। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद चाहिए ताकि, ताकि देश में ये ऊर्जा पहुंचाने का काम, देश को ऊर्जावान बनाने के लिए एक बहुत बड़ी नींव का पत्थर बना रहे, उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बनारस बढ़ता चला गया। अगल-बगल के जिलों से जो भी यातायात है, शहर के बीच से गुजरना पड़ता है। शहर के ट्रैफिक के मामले भी बड़े गंभीर है। परेशानियों का तो हिसाब लगाओ तो बढ़ती ही जाती है। उससे मुक्ति दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण काम था यहां रिंग रोड बनना चाहिए ताकि बाहर से जिसको गुजरना है शहर को disturb किए बिना वो काम चलता रहे। बहुत बड़ा काम है, करीब 600 करोड़ रुपयों का काम है। आज उसका भी शिलान्यास हुआ है और इस इलाके में काशी के साथ अगल-बगल के जितने जिले हैं उन जिलों को जोड़ने वाले रास्ते भी बनाने हैं ताकि उन सभी गांवों का लाभ हो। करीब-करीब 11 हजार करोड़ रुपया उसके लिए आबंटित करने का निर्णय किया गया है। आने वाले दिनों में अड़ोस-पड़ोस के जितने जिले हैं, काशी के साथ जुड़े हुए और तब जाकर के पूरा इलाका एक आर्थिक विकास का growth centre बन सकता है। एक बहुत बड़ा केन्द्र बन सकता है और इसलिए बिजली, पानी, सड़क ये तीन क्षेत्रों में हम इस प्रकार का यहां पर जाल बिछाएं ताकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के सामने सवालिया निशान होते हैं उससे हम मुक्ति दिला सके। उन बातों को बनारस की धरती से भले शुरू होते हो, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास इस जाल को फैलाने की दिशा में हमने काम को आरंभ किया है और आने वाले दिनों में देखते ही देखते उसके नतीजे दिखेंगे।

अभी आपने देखा, आप लोग भी घाट पर जाते हैं और LED की रोशनी आने के बाद तो मुझे बताया गया कि बहुत लोग जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कितना बड़ा बदलाव आया है। हम चाहते हैं हर परिवार में, मेरे काशी के हर परिवार में बिजली का बिल कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं कि बिजली का बिल कम हो? आप चाहते हैं आपके पैसे बचे? सचमुच में चाहते हो? तो मेरी एक बात मानोगे, पक्का मानोगे? वादा करो, भोले बाबा को याद करके वादा करो। आप अपने घर में जितने बल्ब है, ट्यूब लाइट है, LED लगा दीजिए। आप देखिए, आपका बिजली का बिल एकदम से कम हो जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे और रोशनी बढ़ जाएगी। ये double मुनाफा वाले काम है और पूरे भारत में मुझे आंदोलन खड़ा करना है कि पुराने जो बिजली के बल्ब है उससे मुक्ति लीजिए। ये नई technology है, जो हमारी आंखों के लिए अच्छी है, रोशनी के लिए अच्छी है और जेब के लिए भी अच्छी है। हम काशी में एक आंदोलन चलाए। सब लोग उस बात को आगे बढ़ाए तो काशी के अंदर भी हम इसका लाभ ले सकते हैं और मैंने देखा है street light. काशी की जो Street light है उन Street light को भी LED में convert करना है उसके कारण काशी महानगर पालिका का जो बिजली का बिल है वो भी बहुत कम हो जाएगा और वो जो पैसे बचेंगे वो काशी को अगर स्वच्छता के लिए लगा दिए गए तो मेरा काशी चमकता रहेगा। शाम को रोशनी से चमकेगा और दिन में सफाई से चमकेगा और दुनिया के लोग आएंगे तो एक नई काशी को देखकर के जाएंगे।

मैं काशीवासियों का आज हृदय से एक बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं जब चुनाव जीतकर के यहां आया था और गंगा आरती में बैठा था। मां गंगा के आशीर्वाद लेकर के मैं यहां से गया था, बाद में प्रधानमंत्री पद के शपथ लिए थे। पहले मैं आज इस धरती को नमन करने आया था और उस दिन मैंने कहा था, उस दिन मैंने कहा था कि बनारस के नागरिकों ने बनारस की सफाई की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। बनारस के नागरिकों ने बनारस को साफ-सुथरा रखना चाहिए। ये बात मैंने कही थी। आज देश में इस प्रकार की बात करना सरल नहीं होता है। लेकिन मैंने

देखा कि बनारस के लोगों ने मेरी इस बात को सर आंखों पर लिया और बनारस के नागरिकों के अनेक संगठन तैयार हुए, अनेक नौजवान तैयार हुए। महिलाएं, लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, इन लोगों ने बनारस को साफ बनाने का, स्वच्छ रखने का एक बड़ा अभियान उठाया है और उस अभियान के तहत बनारस को आगे सुंदर बनाने का काम चल रहा है।

मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आज बनारस विकास की नई ऊंचाइयों पर जाने का एक केन्द्र बिन्दु बना है। चाहे road का infrastructure हो, चाहे रेल का infrastructure हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे skill development का काम हो, चाहे हमारे बुनकरों के कल्याण का काम हो, इन सभी विषयों पर आज बनारस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक बड़ा अभियान आज हमने प्रारंभ किया है और इसी काम के लिए आज मुझे यहां आने का अवसर मिला।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के द्वारा इस देश के गरीबों को बैंक account के द्वारा आने वाले दिनों में एक आर्थिक व्यवस्था के मूल केन्द्र में लाने में है। एक बड़ा सफल प्रयास हुआ है। मुझे विश्वास है कि इसके कारण आने वाले दिनों में परिवर्तन आएगा।

पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को लेकर के एक परिस्थिति पैदा हुई है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि मामला क्या है, उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है। कोर्ट ने मौखिक सूचना दी है, लेकिन लिखित ऑर्डर नहीं आया है। आज मैंने शिक्षा मित्रों के कुछ नेताओं को बुलाया था। उनकी समस्या समझने का मैंने प्रयास किया और मैंने उनको कहा कि आप जरा मुझे बताइए तो उनकी भी तकलीफ थी कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। कोर्ट क्या कहना चाहती थी वो भी जानकारी नहीं थी। मैंने उनसे कहा है कि कोर्ट का ऑर्डर आते ही मेरे पास भेजिए। भारत सरकार भी इसका अध्ययन करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार को जो हमें सुझाव देने होंगे वो भी हम सुझाव देंगे। लेकिन मैं शिक्षक मित्रों से आज एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने सुना था कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की। मैं आज, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है और हम अपने जीवन को संकट में डाले तो समस्या का समाधान नहीं होता है। शिक्षक मित्र, आत्महत्या करके वो तो चला जाएगा, लेकिन बाद में उस परिवार का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा और इसलिए मेरी मेरे शिक्षक मित्रों से अनुरोध है कि जीवन में कभी लड़ाई हारनी नहीं चाहिए, हौसला खोना नहीं चाहिए। आत्महत्या का मार्ग हमारा नहीं हो सकता। एक बार कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहना चाहती है, उसको देखकर के जरा सुने। मैं भी समझने का प्रयास करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे जो भी बात करनी होगी उसको मैं करने की जिम्मेवारी लेता हूं और मैं आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार को आपके MP के नाते मैं अवश्य पहुंचाऊंगा और मुझे विश्वास है कि मेरे शिक्षक मित्र जो विद्यार्थियों के जीवन को तैयार करते हैं, जो विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करते हैं। जो विद्यार्थियों को जीने की प्रेरणा देते हैं उनके जीवन में आत्महत्या का मार्ग कभी उचित नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इन संवेदनशील मामलों को पूरी तरह गंभीरता से लेती है, ऐसा मुझे विश्वास है और इसलिए कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं मानता हूं कि आपके साथ अन्याय करना चाहेगी और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंगा। समाधानकारी रास्ते क्या हो सकते हैं, इसका मार्ग खोजा जाएगा। भारत माता की।

भाइयों-बहनों आज काशी में tourism को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। आज प्रातः मैंने tourism को बल मिले उस प्रकार की रिकशाओं का भी लोकार्पण किया है। वो अपने आप में भविष्य में tourist सेंट्रों के लिए एक मॉडल बनने वाला है। हम यहां के छोटे-छोटे लोगों को भी उस काम में जोड़ना चाहते हैं। आपने जब मैं बनारस आया तो बनारस के कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि 7 अगस्त को Handloom Day घोषित करना चाहिए। बनारस के बुनकरों की मांग थी। आज मुझे गर्व से कहना है कि आज उसने हमें हैंडलूम दिवस घोषित कर दिया। चेन्नई के अंदर उसका बड़ा समारोह किया और मेरे काशी के बुनकर चेन्नई आए थे और उनका भी मान-सम्मान बढ़ाने का मुझे अवसर मिला था।

काशी की जो शक्ति है वो उसकी कलाकारी की विधि है। काशी की जो संस्कृति है वो उसकी कला विधि में है। काशी की जो शक्ति है वो उसकी संगीत की विरासत में है। काशी को आगे तो बढ़ना है, काशी को आधुनिक भी बनना है। लेकिन साथ-साथ काशी को अपनी इस विरासत को भी अपने साथ बचाए रखना है। इसको भी बचाए रखना है और उसको लेकर के हम काशी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अनेक क्षेत्रों में आपने देखा होगा हमारे केन्द्र के ढेर सारे मंत्री बारी-बारी से आए हैं। अनेक नई योजनाओं को उन्होंने बल दिया है। उन्होंने अनेक नई योजनाओं का एक cumulative effect होने वाला है कि काशी एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

और मैं काशीवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने मुझे MP बनाया है और आप ही के लोग हो, जिनके कारण आज मुझे प्रधानमंत्री पद पर बैठने का और देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। देश चहुं और विकास कैसे करे, देश में नौजवानों को रोजगार कैसे मिले और हो सके तो अपने ही इलाके में रोजगार कैसे मिले, उसको लेकर के skill development का एक बहुत बड़ा अभियान जिसके कारण देश के कोटि-कोटि नौजवान, जिसके हाथ में डिग्री का कागज तो



होता है, लेकिन हाथों में हुनर नहीं होता है और सिर्फ कागज से गाड़ी चलती नहीं है। उसके हाथ में हुनर होना चाहिए, कौशल्य होना चाहिए। दुनिया में हम सबसे युवा हैं। 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है उन भूजाओं में अगर कौशल्य हो, तो पूरी दुनिया को महारत करने की ताकत हिन्दुस्तान के नौजवान में आ जाती है और इसी बात को लेकर के skill development के द्वारा पूरे देश में एक विकास की नई ऊंचाई बनाने के लिए हमने प्रयास किया है।

आपने देखा होगा मैंने 15 अगस्त को लाल किले पर से एक घोषणा की थी और मैंने कहा था ये जो interview नाम की चीज है। driver चाहिए तो भी interview, peon चाहिए तो भी interview, छोटा clerk चाहिए तो भी interview और उसके कारण लाखों नौजवान रोजगार के लिए किसी न किसी की सिफारिश ढूँढते हैं। कोई न कोई बिचौलिया उनके हाथ लग जाता है और नौकरी मिले या न मिले उसका जेब तो काट ही लेते हैं। और छोटी जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में interview होते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में लोग भर्ती करने पड़ते हैं। अगर एक-एक व्यक्ति से 5-5, 10-10 हजार रुपया भी लूटना शुरू करे तो गरीब आदमी के 10 हजार रुपया, वो जीवन भर का कर्जदार बन जाता है और इसलिए मेरी सरकार ने एक मैंने 15 अगस्त को सुझाव दिया था कि interview नाम की चीज बंद होनी चाहिए। और आज मैं नौजवानों को कहता हूँ कि मेरी सरकार उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। कुछ department ने already काम चालू कर दिया है। अभी दो दिन पहले मुझे रेलवे वालों ने बता दिया कि उनकी एक level के नीचे की जो भर्ती है, बोले बिना interview लिए हम online exam लेकर के पूरा कर लेंगे। हमारे नौजवान को रोजगार के लिए इस प्रकार से परेशानियाँ भुगतनी पड़े और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में भी जो बुराईयाँ घुस गई हैं उसकी सफाई होके रहेगी ये मैं नौजवानों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ।

हम सबने मिल करके जन-भागीदारी से देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। आज पूरा दिन मैंने जो बिताया है, एक एक मिनट सिर्फ और सिर्फ विकास की बातों पर ही मैंने लगाया है। जब से मैं यहां Land किया हूँ हर विषय जिनसे मिला जिनसे बातें कीं और आज मैं बनारस के सभी जीवन के क्षेत्र के लोगों से मुझे मिलने का सौभाग्य मिल गया है। बहुत बातें उनसे की मैंने। पूरे दिन भर उनकी बातें सुनता रहा। उनसे विषयों को समझता रहा और केंद्र बिंदु सिर्फ विकास था। और मेरा ये विश्वास है कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान भी सिर्फ एक ही बात से होने वाला है, उस बात का नाम है विकास। अगर विकास होगा तो रोजगार मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे तो गरीबी से लड़ाई लड़ पाएंगे, रोजगार मिलेंगे तो बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। रोजगार मिलेंगे विकास की नई ऊंचाईयाँ होंगी, व्यवस्थाएं विकसित होंगी और इसलिए सरकार व्यवस्थाओं को भी विकसित करना चाहती है और नागरिकों को सामर्थ्यवान भी बनाना चाहती है। आर्थिक सामर्थ्य देना चाहती है, शैक्षणिक सामर्थ्य देना चाहती है, आरोग्य की दृष्टि से अच्छे दिन आएँ उसके जीवन में, उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है।

आज पूरे विश्व ने भारत की जय-जयकार करना शुरू किया है ये पहले नहीं था। पूरी दुनिया भारत के प्रति देखने को तैयार नहीं थी। अभी हमने जून महीने में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस- इसका हमने विश्व के समाने प्रस्ताव रखा। हर हिन्दुस्तानी को खुशी होगी और बनारस वालों को ज्यादा खुशी होगी क्योंकि वो चीजें हैं जो बनारस की धरती से पनपी हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किया और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को दुनिया के hundred and ninety three countries, 193 देशों ने उसको समर्थन किया और विश्व के सभी देशों ने योगा दिवस को मनाया। ये सिर्फ योगा दिवस को मनाना मतलब हाथ-पैर हिलाने वाला मसला नहीं है भारत के साथ जुड़ने का मसला है। ये योग विश्व को भारत के साथ योग करता है जुड़ाता है। ये वो योग है जो हमें जोड़ रहा है, एक ही बात कितना बड़ा बदलाव ला सकती है इसके उदाहरण हैं। आज पूरा विश्व भारत के प्रति आशा की नजर से, गर्व की नजर से देख रहा है। और इसी बातों से देश को नई ऊंचाईयाँ पर ले जाने में एक अवसर पैदा होता है और उस अवसर की पूर्ति के लिए हम दिन-रात कोशिश कर रहे हैं। मां गंगा की सफाई का अभियान पांचों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ ले करके जहां से गंगा गुजरती है, सभी पांचों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ ले करके उस योजनाओं को लागू कर रहा हो और मैंने एक ही आग्रह किया है कि बाकी कुछ आप कर पाओ के न कर पाओ कम से कम गंगा में अब गंदगी नहीं चाहिए, गंदगी जानी नहीं चाहिए, कोई भी शहर अपना गट्टर का पानी गंगा में जाने न दे इतना प्रबंध राज्य सरकारों ने करना चाहिए। उसके लिए दंड देना पड़ेगा दें, दंड देने के लिए तैयार हैं। अभी माता अमृतानंदमयी केरल में है, आश्रम केरल में है लेकिन मां गंगा के लिए 100 करोड़ रुपयों का दान दे दिया। सवा सौ करोड़ देशवासियों के दिल में मां गंगा के प्रति इतना भक्ति है, सब देशवासी गंगा के लिए कुछ न कुछ करने के लिए तैयार हैं लेकिन शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। जिम्मेवारी हमें लेनी पड़ेगी। राज्यों के पास जो दायित्व हैं उसको राज्यों को पूरा करना पड़ेगा। और भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके राज्यों के साथ काम करेगी और मां गंगा की सफाई का काम हमें समय-सीमा में पूरा करना है।

मैं जानता हूँ ये काम कठिन है। 1984 से nineteen eighty four से ये विषय चल पड़ा है। हजारों करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और इसलिए योजना की सफलता के प्रति आशंकाओं का कारण भी है। उसके बावजूद भी हमने अपने प्रयास छोड़ने

नहीं चाहिए। हमने इतने बड़े देश ने इस एक काम को करके दिखाना चाहिए। और गंगा शुद्ध हो, गंगा साफ हो, गंगा गंदगी से मुक्त हो इस गंगा के बेटे के नाते हम सबका दायित्व बन जाता है और उस दायित्व को हम सबने निभाना चाहिए।

और मुझे विश्वास है भाइयो एक जागरूकता आई है। स्वच्छता का अभियान देख लीजिए, एक जागरूकता आई है, एक बदलाव आया है। घर में बच्चे भी कूड़ा-कचरा फेंकने वालों को टोकते हैं ये पहले कभी नहीं होता था। स्वच्छता एक दिन में आने वाली ऐसा कोई सोचता नहीं था। पहले भी कोई सोचता नहीं था। लेकिन पहली बार मैं नहीं मानता हिंदुस्तान की संसद ने स्वच्छता के ऊपर कभी debate की हो। लेकिन जबसे मैंने स्वच्छता अभियान चलाया है आज संसद भी स्वच्छता के विषय पर चर्चा करती है, विपक्ष में बैठे हुए हमारी आलोचना भी करते हैं, लेकिन कम से कम भारत की संसद को स्वच्छता के लिए बात करने के लिए फुरसत तो मिली। ये छोटी बात नहीं है और संसद, संसद स्वच्छता के लिए इतनी जागरूक हो जाए तो बात नीचे पहुंचेगी ये मेरा पूरा विश्वास है भाइयो।

हमारे देश में विकास के लिए दो शब्द हम हमेशा देखें हैं आर्थिक विकास औद्योगिक विकास। एक शब्द प्रयोग चलता है private sector, दूसरा शब्द प्रयोग चलता है public sector. यानी government के जो PSUs हैं वो हैं, या तो कॉरपोरेट हाउस हैं बड़े-बड़े उद्योग कार हैं। ये हमने आर्थिक जो विकास की पटरी है वो इन दो पटरी पर आर्थिक गाड़ी चलाने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं ये दो पटरी पर जितनी गाड़ी तेज जानी चाहिए जा नहीं सकती है। Public Sector, Private Sector इन्हीं दो पिलर पर अगर हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उतनी ताकत नहीं मिलेगी। और इसलिए मैं तीसरे सेक्टर पर बल दे रहा हूं। एक तरफ है Public Sector, Private Sector और मैं एक विचार ले करके चल रहा हूं, Personal Sector, एक individual भी देश की बहुत बड़ी अमानत है। ये Personal Sector कैसे आगे बढ़े? Private Sector, Public Sector की बराबरी में Personal Sector दो कदम आगे कैसे चले उस योजना को ले करके मैं काम कर रहा हूं।

और उस Personal Sector में आता है एक योजना हमने बनाई है मुद्रा बैंक की। हमारे देश में करीब 6-7 करोड़ लोग हैं जो छोटे और निम्न स्तर के व्यापारी हैं। छोटा-मोटा उद्योग चलाते हैं। एकाध-दो एकाध लोगों को रोजगार देते हैं। छोटा कारोबार चलाते हैं, लेकिन किसी के पास हाथ फैलाते नहीं, अपने बलबूते पर खड़े रहते हैं। इन लोगों की ताकत इतनी है कि करीब-करीब 15 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, ये छोटे-छोटे लोग। दूध बेचने वाला भी एकाध बच्चे को इनको रोजगार देता है। अगर ये personal sector है। ये personal sector को अगर ताकत दी जाए। जो आज 15 करोड़ को नौकरी देता है वो कल 30 करोड़ को नौकरी दे सकता है, इतनी ताकत उसमें है। और इसलिए बाल काटने वाला हो, धोबी हो, चाय बेचने वाला हो, पकौड़े बेचने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, फ्रूट बेचने वाला हो, छोटे-मोटे दुकान पर readymade कपड़े बेचता हो, प्रसाद बेचता हो छोटे-छोटे लोग। इस personal sector को ताकतवर बनाना है मुझे। उसको आर्थिक मदद करनी है और मुद्रा बैंक से किसी भी प्रकार की गारंटी के बिना 10 हजार से 50 हजार रुपए तक देना उस नागरिक को देना ताकि उसको साहूकार की ब्याज की चुंगल से बाहर निकले और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उस दिशा में एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। ये personal sector भारत के लिए बहुत बड़ी आर्थिक moment बन सकता है। हमने 50 साल तक private sector, public sector की बात की है, अब वर्तन है हम personal sector पर बल दे और personal sector के द्वारा एक-एक व्यक्ति की उद्यमशीलता। उसको पैसे चाहिए पैसे दे, technology चाहिए technology दे, skill development करना है तो skill development दे, उसको नौजवान की जरूरत है, नौजवान दे, उसको उद्योग जगाने के लिए जगह चाहिए तो जगह दे, व्यापार करने के लिए अवसर चाहिए तो अवसर दे। पूरा खुला पल्ला दें, आप देखिए हिन्दुस्तान का ये सामान्य व्यक्ति, हिन्दुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।

और इसलिए आज मैं काशी की धरती पर पहली बार ये personal sector के विषय को मैं प्रकट कर रहा हूं और आने वाले दिनों में इस personal sector काशी की धरती से आशीर्वाद लेकर के सवा सौ करोड़ देशवासी, 65 प्रतिशत लोग, 35 से कम आयु के लोग वो personal sector है जिसको एक ताकत देकर के मुझे देश को आगे बढ़ाना है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।  
बधुत-बहुत धन्यवाद।

\*\*\*

अतुल कुमार तिवारी/ अमित कुमार / निर्मल शर्मा / मनीषा

**पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय**

19-अक्टूबर-2015 20:16 IST

**आईडीएफसी बैंक के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ**

मैं आईडीएफसी बैंक को बधाई देता हूँ कि 18 साल की यात्रा कोई बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन 18 साल की इस छोटी सी यात्रा में भी भारत के नक्शे पर अपनी एक जगह बनाई है। लेकिन अब तक जो उन्होंने जगह बनाई थी वो ईंट, चूना, माटी, पत्थर, तार इसी के द्वारा बनाई थी। कभी रोड बनाएं कभी बिल्डिंग बनाएं, कभी port बनाए लेकिन अब वो जीवन निर्माण की दिशा में कदम रख रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि 18 साल में जो चुनौतियां आपको मिली हैं, अब शायद ज्यादा चुनौतियां आपके सामने हैं। क्योंकि वो एक limited clientele होता है और आपको अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है। और कुछ चीजें उसमें assured होती हैं, पहले से पता होता है कि भई इस Project का क्या होगा, क्या refund होगा, क्या revenue होगा, बैंक की क्या स्थिति रहेगी। ये वो क्षेत्र नहीं है। और इसलिए एक इंजीनियर का काम सरल होता है, लेकिन एक शिक्षक का काम बड़ा भारी होता है क्योंकि शिक्षक को जीवन तैयार करना होता है, इंजीनियर को इमारत बनानी होती है। IDFC अब तक जो काम करती थी अब उसको शिक्षक का रोल भी अदा करना होगा और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये चुनौतियों के बावजूद भी, एक सही दिशा में कदम होगा।

ये बैंक का मूल उद्देश्य तो गांव में जाना है और मैं मानता हूँ ये देश का दुर्भाग्य है कि देश को नियम बनाना पड़ा कि 25% जब तक आप बैंक में गांव नहीं खोलते हैं आपको permission नहीं मिलेगी। मैं मानता हूँ ये नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन पड़ी। क्योंकि हम लोगों ने कभी भी हमारे ग्रामीण जीवन के potential को समझा नहीं और urban life, governments, government machinery, वहां पर इन कारोबार को चलाने के लिए बहुत अवसर होता है और इसलिए एक प्रकार से बैंक को चलाना, बैंक का growth continue करना ये ज्यादा challenging work नहीं है और इस तरफ ध्यान नहीं गया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये ध्यान में आया है और हर किसी की नजर गई है कि भारत में ग्रामीण जीवन भी एक बहुत बड़ा growth centre बना है। आपको मालूम होगा जब telecom industry आई और उनको जब भी spectrum दिया जाता था और गांव की बात कहते थे तो आगे-पीछे, आगे-पीछे होते थे। या तो किसी को sub-contract दे देते थे और अपनी गाड़ी चला लेते थे। लेकिन जब गांव में गए तो उनके लिए surprise था कि telecom के growth का शहरी percentage से ग्रामीण percentage ज्यादा ऊंचा था। Spread भी ज्यादा था, गति भी तेज थी। और इस अर्थ में उनके लिए वो.. अच्छा! गांव के व्यक्ति का communication ज्यादातर अन्य शहरों से होता है, इसलिए Income का level भी ज्यादा था। शहर का गांव, शहर में ही शहर में करता था, लेकिन उनका Income level....लेकिन ये बातें उनको ध्यान आई, बाद में जाने के बाद। मैं समझता हूँ बैंकिंग sector के लिए भी अब ये अनुभव आने वाला है। बहुत तेजी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत के जीवन को एक ताकत दे रही है। बड़ा बदलाव आ रहा है।

एक बात और भी है, जैसे अरुण जी ने बड़ा विस्तार से बताया कि अब, अब banking जीवन बदल चुका है, अब वो mobile banking ही चलने वाला है। premises-less, paper-less, ये ही बैंक की पहचान होने वाली है। न जिसमें कोई premises होगा और न ही कोई paper होगा। और उसके बाद भी बैंक चलेगी, लोगों को पैसे मिलेंगे, लोगों का कारोबार चलेगा। और धीरे-धीरे हमारे देश में ये स्थिति आने वाली है कि currency भी, शायद आज जो currency print करने का खर्चा होता है, वो भी धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कम होता जाएगा क्योंकि ये कारोबार इस प्रकार से बढ़ने वाला है। और हमने भी देश को उस दिशा में ले जाना है। और जैसे-जैसे हम technology के सहारे banking करेंगे, जब हम paper-less bank की व्यवस्था करेंगे, currency-less कारोबार चलाएंगे तो काले धन की संभावनाएं धीरे-धीरे-धीरे जीरो की तरफ चली जाएंगी। और इसलिए इस सारी व्यवस्था का उपयोग एक उस दायरे में होने वाला है जो देश की मूलभूत कुछ बातें हैं जिसको address करने वाला है। IDFC उसकी beginning कर रहा है। मध्यप्रदेश से उनका प्रारंभ हो रहा है, वो भी उस इलाके, जो एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नर्मदा के तट के साथ जुड़े हुए हैं, वहां से इस काम का आरंभ हो रहा है। ये भी आवश्यक है।

आज सारा विश्व आर्थिक दृष्टि से भारत के प्रति एक बड़े संतोष की नजर से देख रहा है, सिर्फ आशा की नजर से नहीं, एक संतोष की नजर से। और उसको लगता है कि पूरे विश्व में इतना turmoil आ रहा है लेकिन एक भारत है जो स्थिर खड़ा रह पाया है और global economy में भी किसी राष्ट्र का स्थिर economy को handle करना ये भी अपने-आप में विश्व में संतुलन बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। और वो भूमिका भारत ने इस पूरे वैश्विक संकट के

समय अदा की है। इतने बड़े तूफान के बीच भारत अपने आप को बना पाया है। और बना पाया है तो आगे बढ़ने की संभावना भी उसमें बहुत ज्यादा है।

विश्व भारत के संबंध में ये अनुमान लगाता है कि भारत का potential इतना अपरम्पार है अभी तक आप tap नहीं कर पाए। लोग ये नहीं करते हैं कि भई आप कैसे आगे बढ़ोगे, आप कुछ टिक पाओगे के नहीं पाओगे, बचोगे कि नहीं बचोगे, ये चर्चा नहीं। चर्चा ये है, अरे भाई इतना मौका है, आप, आप ठंडे क्यों ? ये सवाल पूछा जा रहा है। यानी सारे विश्व को लग रहा है कि आज विश्व के आर्थिक जीवन में सबसे अगर कोई potential area है जहां growth story है तो वो हिंदुस्तान में है। और हमने भी देखा है World Bank हो, IMF हो, बाकी जितनी Rating Agencies हों, सबने कहा है कि भारत आज दुनिया की, बड़े देशों की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली कम्पनी है। अगर ये ताकत हमारे पास है, तो हमारा काम है कि हम foundation को भी मजबूत करें और vertical भी जाएं। Horizontal and vertical, दोनों तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और Horizontal जाने के लिए ये ग्रामीण जीवन में हम कैसे प्रवेश ? हमारा व्याप कैसे बढ़ाएं? उसी प्रकार से हम नए-नए क्षेत्रों को कैसे चुनें? अगर हम priority sector देखें, priority sector को पैसे देना, ये सरकार के कुछ नियम हैं, जाते हैं लेकिन मान लीजिए कहा गया कि भाई agriculture sector को पैसा देना है, लेकिन एक fertilizer कारखाने को दे दिया, माना जाएगा agriculture sector और हिसाब ठीक हो जाएगा तो agriculture sector को दे दिया। इससे हमें बाहर आना है। हम एक सामान्य agriculturist को या गांव को ध्यान में रख करके या दो, चार, दस गांव के बीच में cold storage कैसे बनें? Warehousing की व्यवस्था कैसे हो? उसमें banking कैसे? हम value addition में कैसे मदद कर सकते? हम सिर्फ agriculture sector को पकड़ें, आज मैं समझता हूं कि इतनी संभावनाएं पड़ी हुई हैं, हिन्दुस्तान का किसान आज दुनिया के साथ अपने-आप में तालमेल करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा, कि एक महिला अपना नम्बर अंग्रेजी में बता रही थी, Mobile Number अंग्रेजी में बता रही थी। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने किसी स्कूल में जा करके पढ़ा होगा। लेकिन अब धीरे-धीरे करके सब चीजें समाज, जीवन में सहज हिस्सा बन रही हैं। ये इस ताकत को पहचानना, यही तो सबसे बड़ी खूबी है। हम इसको अगर ताकत मानते हुए, हां ये बदलाव है क्योंकि मेरा तो ये अनुभव है।

मैंने एक बार कहीं वर्णन भी किया था, मैं गुजरात में जब मुख्यमंत्री था तो एक बहुत ही पिछड़ा तहसील है हमारे यहां, धर्मपुर के पास, बलसाड़ जिले में, tribal belt है। अब मेरा मुख्यमंत्री रहते हुए वहां कभी कार्यक्रम नहीं हुआ था तो मैंने आग्रह किया, मैंने कहा मुझे वहां जाना है। न एक दिन कोई कार्यक्रम नहीं होगा तो ऐसे ही जा करके एक पेड़ लगा करके वहां से वापिस आऊंगा। तो फिर एक chilling centre के उद्घाटन के लिए कार्यक्रम बन गया। अब chilling centre क्या 50 लाख का होता है, छोटा सा क्या होता है, जो दूध लोग देने आते हैं, उसको, ट्रक आने तक उसको संभालते हैं। इतना ही होता है। मैंने कहा मैं उसके लिए जाऊंगा। फिर वहां करनी थी तो जगह नहीं थी, क्योंकि जंगल है तो कोई जगह नहीं थी, तो एक स्कूल थी दूर, दो-ढाई किलोमीटर, स्कूल में function था। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने 50 करीब आदिवासी महिलाओं को बुलाया था। दूध भरने वाली जो महिलाएं होती हैं, 50 को बुलाया था। जहां chilling centre था, वहां। सब वहां तो अलग था माहौल। मैं हैरान था जब chilling center में उद्घाटन वगैरह हुआ, ये महिलाएं सारी मोबाइल से फोटो निकालती थीं। आदिवासी महिलाएं फोन से फोटो निकालती थीं। मुझे जरा surprise हुआ। मैं उनके पास गया। मैंने कहा ये फोटो निकाल कर क्या करोगे? उन्होंने जो जवाब दिया वो और आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा, हम इसको download करवा देंगे। अब ये download शब्द उनको मालूम था। download कैसे होता है, कहां होता है, ये पता था। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहां तक पहुंचे। इसको हम किस प्रकार से आने वाले दिनों में हमारी growth story का हिस्सा कैसे बनाए और उस दिशा में हम कैसे काम करें?

उसी प्रकार से हमारे नौजवान। उनको पढ़ाई के लिए सरलता से Bank loan की व्यवस्था क्यों न हो? मेरा मत है ये women self-help groups....Women self-help group को पैसा मिलता है, अगर उनको बुधवार को पैसा जमा करवाना है 100 रुपए तो मंगल को आकर के दे जाते हैं कि लीजिए साहब मेरा पैसा कल पता नहीं कहीं और खर्च हो जाएगा। ये sensitivity है हमारे यहां, ग्रामीण जीवन में। इसका जितना लाभ लेना चाहिए हमने लिया नहीं और साहूकारों ने इस पर अपनी पकड़ जमा दी और उसने हमारी economy को भी बहुत बड़ा नुकसान किया है। तो हमने एक विश्वास पैदा करना है, एक गारंटी पैदा करनी है। मैं समझता हूं ये जो प्रयास है, वो प्रयास उस परिणामों को जरूर अवश्य फल देगा।

Banking sector में हमारी ये कोशिश रही है कि bank nationalize हुई। तब तो बताया गया था कि भई गरीबों के लिए हुआ, लेकिन हमने जो देखा कि वो बहुत सीमित रहा। जैसे मध्यम वर्ग के परिवारों तक family doctor होता है, वैसे उच्च परिवारों का एक Banker होता है। बड़े ऊंचे घरानों का और बीमार भी होंगे लेकिन अगर Banker ने कहीं lunch-dinner रखा है तो जरूर जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि भई इसका उनका कारोबार कितना महत्वपूर्ण है। ये अच्छा है, बुरा है लेकिन है। मैं समझता हूं कि अब हमारे यहां Neo-Middle Class कहो या मध्यम वर्ग कहो, ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है। हम उनकी तरफ ध्यान केन्द्रित करके, ऐसी व्यवस्थाओं को कैसे विकसित करें। मान लीजिए आप, आपके सामने

दो proposal है। एक है कि कोई भवन बनाना है, सरकारी दफ्तर बनाना है और दूसरी proposal है कि इसने प्राइवेट में कहा है कि मैं यहां एक कॉलेज खड़ा करना चाहता हूं, एक Higher-Secondary School चालू करना चाहता हूं, मुझे बैंक से पैसा चाहिए। अगर मैं बैंक में हूं तो मैं पहली priority उस स्कूल वाले को दूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां स्कूल बनता है तो फिर ऐसे 50 दफ्तर बनाने की ताकत उनसे अपने आप आ जाने वाली है। इसलिए हमारे investment की priority क्या बने? पैसे देने की priority क्या बने? ये अगर हमने chain शुरू की जिसके multiple हमें benefit हो। अगर ये होगा तो मैं मानता हूं कि बहुत ही लाभ होगा।

हमने जो financial inclusion का जो मिशन उठाया है। अब जैसे अरुण जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की जो हमने योजना बनाई जिसमें हमने मध्यम वर्ग, गरीब, धोबी हो, नाई हो, दूध बेचने वाला हो, अखबार बेचने वाला हो उसको मुद्रा योजना के तहत finance कैसे हो। इस देश में करीब 6 करोड़ लोग ऐसे हैं, इस प्रकार के काम में और उनका average कर्ज 17 हजार रुपए है। कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन वे ये पैसे साहूकार से लेते हैं, बहुत ब्याज देते हैं और वो अपना विकास-विस्तार नहीं कर पाते हैं। मुद्रा योजना के तहत हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों को इस ब्याज के चक्कर से मुक्ति दिलाना और उनको financial help liberally करना। हमने 50 हजार, 5 लाख, 10 लाख तक की, उसकी व्यवस्था की, 50 लाख तक की की। अभी तो मैं समझता हूं मुश्किल से 100 दिन हुए होंगे इस योजना को launch किए। अब तक 61 लाख clients and करीब 35 thousand crore rupees, ये वहां गया है। 35 हजार करोड़ रुपया बाजार के अंदर नीचे जाना मतलब economy को कितनी बड़ी ताकत देता है वो। 35 हजार करोड़ किसी एक शहर में डालने से उतना change नहीं आता है जितना कि हजारों गांवों के अंदर 35 हजार करोड़ रुपया जाता है, तो economy में एक vibrancy आना शुरू हो जाता है, नीचे से शुरू हो जाता है और ये आने वाले दिनों में देखेंगे और हमारी कोशिश यही है कि हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं।

हमारे देश में Banking sector के संबंध में पचासों प्रकार के सवालिया निशान उठे हैं। Appointment से लेकर के, governance से लेकर के, पैसे देने के संबंध में पचासों प्रकार के सवालिया निशान लगे हैं। हमने आने के बाद एक दिन round-table conference किया, चिंतन शिविर की, सभी बैंक के लोगों के साथ detail में चर्चा की। उनकी समस्याएं क्या हैं, सरकार से अपेक्षाएं क्या हैं, कानूनी मुसीबतें क्या हैं। सारी चीजों की विस्तार से चर्चा की। RBI भी मौजूद था, मैं भी था, अरुण जी भी थे, काफी विस्तार से चर्चा की और उसमें से जो बातें आईं उस बातों को हमने लागू करने का प्रयास किया है। हमने एक सप्तसूत्री योजना बनाई है, जिस योजना का मैं समझता हूं कि हमारे देश में ऐसी चीजों की चर्चा बहुत कम होती है। लेकिन इसका बहुत बड़ा निर्णय है और A B C D E F G, ये सप्तसूत्री मेरा कार्यक्रम है। ये सप्तसूत्री कार्यक्रम बैंकों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है।

एक है हमारा A - Appointments. बैंकों में उच्च पदों पर नियुक्तियों में सुधार लाने का हमने फैसला किया है और इसलिए हमने 1969 के बाद nationalised bank में private sector के लोगों को भी लिया है, वरना nationalised bank से लोग private में चले जाते थे। पहली बार ये reverse trend शुरू हुआ है, जिसमें efficiency को हमने महत्व दिया है।

B - B for Bank, Board, Bureau. ये B3 पहली बार हम इस देश में लाए हैं कि बैंकों में जो भी नियुक्तियां हुईं उसका selection top rank के लिए, ये board करेगा। Politically मुझे ये पसंद आया, उसको मैं एक director बना दूँ और वो वहां बैठ जाए और फिर बाद में जब loan देनी हो तो वाया उसी से आ जाए proposal और फिर पता चले भई ये तो PM का आदमी बोल रहा है, देना ही पड़ेगा। ये डूबने के पीछे कारण यही है और इसलिए हमने कहा है कि ये कतई हम नहीं करेंगे, सारे professional लोगों को हम इस काम में लगाएंगे।

C - Capitalization. पिछले कुछ वर्षों में दिए गए loans में bad loans हैं। उसके कारण संकट आया है। अब रोते-बैठने का कोई अर्थ नहीं है इसलिए हमने करीब आने वाले कुछ वर्षों में 70 हजार करोड़ रुपया बैंक के अंदर डालकर के ये bad loans के कारण जो संकट है, उसमें से हम बाहर लाने का कार्यक्रम कर रहे हैं।

D - De-stress of assets. कुछ क्षेत्रों में जहां ये समस्या गंभीर है, हमने import duties बढ़ाने का domestic producer को सहारा दिया है। आपने देखा होगा हमने Steel में अभी किया। ताकि जिसके कारण Steel जो बैंक के साथ Steel उद्योग पैसा लेता था, उसको एक ताकत मिले। तो हमने De-stress के लिए कई कदम उठाने की दिशा में काम किया है।

6 है -नए debt recovery tribunal. जिसमें हम bad loans recovery इन सारे कामों को मैंने कहा है जैसे Power sector. हम बहुत तेज गति से निर्णय पर जा रहे हैं। Power sector जो NPA की समस्या से जुड़ा हुआ है उसको कैसे

handle करना है।

E - Empower. Empower का मेरा सीधा-सीधा मतलब था, जब मैं पुणे में गया था इस मीटिंग में तब मैंने कहा था, Zero interferences. आपको political leadership और establishment से कभी फोन नहीं आएगा कि इसके loan का क्या करना है लेना, देना और आज तक इतने महीने हो गए, एक भी जगह से खबर नहीं आई है कि ऐसा कोई pressure है। purely, professionally चलाइए और बाहर लाइए। तो इस प्रकार से बैंकों को Empower करने की दिशा मैं हमने काम किया है।

F - Framework for accountability. बैंकों का performance monitor करने के लिए key performance indicator हमने set किए हैं ताकि हमें regularly पता चले कि भई कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं, वो नहीं। कितना तो संतोष कभी-कभी दे देता है, लेकिन कहां और कैसे और कितने समय में। उस दिशा में indicators को हमने बल दिया है। और last है G - Governance. हमारे banking sectorमें governance को बल देना है। हमने technology पर जाना है, transparency को लाना है। cyber crime की सबसे ज्यादा संभावनाएं banking sector, financial world में हैं या तो data चोरी करने की। ये दो ही सबसे बड़े क्षेत्र हैं और इसलिए हमको assure करना होगा हमारे governance को।

तो ऐसी सप्तसूत्री हमारी योजना के द्वारा इन seven pillars पर पूरा banking sector को ताकत कैसे मिले। सरकार ने इतने महत्वपूर्ण initiative लिए हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है बैंक कंधे से कंधा मिलाकर के उसके साथ चलेगा। कुछ क्षेत्रों में बैंक दो कदम आगे होगा और मैं समझता हूं कि ये ताकत ultimately भारत के जो निर्धारित लक्ष्य हैं और जिन माध्यमों से हैं, उन सबको मिलकर के हम पूरा कर सकते हैं।

आने वाले दिनों में IDFC को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं वो इस क्षेत्र में बहुत-बहुत प्रगति करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

\*\*\*

अतुल कुमार तिवारी/अमित कुमार/निर्मल शर्मा/मनीषा

पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय

24-नवंबर-2015 13:09 IST

---

भारत-सिंगापुर आर्थिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन का पाठ

श्री एस ईश्वरन, व्यापार और उद्योग मंत्री, सम्मानित मंत्रियों और प्रिय दोस्तों!

यह बहुत खुशी की बात है कि आज मैं आप के बीच हूँ। भारत-सिंगापुर आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी यह यात्रा बहुत लाभदायक और सकारात्मक रही है। आज सुबह सिंगापुर के नेताओं के साथ मेरी बैठकें बहुत बेहतरीन रही हैं।

हमने सामरिक भागीदारी पर जो निर्णय लिए हैं वे हमारे संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हमने इस रिश्ते के लिए महत्वाकांक्षा का एक उच्च स्तर निर्धारित किया है।

दोस्तों! हमारे ऐतिहासिक संबंध और सांस्कृतिक निकटता हमारी संपत्ति है। बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी सिंगापुर के जीवन और काम के माहौल को समृद्ध कर रहे हैं। हाल के वर्षों में आर्थिक संबंधों ने हमारे संबंधों में निर्णायक भूमिका निभाई है।

सिंगापुर, विश्व स्तर पर हमारा 10वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। आसियान देशों में यह दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। 2005 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के बाद द्विपक्षीय व्यापार में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। भारत में विदेशी निवेश के स्रोत के रूप में सिंगापुर दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है। हाल के दिनों में सिंगापुर में भारतीय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी काफी बढ़ा है। सिंगापुर अब भारतीय निवेश के लिए शीर्ष स्थलों में से एक है।

भारतीय कंपनियाँ बड़ी संख्या में सिंगापुर में पंजीकृत हैं। पिछले कुछ दशकों में भारतीय बाजार की मौजूदगी की वजह से सिंगापुर की कंपनियों का भी भारतीय बाजार के साथ एक अपनेपन का रिश्ता बना है। हमारी कंपनियाँ बेहतरीन सेवा देने की स्थिति में हैं। दोनों ही तरफ से बड़ी संख्या में कंपनियों की बढ़ती हुई भागीदारी और दोनों देशों के बाजारों में विदेशी कंपनियों की मौजूदगी से मैं और भी रोमांचक भागीदारी की उम्मीद करता हूँ।

• आप को सुनिश्चितता की आदत है; भारत में विस्तार के लिए गुंजाइश है;

• आप उर्ध्वधर बढ़ने के शौकीन हैं; भारत का विकास ऊर्ध्वधर और क्षैतिज दोनों दिशाओं में है।

• आप एक रोमांचक इनक्यूबेटर हैं; भारत एक विशाल प्रयोगशाला है।

इस प्रकार, सिंगापुर और भारत कई संभावनाओं वाले क्षेत्रों में एक साथ काम कर सकते हैं।

पिछले महीने मुझे सिंगापुर के सहयोग से शुरू होने वाली दो परियोजनाओं की आधारशिला रखने का अवसर मिला। पहली है, आंध्र प्रदेश की नयी राजधानी है- अमरावती। सिंगापुर इस नये शहर के मास्टर प्लान के निर्माण में जुड़ा है। दूसरा, मैंने मुंबई के जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर चौथे कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी जो पीएसए सिंगापुर की साझेदारी से बनाया जा रहा है। हम भी चांगी हवाई अड्डे के सहयोग से दो भारतीय हवाई अड्डों को संचालित करने का अवसर तलाश रहे हैं। ये हमारी आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने के हाल के उदाहरण हैं।

सिंगापुर भी हमारे वैश्विक दृष्टिकोण में भारत का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान दोस्त है। हमारी लुक एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कार्यान्वयन में सिंगापुर एक आवश्यक सहयोगी है। इस नीति के क्रियान्वयन में सिंगापुर ने जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उसका मुझे पूरा ज्ञान है। मैं सिंगापुर के साथ एक बड़े स्तर पर काम करने को तत्पर हूँ।

द्विपक्षीय दायरे से परे, तीसरे देशों के साथ, सहयोग के माध्यम से, काम करने के महत्वपूर्ण अवसर भी हैं। इसका एक उदाहरण आसियान आर्थिक समुदाय है जो अस्तित्व में आ चुका है। यह 600 मिलियन लोगों के लिए 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार का निर्माण कर रहा है। यह आगे हमारे व्यापार को साझे तौर पर व्यापक दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अवसर तलाशने में मदद करेगा।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी), जिसमें आसियान और उसके छह वार्ता भागीदार हैं, में भी हमारी कंपनियों के लिए एक और संभावित अवसर है। अभी हाल में नई दिल्ली में आयोजित भारत अफ्रीका फोरम समिट में, सिंगापुर को



खास मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया था। यह भारत-सिंगापुर एकजुटता के एक और आयाम की मान्यता है। हम अफ्रीकी देशों में संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं।

देवियो और सज्जनों!

भारत आर्थिक और सामाजिक पैमाने पर परिवर्तन की ऐसी गति के दौर से गुजर रहा है जो इतिहास में बेजोड़ है। हमारी विकास दर पिछले साल 7.3 प्रतिशत थी। विश्व बैंक ने इस साल और बेहतर विकास दर का अनुमान लगाया है। बड़े देशों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम भी इस विकास का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमने वित्तीय समावेशन पर प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की है। हमारी रणनीति है:

- अर्थव्यवस्था को उत्साहित करना
- लोगों को सशक्त बनाना
- गैर वित्त पोषित को वित्त पोषित बनाना
- गरीब को सुरक्षित बनाना
- और सभी के आय स्तर में वृद्धि करना।

**धन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।** इस उद्देश्य के साथ, हमने 190 मिलियन नए बैंक खाते खोले हैं। उनके माध्यम से, हम गरीबों को लाभ का सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह लक्ष्यीकरण भी सरकारी खर्च में अनुशासन ला रहा है। हमने नई बीमा और पेंशन योजनाओं की शुरुआत की है। 'मुद्रा' नामक एक नए बैंक के माध्यम से, हम छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों का वित्त पोषण कर रहे हैं। हमने सभी के लिए आवास, पानी, बिजली और स्वच्छता प्रदान करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्रकार, भारत अब आर्थिक क्रांति के अगले दौर में है। हमारे बदलते प्रतिमानों ने वैश्विक निवेशक समुदाय के लिए नए अवसर पैदा किये हैं।

इन अवसरों में 100 स्मार्ट शहरों की स्थापना के लिए 50 लाख सस्ते घरों के निर्माण से लेकर; रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण और नये रेल गलियारों की स्थापना के लिए रेलवे स्टेशनों का फिर से विकास; पारेषण और वितरण नेटवर्क के साथ 175 गीगावॉट का अक्षय ऊर्जा का उत्पादन। राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों और मेट्रो रेल नेटवर्क का निर्माण।

माल के उत्पादन और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इस तरह की एक विशाल संभावना की क्षमता किसी भी अन्य देश में उपलब्ध नहीं होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी पर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर ग्राहक आधार की पेशकश कर सकती है।

हम अपनी नीतियों और लोगों के माध्यम से इस विकास की क्षमता का दोहन करने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल भारत और कौशल भारत जैसे अभियान इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। हमने हाल के दिनों में नए व्यवसायों की संख्या में भारी वृद्धि देखी है। इनमें से कुछ की स्थापना तो वैश्विक खिलाड़ियों को चुनौती देने वाली है। पूरी तरह से इस ऊर्जा का दोहन करने के लिए, हमने हाल ही में स्टार्ट अप इंडिया अभियान शुरू किया है। स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया।

मित्रों, पिछले कुछ महीनों में विदेशी निवेशकों की भारत में रुचि बहुत तेजी से बढ़ी है। हालांकि, कुछ विनियामक और कराधान मुद्दे उनकी भावनाओं पर प्रतिकूल असर डाल रहे थे। हमने लंबे समय से विचाराधीन चिंताओं को दूर करने के लिए बहुत निर्णायक कदम उठाए हैं।

आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ -

- हमने सुरक्षा और पर्यावरण मंजूरी सहित नियामक मंजूरी में तेजी लाई है;
- हमने लाइसेंस राज को काफी उदार बनाया है;
- हमने रक्षा औद्योगिक लाइसेंस की वैधता अवधि तीन साल से बढ़ाकर अठारह साल कर दी है;
- हमने करीब 60 प्रतिशत रक्षा मदों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। निर्यात के लिए अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र जैसे प्रतिबंधों को उदार बनाया है।
- हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम पूर्वव्यापी कराधान का सहारा नहीं लेंगे।
- और हमने इस स्थिति का कई तरीकों से प्रदर्शन किया है।

- हमने विदेशी एवं अन्य निवेशकों के लिए कम्पोजिट सेक्टर कैप की अवधारणा प्रस्तुत की है।
- हमने वैकल्पिक निवेश कोष के लिए नियमों को अधिसूचित किया है।
- हमने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के लिए पूंजी लाभ कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया है।
- हमने स्थायी प्रतिष्ठान के मानदंडों को संशोधित किया है;
- हमने जनरल एंटी-अवॉयडेंस रूल्स के कार्यान्वयन को दो साल के लिए स्थगित करने का फैसला किया है।
- हमने संसद में जीएसटी विधेयक को पेश किया है, हमें उम्मीद है कि 2016 में यह पारित हो जाएगा।
- एक नया दिवालियापन संहिता और नई आईपीआर नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है। कंपनी कानून न्यायाधिकरण का जल्द ही गठन किया जाएगा।
- कोयला, स्पेक्ट्रम, और लौह अयस्क जैसे प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन एवं नीलामी की हमारी पारदर्शी प्रणाली अब स्थिर है।

ये तो कुछ उदाहरण भर हैं। हम अपनी टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी एवं उम्मीदों के मुताबिक बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम इसके लिए भी उत्सुक हैं कि असली निवेशक और ईमानदार करदाता जल्द मिलें और टैक्स के मामलों में स्पष्ट फैसला लें। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमने पहले ही काफी सुधार किए हैं।

#### हमारी पहल का परिणाम:

- विदेशी निवेश को लेकर भावनाएं अब प्रतिबद्धता में बदलने लगी हैं।
- इस अवधि में पिछले साल की तुलना में इस साल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़कर 40% हो गया है।
- धारणाएं सकारात्मक परिणाम में बदल रही हैं।
- विश्व बैंक के मुताबिक कारोबार को सरल बनाने के मामले में हम 12 पायदान ऊपर चढ़ गए हैं।
- 32 फीसदी स्प्रिंट के साथ ब्रांड वैल्यू के मामले में भारत दुनिया का 7वां सबसे तरजीही देश बन गया है।
- तमाम एजेंसियों एवं संस्थानों ने भारत को सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में लगातार नामित किया है।
- साथ ही निवेश आकर्षित करने के मामले में भारत की यूएनसीटीएडी रैंकिंग सुधार हुआ है। हम पहले 15वें स्थान पर थे। लेकिन हम 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
- भारत भी विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक पर 16 स्थानों की बढ़त हासिल की है।
- रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रैंकिंग को सकारात्मक रूप से उन्नत किया है।

इस प्रकार सिर्फ 18 महीनों में हमने वैश्विक दिग्गजों की नजर में भारत की विश्वसनीयता को सफलतापूर्वक बहाल किया है। जैसे ही मेरी सरकार ने कार्यभार संभाला, हमने अन्य तमाम सुधारों के साथ एफडीआई जैसे उदारवाद को शुरू किया है। हमने रेलवे में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति दी है और रक्षा एवं बीमा क्षेत्र में इसकी सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी है। हम ऐसी नीतियों को लेकर सचेत रहे हैं। हम पूरी भावना के साथ प्रक्रियाओं की भावना को तय कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में एफडीआई के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए कदम उठाए हैं।

#### इसके साथ अंतिम सुधारों का दौर:

- भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सबसे अधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- एफडीआई के लिए कुछ नए क्षेत्रों को पूरी तरह खोल दिया गया है।
- अधिकतर क्षेत्रों में अब एफडीआई को स्वतः मंजूरी दी जा रही है।
- ग्रीनफील्ड क्षेत्रों के अलावा ब्राउनफील्ड जैसे क्षेत्र एफडीआई को स्वतः स्वीकार कर रहे हैं। इसमें सड़क, निर्माण एवं मेडिकल उपकरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- एफडीआई के लिए प्रवेश और निकासी की स्थितियों में काफी राहत दी गई है।

दोस्तों! हम डिजिटल नेटवर्क्स और स्वच्छ ऊर्जा सहित अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। मुख्य बुनियादी ढांचे के अलावा, अपने लोगों की आय तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए हम अपने सामाजिक, औद्योगिक एवं कृषि-ढांचे में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं।

हमने खर्चों पर नियंत्रण करके सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा पूंजी निवेश में भारी बढ़ोतरी की है। इसका लाभ उठाने के लिए हमने नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को विस्तार देने के लिहाज से हम टैक्स फ्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स लेकर भी आ रहे हैं। यह बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालीन स्थिति में वित्त मुहैया कराएगा। बुनियादी ढांचे के लिए हमने कुछ देशों में रुपया बांड लांच करने का फैसला भी किया है। सिंगापुर भी उसमें से एक हो सकता है। इसको लेकर हम सिंगापुर के साथ काम करने के लिए काफी उत्सुक हैं।

दोस्तों! भारत में लगभग 80 करोड़ लोग 35 साल की उम्र के नीचे हैं। उनकी आकांक्षाओं, ऊर्जा, उद्यम और कौशल का इस्तेमाल भारत के आर्थिक बदलाव के लिए किया जाएगा। लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए युवाओं को रोजगार देना तात्कालिक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, जो कई दशकों से जीडीपी के करीब 16 फीसदी पर ठहर गई है। अल्प एवं मध्यम अवधि में इस साझेदारी को करीब 25 फीसदी तक पहुंचाना होगा। इसके मद्देनजर हमने 'मेक इन इंडिया' की शुरुआत की है। हम सभी मोर्चों पर भारत को एक वैश्विक निर्माण हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए विश्वस्तरीय निर्माण क्षेत्र के साथ हम वैश्विक कौशल को विकसित कर रहे हैं। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए कारोबार को सरल बनाने हेतु उद्योगों एवं निर्माण क्षेत्र के लिए त्वरित मंजूरी दे रहे हैं। हमारी रणनीति का हॉल मार्क सुशासन है, जो भागीदारी एवं नीतियों को चलाने वाली है।

पीपीपी मॉडल के जरिये हम उन क्षेत्रों में निवेश के लिए निजी क्षेत्रों को उत्साहित कर रहे हैं, जहां अब तक सिर्फ सरकार निवेश करती रही है। हम बाजार में अनुशासन स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के साथ एकीकृत करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आगामी तीन महीने भारत में निवेश को प्रभावित करने वाले मुद्दों को सुलझा लेंगे।

दोस्तों! जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसकी दो तरह की प्रतिबद्धताएं हैं - पहली, हमारे लोग उसके केंद्र में रहने चाहिए। जो हम निवेश कर रहे हैं वह जनता के लिए होना चाहिए। हमारी विकास की तेज रफ्तार से लोगों का जीवन बदलना चाहिए।

हमारी दूसरी प्रतिबद्धता पर्यावरण, धरती और प्रकृति के प्रति है। राजनीति और अर्थव्यवस्था के विकास से जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कम नहीं होती है। उनमें भय या पक्षपात का भाव नहीं दिखना चाहिए। वे इससे अलग नहीं कर सकते हैं कि प्रकृति हमारी मां है। प्रकृति हमें जीवन देती है और हमारे जीवन को स्थायीत्व प्रदान करती है। यह हमारी आस्था का एक लेख है। मुझे भरोसा है कि वैश्विक समुदाय इसके प्रति उससे अधिक काम करेगा जितनी आवश्यकता है। हम सामान्य रूप से जितना कर सकते हैं उससे अधिक काम करेंगे।

इन दोनों प्रतिबद्धताओं के साथ आर्थिक अवसर एवं गतिविधि मुहैया कराने के लिहाज से एक लहर पैदा होती है जो कि दूसरे देशों में नहीं है। बड़े निवेशकों के लिए अवसर के द्वार खुले हुए हैं।

यहां वे बातें बता रहा हूँ जो पिछले 18 महीनों में हमने कही हैं,

- सुधारों से बड़े रास्ते खुल रहे हैं, अब उन्हें अंतिम दूरी तय करनी है;
- सुधार से व्यवस्था में बदलाव आएगा ताकि वे काम कर सकें;
- सामान्य भाषा में कहें तो उनका लक्ष्य लोगों को यह अहसास कराना है कि उनमें क्षमता है और वे अपने सपने पूरे कर सकते हैं;
- इस और सामान्य भाषा में कहें तो, उनके चेहर पर और अधिक चमक आ गई है
- इसके अलावा नई सीमाओं और वित्तीय बाजारों के लिए नींव रखी गई है।
- अर्थव्यवस्था के उड़ान भरने के रास्ते तय कर दिए गए हैं

हाल ही में आईएमएफ प्रमुख ने कहा था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत बेहतरीन जगह है। मैं इस बात का इंतजार नहीं करना चाहता कि इस बेहतरी को खुद चलकर आप तक जाना पड़े।

इसलिए, मैं यहां हूँ।

मैं यहां आपको भारत आमंत्रित करने के लिए आया हूँ।

मैं यह भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं वहां आपका ख्याल रखूंगा।

बहुत, बहुत, धन्यवाद

\*\*\*\*

आईपीएस/डीए - 5762



**पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय**

21-नवंबर-2015 18:36 IST

**आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री के उद्घाटन वक्तव्य का मूल पाठ**

महामहिम प्रधानमंत्री श्री मोहम्मद नज़ीब बिन तुन अब्दुल रज्जाक,

महामहिम,

प्रधानमंत्री महोदय इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए धन्यवाद। मैं इस उत्कृष्ट व्यवस्था और आतिथ्य के साथ-साथ आसियान-पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आपके नेतृत्व की अत्यंत सराहना करता हूँ।

एक दोहरी त्रासदी से उबरते हुए मलेशिया ने अपने को मज़बूती से वापस लौटने और संकल्प का प्रदर्शन किया है।

कुआलालंपुर एशियाई पुनरुत्थान और क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक है।

आसियान समुदाय के जन्म के एक ऐतिहासिक अवसर पर शुभकामनाएं।

हमेशा कि तरह, आसियान क्षेत्रीय सहयोग और अखण्डता के लिए प्रेरणा और नेतृत्व दोनों प्रदान कर रहा है, और भारत के दृष्टिकोण से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एकीकरण के लिए आसियान के मूल्य और नेतृत्व केन्द्र बिन्दु बने रहेंगे।

महामहिम मुझे दूसरे आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में पुनः आने पर प्रसन्नता है। मैं ने.पी.ताव में पिछले शिखर सम्मेलन में मैंने हमारे संबंधों की शक्ति और साझेदारी की क्षमता को देखा और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। भारत-आसियान सामरिक भागीदारी के प्रति आपके द्वारा जताई गयी वचनबद्धता और विश्वास।

हम बहुल वैश्विक चुनौतियों, आर्थिक अनिश्चिताओं, राजनीतिक अशान्ति और सुरक्षा खतरों के समय मिल रहे हैं।

इस कठिन घड़ी में, भारत-आसियान आशा के दो उज्ज्वल स्वरूप है।

भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख है। विकास दर 7.5 प्रतिशत को छू रही है और इसके बढ़ने की संभावना है। हमारी मुद्रास्फीति के साथ-साथ हमारे वित्तीय और विदेशी घाटे में भी कमी आई है। हमारे व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास में तेज़ी से वृद्धि हुई है।

भारत में परिवर्तन का पैमाना विशाल है इसलिए भारत में आर्थिक अवसरों का आकार भी व्यापक है।

और अब हमारे पास खुला और स्वागत करता एक माहौल भी है। यह विश्व बैंक के व्यापार को आसान बनाने की नीति में भारत की श्रेणी को तेज़ी से आगे लाने को भी प्रतिबिम्बित करता है और हम गति और साहस के साथ अपने सुधारों को जारी रखेंगे।

आसियान देशों की अर्थव्यवस्था का गतिशीलता और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना जारी है। निसंदेह हम अपने 1.9 अरब लोगों की समृद्धी को सुदृढ़ करेंगे।

महामहिम,

मुझे प्रसन्नता है कि एक स्थायी गिरावट के बाद हमारा व्यापार 2014-15 में करीब 760.5 बिलियन अमरिकी डॉलर तक बढ़ा है और इसी गति में निवेश भी आसियान आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में सबसे बड़ा निवेश सहभागी बना हुआ है। हालांकि आर्थिक साझेदारी के लिए बहुत सी क्षमताओं से लाभ लिया जाना बाकी हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे हमारी

अर्थव्यवस्थाओं ने वृद्धि की है वैसे ही हमारे व्यापार और निवेश भी व्यापक होंगे।

महामहिम,

मैं सहयोग के अपने प्रारूप की प्रगति के प्रति भी आश्वस्त हूँ। इस संदर्भ में जुलाई 2015 में सेवाओं और निवेश में समझौते हमारे व्यापार के लिए एक प्रमुख आगामी कदम है। हम एक संतुलित और महत्वकांक्षी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए वार्ता की दिशा में प्रगति के प्रति भी आशान्वित हैं जिसमें माल और सेवाओं के साथ-साथ निवेश भी शामिल होगा।

साझा समृद्धि के लिए संपर्क एक प्रमुख मार्ग है। त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना अच्छी प्रगति कर रही है और इसे 2018 तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। हम भारत और आसियान के बीच भौतिक डिजिटल संपर्क को प्रोत्साहित करने वाली परियोजनाओं के लिए 1.0 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता के लिए प्रतिबद्ध होने का भी प्रस्ताव करते हैं।

जैसा कि अतीत में हमने कंबोडिया, लाओस, म्यामांर और वियतनाम के साथ अपनी साझेदारी पर विशेष बल दिया।

क्षमता संवर्धन परियोजनाओं के क्षेत्र में हमारी साझेदारी इनमें विस्तार करेगी। इसके अलावा सीएलएमवी देशों में विनिर्माण केन्द्रों को विकसित करने के लिए हमारा एक परियोजना विकास कोष के गठन का इरादा है।

महामहिम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अभिनव हमारे सहयोग और हमारी आर्थिक साझेदारियों को समर्थन देने में एक मज़बूत स्तंभ का कार्य करते हैं। हम आसियान-भारत और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष को वर्तमान एक मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 5 मिलियन अमरीकी डॉलर करेंगे। हम न्यून लागत तकनीकियों के व्यवसायीकरण, तकनीकी हस्तांतरण और अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधा देने के लिए एक आसियान-भारत अभिनव मंच के गठन का भी इरादा रखते हैं।

वियतनाम में अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी सहयोगी परियोजना मज़बूत प्रगति की ओर है। मैं इसके शीघ्र पूर्ण होने का आपको विश्वास दिलाता हूँ। भारत ने स्वदेश में निर्मित जीपीएस सहायता प्राप्त भू संवर्धित नेविगेशन अथवा गगन सेवाओं का भी आसियान पेशकश की है, जो सूचना सुविधाओं और स्थिति निर्धारण की सहायता के मामले में उन्नत नेविगेशन तकनीक प्रदान करती है।

मैं महासागर अथवा नील अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास में सहयोग का भी प्रस्ताव रखता हूँ। यह हमारी भविष्य गत अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण संचालक के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा और स्वच्छ ऊर्जा का एक स्रोत होगा। भारत बहुत से महासागरीय देशों के साथ सहयोग संबंध स्थापित कर चुका है।

महामहिम, हमारे अनुसंधान और अभिनव प्रयासों में समान चुनौतियों, व्यापक शहरीकरण और बड़े शहरों के साथ-साथ भविष्य के कौशल, खाद्य सुरक्षा, जल और वहनीय स्वास्थ्य सुविधाओं को भी शामिल होना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चिंता का मुद्दा है। भारत ने महत्वकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा योजनाएं तैयार की हैं, जिनमें 2022 तक अक्षय ऊर्जा की 175 गीगावॉट अतिरिक्त क्षमता और 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन के माध्यम से ऊर्जा के 40 प्रतिशत भाग को प्राप्त करना शामिल हैं।

महामहिम, हमें अपने संस्थानों में अक्षय ऊर्जा के 100 से अधिक कार्यशालाओं की पेशकश करने पर भी प्रसन्नता होगी।

मैंने 122 सौर समृद्ध देशों के एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी प्रस्ताव दिया है जिसका शुभारंभ 30 नवंबर को पेरिस में मैं, और फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद करेंगे। हम इस गठबंधन में आपकी भागीदारी के प्रति भी आशान्वित हैं।

महामहिम,

मैं हमारे संबंधों के सांस्कृतिक स्तम्भों को पुनः और मज़बूत बनाने के सामूहिक प्रयासों को भी बेहद महत्व देता हूँ। आसियान-भारत सांस्कृतिक संबंधों पर नई दिल्ली में जुलाई में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हम पूर्व की ओर अपने गेटवे शिलोंग में उत्तर-पूर्वी विश्वविद्यालय में एक आसियान अध्ययन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के लिए इस वर्ष गठित हुए प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्रथम

प्राप्तकर्ता आसियान के महासचिव महामहिम ले.लूओंग.मिन्ह के लिए प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ।

भारत जल्द ही सभी दस आसियान देशों को इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सुविधा का विस्तार करेगा।

महामहिम,

हमारी भविष्य की समृद्धि हमारे क्षेत्र, महासागरों, अंतरिक्ष और साइबर विश्व की सुरक्षा और स्थिरता की नींव पर टिकी है। जनवरी 2015 में हमने प्रथम आसियान-भारत साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। जो इस क्षेत्र में सहयोग का एक महत्वपूर्ण आधार होगा।

भारत समुद्र के कानून पर 1982 संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप बे-रोक-टोक व्यापार और नेविगेशन की आज़ादी के प्रति प्रतिबद्धता में आसियान के साथ है। क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए।

भारत को आशा है कि दक्षिण चीन सागर में विवाद से जुड़े सभी पक्ष आचरण पर घोषणा के कार्यान्वयन के लिए तय दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे और इस मामले में एक आम सहमति बनाने के लिए आचार संहिता को शीघ्र अपनाने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करेंगे।

हमें समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती से मुकाबला, मानवीय और आपदा राहत में सहयोग की विशेष योजनाओं को भी विकसित करना चाहिए।

आतंकवाद हम सबके समक्ष एक प्रमुख वैश्विक चुनौती बनकर उभरा है। हम आसियान सदस्यों के साथ उत्कृष्ट द्विपक्षीय सहयोग रखते हैं और हमें यह देखना चाहिए कि हम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए अपने सहयोगों को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक कन्वेंशन को स्वीकारने का समर्थन देना चाहिए।

महामहिम, तेज़ी से बदल रही क्षेत्रीय व्यवस्थाओं और अनिश्चित समय के इस दौर में एक शान्तिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए हम क्षेत्र की रूपरेखा को निर्धारित करने के मामले में आसियान के नेतृत्व को लेकर आशान्वित हैं।

महामहिम आपकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ मैं भारत की इस प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अपने संबोधन का समापन करना चाहूंगा कि भारत इस साझेदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और इसके लिए हमने जकार्ता में आसियान हेतु एक स्थायी मिशन का शुभारंभ कर दिया है।

अपने सहयोगी एजेंडों को भविष्य में किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं इस विषय पर मैं आपके विचार सुनने के लिए तत्पर हूँ।

धन्यवाद

\*\*\*\*\*

एसएस/डीए -5671



पत्र सूचना कार्यालय  
भारत सरकार  
प्रधानमंत्री कार्यालय

06-नवंबर-2015 19:49 IST

---

दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री के उद्घाटन संबोधन का मूल पाठ

सरकार में मेरे सहयोगियों,

मित्रों और भारत और विदेश के विशिष्ट अतिथियों,

मैं छठे दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्फ्लेव को संबोधित करने के लिए आज यहां उपस्थित होकर खुश हूं। यह भारत और विदेश के अर्थशास्त्रियों, नीति-निर्माताओं, विचारकों को एक साथ लाने का अच्छा मंच है। मैं वित्त मंत्रालय को इसके आयोजन के लिए बधाई देता हूं।

यहां आपके विमर्श का विषय है जेएएम यानी जन धन योजना, आधार और मोबाइल। जेएएम की यह दृष्टि आने वाले दिनों में सरकार के कई और प्रयासों का आधार बनेगा। मेरे लिए जेएएम का मतलब है जस्ट एचिविंग मैक्सिमम।

- खर्च किए गए रुपये का अधिकतम मूल्य हासिल करना
- हमारे गरीबों का अधिकतम सशक्तिकरण
- आम जनता तक टेक्नोलॉजी की अधिकतम पहुंच

लेकिन अपनी बात रखने से पहले मैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर सरसरी नजर डालना चाहूंगा। हर बड़े संकेतक के हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 17 महीने पहले सरकार का कार्यभार संभालने के वक्त से तुलना करें तो यह काफी अच्छा प्रदर्शन है।

जीडीपी बढ़ी है और महंगाई कम हुई है

विदेशी निवेश बढ़ा है और चालू खाते का घाटा कम हुआ है

राजस्व बढ़ा है और ब्याज दरें कम हुई हैं

राजकोषीय घाटा कम हुआ है और रुपये के मूल्य में स्थिरता आई है

जाहिर है यह सब संयोगवश नहीं हुआ है। आप जानते ही हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का हाल भी अच्छा नहीं है। ऐसे में यह सफलता हमारी दूरदर्शी सोच की नतीजा है। हमने मैक्रो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो सुधार किए हैं उससे आप भलि-भाति परिचित होंगे। हमने राजकोषीय प्रबंधन की मजबूती की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। महंगाई कम करने के लिए पहली बार हमने रिजर्व बैंक के साथ मौद्रिक फ्रेमवर्क समझौता किया है। यहां तक कि राजकोषीय घाटे को घटाते हुए भी हमने काफी हद तक उत्पादक सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया है। यह दो तरीके से संभव हुआ। पहला तो यह कि हमने जीवाश्म ईंधन पर कार्बन टैक्स लगाया। हमने डीजल कीमतों से नियंत्रण हटाने का साहसिक कदम उठाया और इस तरह ऊर्जा सब्सिडी को खत्म कर दिया। कोयले पर उप कर (सेस) को बढ़ा कर 50 रुपये प्रति टन से 200 रुपये प्रति टन कर दिया गया। दुनिया भर में कार्बन टैक्स पर बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। लेकिन इस पर काम नहीं होता सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। हमने इस पर काम किया है। दूसरा, हमने प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल जैसे अभिनव तरीके से बरबाद होने वाले खर्च को बचाया है। इनमें से कुछ तरीके आपके एजेंडे में हैं, जैसे सब्सिडी के योग्य लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए आधार का इस्तेमाल। कुछ और भी सुधार हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं। लेकिन आम तौर पर लोग मानते हैं कि हमारे सुधार ज्यादा व्यापक, ज्यादा गहरे हैं।

मैं इनके बारे में विस्तार से बताऊं इससे पहले पहले मैं यहां दो मुद्दों का जिक्र करना चाहूंगा। पहला यह कि सुधार किसलिए और सुधार के लक्ष्य क्या हों, क्या यह सिर्फ जीडीपी बढ़ाने के लिए किए जाएं। या फिर ये समाज में परिवर्तन लाने के लिए हों। मेरा जवाब साफ है। वी मस्ट रीफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म। यानी हमें परिवर्तन के लिए सुधार करना होगा।

दूसरा सवाल यह है कि आखिर सुधार किसके लिए किए जाएं। सुधार किन लोगों के लिए हो। क्या हमारा उद्देश्य विशेषज्ञों के समूह को प्रभावित करने और बौद्धिक विमर्श में बढ़त बनाने के लिए हो। या फिर इसका उद्देश्य कुछ अंतरराष्ट्रीय लीगों में कुछ हासिल करने के लिए हो। इस बारे में भी मेरा जवाब स्पष्ट है। सुधार वहीं हैं जो सभी नागरिकों की मदद करें खास कर गरीबों की। गरीबों को अच्छी जिंदगी हासिल करने में मदद के लिए सुधार हों। यानी सबका साथ, सबका विकास।

संक्षेप में कहें तो सुधार अपने आप में कोई आखिरी मंजिल नहीं है बल्कि यह यहां तक पहुंचने के लंबे सफर में यह एक पड़ाव की तरह है। और यह मंजिल है भारत में परिवर्तन लाना। इसलिए मैंने कहा रीफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म। इसलिए परिवर्तन के लिए सुधार छोटी तेज दौड़ नहीं बल्कि मैराथन है।

हमने जिन सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाया है, वे कई तरह के हैं। सरल शब्दों में, मैं इन्हें वित्तीय, ढांचागत और संस्थागत सुधारों के रूप में वर्गीकृत करूंगा। मेरे लिए यहां पर इन सभी सुधारों को कवर करना संभव नहीं है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधारों का उल्लेख करूंगा।

मैं इसकी शुरुआत वित्तीय सुधारों से करता हूं। हम अक्सर ब्याज दरों और ऋण नीति की चर्चा करते हैं। ब्याज दरों में बदलाव पर कई महीनों तक बहस होती है। कई टन न्यूजप्रिंट और टेलीविजन के कई घंटे इस पर जाया हो जाते हैं। निःसंदेह ब्याज दरें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या ब्याज दरें उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो बैंकिंग प्रणाली से बाहर

हैं ? क्या ब्याज दरें उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसे किसी बैंक से कभी भी उधार या कर्ज मिलने की कोई संभावना नहीं है। यही कारण है कि विकास से जुड़े विशेषज्ञ वित्तीय समावेश की वकालत करते रहे हैं। पिछले 17 महीनों में हमारी उपलब्धि यह रही है कि इस दौरान 190 मिलियन लोगों को बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाया गया है। यह संख्या दुनिया के ज्यादातर देशों की आबादी से कहीं अधिक है। वर्तमान में ये करोड़ों लोग हमारी बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा हैं और ब्याज दर जैसे शब्द अब उनके लिए मायने रखते हैं। न केवल इन लोगों को बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाया गया है, बल्कि उन्होंने यह दर्शा दिया है कि पिरामिड की तलहटी में बड़ी ताकत है। आप मानें या ना मानें, जन धन योजना के तहत खोले गए खातों में आज कुल बैलेंस तकरीबन 26,000 करोड़ रुपये या लगभग चार अरब डॉलर है। इससे साफ जाहिर है कि वित्तीय समावेश को लेकर हमारा सुधार बड़ा बदलाव लाने में कामयाब रहा है। हालांकि, इसके बावजूद इस मौन क्रांति की तरफ शायद ही किसी का ध्यान गया हो।

एक अन्य अहम बदलाव के तहत जन धन योजना ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने और पाने के मामले में भी गरीबों को सशक्त बनाया है। हर जन धन खाताधारक एक डेबिट कार्ड पाने का हकदार है। भारतीय बैंकों को 'मोबाइल एटीएम' के संचालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मोबाइल एटीएम वह होता है, जिसमें हाथ में रखे गए एक उपकरण के जरिए नकदी की निकासी की जा सकती है और सामान्य बैंकिंग कार्य पूरे किये जा सकते हैं। यही नहीं, जन धन योजना और रुपे डेबिट कार्ड की बदौलत हमने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी सुनिश्चित कर दी है। इसमें परम्परागत रूप से महज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का वर्चस्व रहा है। यहां तक कि एक साल पहले तक बाजार में शायद ही कोई स्वदेशी कार्ड ब्रांड था। आज भारत में 36 फीसदी डेबिट कार्ड असल में रुपे कार्ड ही हैं।

वित्तीय समावेश केवल बैंक खाते खोलने अथवा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने में सक्षम बनाने तक ही सीमित नहीं है। मेरा यह पक्का विश्वास है कि भारत में जबर्दस्त उद्यमशीलता है। इसका दोहन करने की जरूरत है, ताकि भारत रोजगार चाहने वालों के बजाय रोजगार सृजित करने वालों के राष्ट्र के रूप में तब्दील हो सके। जब हमने कार्यभार संभाला था, तब हमने यह पाया था कि 58 मिलियन गैर-कॉरपोरेट उद्यम 128 मिलियन रोजगार मुहैया करा रहे थे। इनमें से 60 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में थे। इनमें से 40 फीसदी से भी ज्यादा पर पिछड़े वर्गों से ताल्लुक रखने वाले लोगों का और 15 फीसदी पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से जुड़े लोगों का स्वामित्व था। लेकिन उनके वित्त पोषण में बैंक कर्ज की हिस्सेदारी बेहद मामूली थी। इनमें से ज्यादातर को कभी भी किसी बैंक से कोई कर्ज नहीं मिला था। दूसरे शब्दों में, अर्थव्यवस्था के उस सेक्टर को सबसे कम कर्ज मिला, जो सर्वाधिक रोजगार मुहैया कराता था। जहां एक ओर जन धन योजना का उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग दायरे में लाना रहा है, वहीं दूसरे सुधार का उद्देश्य ऋण की सुविधा से वंचित लोगों को कर्ज मुहैया कराना रहा है। हम माइक्रो-इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी योजना, जो 'मुद्रा' के नाम से जानी जाती है, के तहत एक नई वित्तीय एवं नियामक व्यवस्था सृजित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक छोटे कारोबारियों को छह मिलियन से भी ज्यादा कर्ज मुहैया करा चुके हैं, जिनकी राशि कुल मिलाकर लगभग 38000 करोड़ रुपये अथवा छह अरब डॉलर बैठती है। अगर यह मान कर चला जाए कि हर कर्ज दो रोजगार सृजित करता है, तो उस हिसाब से हमने 12 मिलियन नये रोजगारों की नींव रखी है। यहां तक कि कॉरपोरेट सेक्टर में 200 हजार करोड़ रुपये का निवेश होने पर भी इतनी संख्या में रोजगार सृजित नहीं होंगे। हमने अब एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत हर बैंक की एक शाखा अर्थात् 125,000 शाखाएं अपना व्यवसाय शुरू करने में एक दलित अथवा अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति और एक महिला की मदद की मदद करेगी। हम एक ऐसा माहौल भी बनाने में जुटे हुए हैं, जो अटल नवाचार मिशन और स्व रोजगार एवं प्रतिभा उपयोग कार्यक्रम के जरिए नवाचार एवं स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देगा।

एक अन्य वित्तीय सुधार के अंतर्गत नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से सुरक्षा सुलभ कराने का प्रावधान किया गया है। हमने बगैर सब्सिडी वाली तीन किफायती योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और पेंशन को कवर किया गया है। इनके तहत व्यापक कवरेज को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम को काफी कम रखा गया है। अब 120 मिलियन से भी ज्यादा सदस्य हो गए हैं।

इनमें से ज्यादातर सुधारों को कामयाब बनाने के लिए हमें एक सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली की जरूरत है। हमें एक ऐसी प्रणाली विरासत में मिली थी, जिसमें संभवतः भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार बैंकिंग निर्णयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में होने वाली नियुक्तियों पर हावी था। बैंकों के साथ प्रधानमंत्री की हुई अब तक की प्रथम परिचर्चा, जिसे 'ज्ञान संगम' के नाम से जाना जाता है, के बाद हमने इस तरह की प्रवृत्ति में बदलाव के लिए ठोस कदम उठाए हैं। दक्षता बढ़ाने के लिए अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं, जिनमें प्रदर्शन से संबंधित स्पष्ट उपाय और जवाबदेही से जुड़ी व्यवस्था भी शामिल है। हमने पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

लेकिन गैर-वित्तीय कदम इससे भी कहीं ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। बैंकिंग निर्णयों में हस्तक्षेप समाप्त हो गया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के तहत नियुक्तियों के लिए एक नई प्रक्रिया कायम की जा रही है। विश्वसनीय एवं सक्षम बैंकों को विभिन्न बैंकों का प्रमुख नियुक्त किया गया है। 46 साल पहले बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद पहली बार निजी क्षेत्र के प्रोफेशनलों को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया है। यह एक प्रमुख सुधार है।

अब समूचे इको-सिस्टम का फोकस गरीबी उन्मूलन पर है। संभवतः इसे 'गरीबी उन्मूलन उद्योग' कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर इरादे अच्छे हैं। पूरी तरह सोच-समझकर तैयार की गई योजनाओं और सब्सिडी की निश्चित तौर पर खास अहमियत है। लेकिन गरीबी उन्मूलन उद्योग के सशक्तिकरण के बजाय गरीबों का सशक्तिकरण कहीं ज्यादा कारगर साबित होगा। हमारे वित्तीय सुधार खुद गरीबों को गरीबी के खिलाफ जंग लड़ने की ताकत देते हैं। मैं एक घर का उदाहरण देना चाहूंगा। कुल लागत का कुछ हिस्सा इसकी नींव और बुनियादी ढांचे पर खर्च हो जाता है। इसके बाद फिक्स्चर, फिटिंग और फर्नीचर पर होने वाले खर्चों का नम्बर आता है। अगर नींव और ढांचा कमजोर होगा, तो बढिया फिटिंग अथवा आकर्षक फ्लोर टाइल्स या खूबसूरत पर्दों पर किया गया निवेश संभवतः टिकाऊ साबित नहीं होगा। अतः, वित्तीय समावेश और सामाजिक सुरक्षा के जरिए गरीबों का सशक्तिकरण कहीं ज्यादा स्थिर एवं टिकाऊ समाधान साबित होगा।

अब मैं विभिन्न क्षेत्रों में किये गये ढांचागत सुधारों का उल्लेख करता हूँ।

आजीविका मुहैया कराने के लिहाज से कृषि अब भी भारत का मुख्य आधार है। हमने अनेक सुधार लागू किये हैं। पहले उर्वरक सब्सिडी को उसी मद में देने के बजाय रसायन उत्पादन में लगाने की प्रवृत्ति देखी जाती थी। एक सरल, किंतु अत्यंत कारगर हल नीम कोटेड उर्वरक है, जो डाइवर्जन के लिहाज से अनुपयुक्त है। इससे पहले इसे छोटे स्तर पर शुरू किया गया था। हम अब यूरिया की सार्वभौमिक नीम-कोटिंग की तरफ अग्रसर हैं। इसकी बदौलत अन्यत्र दी जानी वाली कृषि सब्सिडी के करोड़ों रुपये पहले ही बचाए जा चुके हैं। यह इस बात का एक अनोखा उदाहरण है कि किस तरह साधारण सुधार भी अत्यंत कारगर साबित हो सकते हैं।

हमने राष्ट्रीय स्तर पर मृदा सेहत कार्ड लांच किया है, जिससे हर किसान को अपनी जमीन की मिट्टी की सेहत के बारे में आवश्यक जानकारी मिलती है। इससे किसान को कच्चे माल की सही मात्रा एवं उनके मिश्रण का चयन करने में मदद मिलती है। इससे कच्चे माल की बर्बादी काफी हद तक कम हो जाती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। इसके अलावा मिट्टी का संरक्षण भी होता है। अनावश्यक रासायनिक कच्चे माल का उपयोग कम किया जाना उपभोक्ताओं की सेहत के लिहाज से भी अच्छा है। यही नहीं, इससे किसानों को अपनी जमीन के लिए सर्वोत्तम फसल का चयन करने में भी मदद मिलती है। अनेक किसान इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि उनकी भूमि वास्तव में किसी दूसरी फसल के लिए कहीं ज्यादा उपयुक्त है। आर्थिक लिहाज से यह सभी के लिए फायदे की बात है। इससे लागत घटती है, पैदावार बढ़ती है, पर्यावरण बेहतर होता है और उपभोक्ताओं की सेहत का संरक्षण होता है। 140 मिलियन मृदा सेहत कार्ड जारी किये जाएंगे, जिसके लिए 25 मिलियन से भी ज्यादा मिट्टी नमूनों के संग्रह की जरूरत पड़ेगी तकरीबन 1500 प्रयोगशालाओं के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के जरिए इन नमूनों का परीक्षण किया जाएगा। तकरीबन चार मिलियन नमूनों का संग्रह पहले ही हो चुका है। यह भी व्यापक बदलाव लाने वाला एक सुधार है।

हमने 'सब के लिए आवास' कार्यक्रम भी शुरू किया है, जो विश्वभर में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके तहत 20 मिलियन शहरी मकान और 30 मिलियन ग्रामीण मकान बनाए जाएंगे। इस तरह तकरीबन 50 मिलियन मकान बनाए जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी भारतीय बेघर न रहे। इससे मुख्यतः अकुशल, अर्धकुशल और गरीबों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। यह बहुआयामी कार्यक्रम भी असल में व्यापक बदलाव लाने वाला सुधार है।

भारत के श्रम बाजारों के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। हम पहले ही कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हैं। रोजगार बदलने के समय भविष्य निधि और अन्य लाभ पाने में असमर्थ रहने के चलते संगठित क्षेत्र के अनेकानेक कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। किसी एक नियोक्ता के तहत मिलने वाले लाभ को दूसरे नियोक्ता के यहां स्थानांतरित करना काफी कठिन होता है। हमने एक सार्वभौमिक खाता संख्या शुरू की है, जो रोजगार बदलने के वक्त भी संबंधित कर्मचारी के पास बरकरार रहेगी। इससे कर्मचारियों को नौकरी बदलने में आसानी होगी और नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों दोनों को सहूलियत होगी।

हमने इससे भी आगे बढ़कर एक कदम उठाया है। हमने असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सार्वभौमिक पहचान संख्या देकर और उनके लिए कुछ विशेष न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बनाया है। आने वाले वर्षों में भारत में रोजगारों की गुणवत्ता पर निश्चित रूप से इसका व्यापक असर देने को मिलेगा।

प्रधानमंत्री बनने से पहले मुझे अनेक आर्थिक विशेषज्ञों की ओर से भारत में आवश्यक सुधारों के बारे में अनेक सुझाव प्राप्त हुए थे। हालांकि, इनमें से किसी भी सुझाव में स्वच्छता एवं साफ-सफाई के मसले का जिक्र नहीं था। स्वास्थ्य और पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ साफ-सफाई की भी वर्षों से अनदेखी होती रही है। इसे अक्सर बजट और परियोजनाओं एवं व्यय के एक सवाल के रूप में देखा गया है। हालांकि, इसके बावजूद आप सभी इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि कमजोर साफ-सफाई और स्वच्छता का अभाव स्वास्थ्य से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। इससे हमारे अच्छे स्वास्थ्य का हर पहलू प्रभावित होता है। खासकर महिलाओं के लिए इसकी ज्यादा अहमियत है। हमारा स्वच्छ भारत अभियान न केवल स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई पर असर डालेगा, बल्कि महिलाओं की स्थिति और सुरक्षा में भी बेहتری सुनिश्चित करेगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि स्वच्छ भारत अभियान से अच्छे स्वास्थ्य को लेकर जन जागरूकता बढ़ेगी। अगर यह सुधार कामयाब साबित होता है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि इससे भारत में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा।

हमने परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रबंधकीय सुधार किये हैं। वैश्विक स्तर पर कुल व्यापार में कमी दर्ज होने के बावजूद वर्ष 2014-15 में हमारे प्रमुख बंदरगाहों के कुल यातायात में पांच फीसदी और परिचालन आय में 11 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय जहाजरानी निगम पिछले कई वर्षों से लगातार घाटा उठा रहा था और वर्ष 2013-14 में निगम को 275 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वर्ष 2014-15 में निगम ने 201 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। यह महज एक वर्ष में तकरीबन 500 करोड़ रुपये का व्यापक सुधार दर्शाता है। राजमार्गों से जुड़े नये कार्यों के ठेके देने की गति भी वर्ष 2012-13 के 5.2 किमी प्रति दिन और वर्ष 2013-14 के 8.7 किमी प्रति दिन से बढ़कर अब 23.4 किमी प्रति दिन हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के कामकाज में इस तरह के प्रबंधकीय सुधारों का समूची अर्थव्यवस्था में कई गुना असर देखने को मिलेगा।

एक अन्य उपाय हमने 'मृत पैसे' की पहचान करने और उसके उत्पादक उपयोग के रूप में किया है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण सोना है। भारत सोने के प्रति देशवासियों के सांस्कृतिक लगाव के लिए जाना जाता है। अर्थशास्त्रियों के रूप में आप यह संभवतः भली-भांति समझ रहे होंगे कि इस तथाकथित सांस्कृतिक लगाव का एक मजबूत आर्थिक लॉजिक है। भारत में आमतौर पर उच्च महंगाई देखी जाती रही है। महंगाई की मार से बचाने में सोने को काफी सहायक माना जाता रहा है और इसमें परिवर्तनीय ऊंची कीमत भी निहित रहती है। इसकी परिवर्तनीयता एवं उपयोगिता भी महिलाओं के सशक्तिकरण का एक स्रोत है, जो परम्परागत रूप से गहनों की मुख्य मालकिन होती हैं। हालांकि, यह सूक्ष्म आर्थिक गुण

एक बड़े आर्थिक अवगुण में तब्दील हो सकता है। यहां पर आशय भारी-भरकम सोना आयात से है। हमने हाल ही में स्वर्ण संबंधी अनेक योजनाएँ शुरू की हैं। इससे सोने को वास्तव में अपने पास रखे बगैर ही देशवासियों को स्वर्ण के महगाई संबंधी संरक्षण के साथ-साथ सामान्य ब्याज भी मिलेगा। यदि यह योजना अपने उद्देश्य में सफल होती है, तो इससे आयात को कम करने के साथ-साथ आम जनता की तर्कसंगत अपेक्षाओं को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। निश्चित रूप से यह भी एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसमें जबर्दस्त बदलाव लाने की क्षमता है।

अब मैं संस्थागत एवं शासन संबंधी सुधारों का उल्लेख करता हूँ।

वर्षों से योजना आयोग की काफी आलोचना होती रही थी। इसे आम तौर पर एक कष्टकर केन्द्रीकृत शक्ति के रूप में देखा जाता रहा था, जो राज्यों पर केन्द्र की इच्छा को थोपती थी। यह अलग बात है कि इसके कुछ बड़े आलोचकों का अचानक ही इस संस्था के प्रति प्रशंसा बोध काफी बढ़ गया था, जबकि पहले वे इससे घृणा करते थे। सत्ता में आने के बाद हमने एक नया संस्थान बनाया, जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति के नाम से जाना जाता है। नीति का मेरा विजन योजना आयोग से काफी हटकर है। यह विचारों एवं कार्रवाई का एक सहयोगात्मक मंच है, जहां राज्य पूर्ण भागीदार हैं और जहां केन्द्र एवं राज्य सहकारी संघीयवाद की भावना से एकजुट होते हैं। संभवतः कुछ लोगों ने सोचा था कि यह महज एक नारा है। लेकिन हमारे पास इसकी रूपांतरकारी शक्ति के ठोस उदाहरण हैं। अब मैं इसकी व्याख्या करता हूँ।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यों को स्वतः हस्तांतरण के रूप में केन्द्रीय राजस्व में और ज्यादा हिस्सा दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत कुछ आंतरिक सलाह मिलने के बावजूद मैंने इस सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय लिया। इससे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन की जरूरत महसूस की जा रही है। वर्ष 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद से ही केन्द्र द्वारा एकतरफा ढंग से इस तरह के निर्णय लिये जाते रहे थे। हमने कुछ अलग हटकर काम किया। केन्द्रीय योजनाओं में हिस्सेदारी का पैटर्न तय करने का जिम्मा केन्द्रीय मंत्रियों के एक समूह के बजाय 'नीति' में मुख्यमंत्रियों के एक उप-समूह को सौंपा गया। और मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सहकारिता संघीय व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए मुख्यमंत्रियों ने सिफारिशों की एक सूची पर सर्वसम्मति से हामी भरी है। एक खास बात यह है कि इस मसले के काफी जटिल होने और विभिन्न राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखने के बावजूद इन मुख्यमंत्रियों की सर्वसम्मति संभव हो पाई। उनकी रिपोर्ट मुझे 27 अक्टूबर को प्राप्त हुई। हिस्सेदारी के पैटर्न पर मुख्य सिफारिश को उसी दिन स्वीकार कर लिया गया और लिखित निर्देश ठीक अगले दिन ही जारी कर दिए गए। कई अन्य मसलों पर भी ये मुख्यमंत्री राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में अगुवाई कर रहे हैं। संस्थान में सुधार सुनिश्चित कर हमने रिश्तों में भी बदलाव ला दिया है।

'मेक इन इंडिया' और 'व्यवसाय करने में सुगमता' को लेकर हमारे कार्य निःसंदेह जगजाहिर हैं। 'मेक इन इंडिया' पर हमारे विशेष जोर को विश्व व्यापार की धीमी वृद्धि दर के रूप में देखा जाना चाहिए। व्यापार की वृद्धि दर वर्ष 1983 से लेकर वर्ष 2008 के बीच जीडीपी वृद्धि दर से आगे निकल गई। हालांकि, उसके बाद से ही जीडीपी के मुकाबले व्यापार धीमी गति से वृद्धि दर्शा रहा है। अतः घरेलू खपत के लिए उत्पादन विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

आप सभी संभवतः इस बात से वाकिफ होंगे कि विश्व बैंक के 'ड्रुंग बिजनेस सर्वेक्षण' में भारत की रैंकिंग अब काफी सुधर गई है। लेकिन राज्यों के बीच अत्यंत स्वस्थ एवं रचनात्मक प्रतिस्पर्धा एक नई खास बात है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ शीर्ष राज्यों में झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा भी शामिल हैं। यह रचनात्मक प्रतिस्पर्धी संघीय व्यवस्था का एक नायाब उदाहरण है।

65 वर्षों से भी ज्यादा की परम्परा को तोड़ते हुए हमने यहां तक कि विदेश नीति में भी राज्यों को शामिल किया है। विदेश मंत्रालय से कहा गया है कि वह राज्यों के साथ मिलकर काम करे। जब मैं चीन के दौर पर गया था, तो 'राज्य से राज्य के बीच शिखर सम्मेलन' भी आयोजित किया गया था। राज्यों से निर्यात संवर्धन परिषदों का गठन करने को कहा गया है। राज्यों की सोच को वैश्विक बनाना भी एक और अहम सुधार है, जिसमें व्यापक बदलाव लाने की क्षमता है।

मुझे पक्का विश्वास है कि भारत की जनता बहुत ज्यादा परिपक्व है और कुर्सी पर बैठे-बैठे आलोचना करने की बजाय सार्वजनिक तौर पर बेहद उत्साहित है और विशेषज्ञ इसका श्रेय उन्हें ही देते हैं। गवर्नेस से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मसला नागरिकों और सरकार के बीच पारस्परिक विश्वास का है। हमने हस्ताक्षरों के 'प्रमाणीकरण' की अनेक जरूरतों को समाप्त करते हुए नागरिकों पर विश्वास कर इस दिशा में शुरुआत की। उदाहरण के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों के स्व-प्रमाणीकरण की इजाजत विद्यार्थियों को दे दी है। हमने ऑनलाइन बायोमीट्रिक पहचान की शुरुआत कर पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र हेतु सरकारी कार्यालय जाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अर्थशास्त्रियों का परम्परागत रूप से यह मानना रहा है कि लोग स्वहित को देखते हुए ही काम करते हैं। लेकिन भारत में स्वैच्छिक भावना की लंबी परम्परा रही है। हमने रसोई गैस सब्सिडी को स्वेच्छा से छोड़ने में जन सहयोग के लिए 'गिव-इट-अप अभियान' शुरू किया। हमने उनसे वायदा किया कि छोड़े जाने वाला हर कनेक्शन उस गरीब परिवार को दिया जाएगा, जिसके पास फिलहाल गैस की सुविधा नहीं है। इससे हमें जलावन लकड़ी का इस्तेमाल करने वाली अनेक गरीब महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी खतरे के साथ-साथ सांस की बीमारी से बचाने में मदद मिलेगी। इसे जबर्दस्त समर्थन प्राप्त हुआ। कुछ ही महीनों के भीतर 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीयों ने अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी है। इनमें से ज्यादातर अमीर परिवार नहीं हैं और वे निम्न मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। यदि इस कमरे में उपस्थित किसी भी व्यक्ति के पास सब्सिडी वाला कनेक्शन है, तो मैं उनसे सब्सिडी छोड़ने वाले लोगों में शुमार होने के लिए कहूंगा।

यह मेरे लिए एक उपलब्धि है कि जो मैं सोचता हूँ, उसे हमारे कटु आलोचक भी असहमत नहीं हो पाते हैं। यह भ्रष्टाचार के स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। पिछले कई वर्षों से अर्थशास्त्रीगण एवं अन्य विशेषज्ञ किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था की प्रगति में भ्रष्टाचार को एक प्रमुख बाधा मानते रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अनेक निर्णायक कदम

उठाए हैं। मैं पहले ही इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्या तब्दीली लाई गई है। एक अन्य प्रमुख सुधार जग जाहिर है। इस सुधार का वास्ता महत्वपूर्ण संसाधनों के आवंटन में मनमानी की समाप्ति से है। कोयला, स्पेक्ट्रम और एफएम रेडियो की नौलामी से बड़ी मात्रा में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। कोयले के मामले में मुख्य लाभार्थी भारत के कुछ निधनतम राज्य रहे हैं, जिनके पास अब विकास के लिए और ज्यादा संसाधन होंगे। कनिष्ठ स्तर के सरकारी पदों के लिए होने वाले साक्षात्कार को आमतौर पर भ्रष्टाचार के एक साधन के रूप में देखा जाता रहा है। हमने हाल ही में सरकार में कनिष्ठ पदों के लिए साक्षात्कार प्रणाली को खत्म कर दिया है। हम पारदर्शी लिखित परीक्षा के परिणामों पर भरोसा करके ही यह तय करेंगे कि किसका चयन किया जाएगा। कर चोरी और मनी लांड्रिंग के खिलाफ हमारे अभियान से सभी वाकिफ हैं। नये काला धन अधिनियम के लागू होने से पहले 6500 करोड़ रुपये का आकलन किया गया। इसके अलावा नये अधिनियम के तहत 4000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि घोषित की गई है। इस तरह विदेश से 10,500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के काले धन की पहचान और आकलन किया गया है। अगर हम ईमानदारी और पारदर्शिता में इस सुधार को बनाए रखते हैं, तो इससे बड़ा परिवर्तनकारी सुधार और कौन सा हो सकता है?

हम ईमानदार करदाताओं को बेहतर सेवा मुहैया कराने के लिए भी अनेक कदम उठा रहे हैं। अब समस्त कर रिटर्न में से 85 फीसदी रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न के बाद एक पेपर वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती थी, जिसकी प्रोसेसिंग में कई हफ्ते लग जाया करते थे। इस साल हमने आधार का इस्तेमाल करते हुए ई-वेरिफिकेशन की शुरुआत की है और चार मिलियन से भी ज्यादा करदाताओं ने इस सुविधा का उपयोग किया है। उनके लिए यह समूची प्रक्रिया सरल व इलेक्ट्रॉनिक थी, जो तत्काल पूरी हो गई, क्योंकि इसके लिए किसी पेपर की जरूरत नहीं थी। इस साल 91 फीसदी इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न की प्रोसेसिंग 90 दिनों के भीतर हो गई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 46 फीसदी था। मैंने आयकर विभाग से ऐसी प्रणाली अपनाने को कहा है जिसमें न केवल रिटर्न भरने, बल्कि जांच-पड़ताल का काम भी कार्यालय जाए बगैर ही संपन्न हो जाए। सवाल-जवाब ऑनलाइन अथवा ई-मेल के जरिए किये जा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यह जानने की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसके पास क्या, कहां और कितने समय से लंबित है। इसे पांच बड़े शहरों में संचालित किया जा रहा है। मैंने यह भी निर्देश दिया है कि आयकर अधिकारियों से जुड़ी प्रदर्शन आकलन प्रणाली में फेरबदल किया जाए। आकलन में यह दर्शाया जाना चाहिए कि किसी अधिकारी के आदेश और आकलन को अपील के वक्त बरकरार रखा गया या नहीं। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और अधिकारीगण सही आदेश जारी करने के लिए प्रेरित होंगे। पूरी तरह से अमल में आने के बाद ये बदलाव जैसे कि ऑनलाइन जांच-पड़ताल और प्रदर्शन आकलन से जुड़े बदलाव आगे चलकर परिवर्तनकारी साबित हो सकते हैं।

यह एक प्रतिष्ठित सम्मेलन है। आपको अभी कई रोचक और विचारप्रेरक सत्रों में भाग लेना है। मैं आप सभी से यह अपील करता हूँ कि आप परम्परागत उपायों से कुछ अलग हटकर सोचें। हमें सुधारों के अपने विचार को कुछ मानक धारणाओं तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। सुधारों का हमारा विचार समावेशी और वैविध्यपूर्ण होना चाहिए। सुधारों का लक्ष्य गुलाबी पेपरों में बेहतर शीर्षक नहीं है, बल्कि हमारी जनता की बेहतर जिंदगी सुनिश्चित करना है। मुझे पक्का विश्वास है कि आप अपने ज्ञान की बदौलत और भी अच्छे विचार सामने रखेंगे। मैं आपकी ओर से और ज्यादा परिवर्तनकारी सुधारों को पेश किये जाने की आशा करता हूँ, जो पूरे भारत में लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। ऐसा होने पर न केवल भारत में हम, बल्कि पूरी दुनिया लाभान्वित होगी।

धन्यवाद ।

\*\*\*\*

डीएम/आरआरएस/वाईबी/एसके- 5361

